ISSN No. 2581-3528

केशव संवाद

अंक : 1 अक्टूबर–2026

RNI No. UPHIN/2000/03766

₹ : 100/-

युवा विशेषांक

युवा और उत्तर प्रदेश

नए विचार, नई ऊर्जा, नया उत्तर प्रदेश

- तकनीकी नवाचार
- MSME और युवा उद्यमी
- सुशासन से विकास
- सांस्कृतिक विरासत
- महाकुंभ 2025 युवा स्वयंसेवा
- आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश

युवा सोच, नया भारत

मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों,

प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश शुभत्व एवं मंगल के आराध्य हैं। मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, जब मैं देखता हूं कि संपूर्ण प्रदेश में, विशेषकर युवा अपने घरों में भगवान गणपति की स्थापना कर श्रद्धा के साथ उनका पूजन करते हैं। **सामाजिक एकता एवं राष्ट्र के प्रति अपने संकल्प को सुदृढ़ करने वाले महापर्व गणेश चतुर्थी की आप सभी को कोटि-कोटि मंगलकामनाएं।**

भगवान गणेश का पर्यावरण और जीवों के साथ गहरा जुड़ाव, उनकी रूप-रचना तथा जीवन-दर्शन, प्रकृति के संरक्षण और संतुलन का संदेश देता है। गज मुख जंगलों और वन्यजीवों का प्रतीक है, तो मूषक वाहन भूमि की उर्वरता और कृषि से जुड़ा है। विशाल उदर संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करने का भाव व्यक्त करता है, जबकि उनके बड़े कान हमें प्रकृति की हर पुकार को सुनने का संदेश देते हैं।

गणेश चतुर्थी पर पूजा जाने वाला 'एकविंशति पत्र' (इक्कीस प्रकार की विशेष पत्तियां) औषधीय पौधों के संरक्षण से जुड़ा है। इस प्रकार गणपति का चरित्र हमें मानव जीवन और प्रकृति के एक-दूसरे का पूरक होने का संदेश देता है। इसी विराटता को **लोकमान्य तिलक ने आस्था से एकता, एकता से जनशक्ति और जनशक्ति से राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देने वाला महापर्व बना दिया।**

गणेशोत्सव के ज्ञान, विवेक और कर्म की भावना सृजन तथा निर्माण के स्वरूप भगवान विश्वकर्मा के पूजन में दिखाई देती हैं। **17 सितंबर को जब सृष्टि के प्रथम अभियंता भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया जाएगा,** तब कौशल एवं तकनीक के संगम से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प और पुष्ट होगा।

एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र और आधुनिक आधारभूत संरचनाएं नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का प्रमाण हैं। किसी प्रदेश का वास्तविक निर्माण केवल बड़े ढांचों से नहीं, वहां के लोगों के हुनर, विचारों की शक्ति और उद्यमिता के साहस से होता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद-एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जैसी पहलों के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों, युवाओं और उद्यमियों को कौशल, उपकरण, वित्त और बाजार से जोड़ने का कार्य कर रही है।

मैं आप सभी से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि 'वोकल फॉर लोकल' को केवल विचार नहीं, बल्कि व्यवहार का अंग बनाएं। स्थानीय उत्पादों का सम्मान बढ़ेगा, तो कारीगरों के हाथों को काम, युवाओं को रोजगार के अवसर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और हुनर तथा स्थानीय सामर्थ्य पर विश्वास से ही आत्मनिर्भर एवं विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।

आपका

योगी आदित्यनाथ

गणपति बप्पा मोरया

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

उत्तर प्रदेश : युवा विशेषांक

केशव संवाद

RNI No. UPHIN/2000/03766

ISSN No. 2581-3528

अक्टूबर, 2026

वर्ष : 26 अंक : 10

सलाहकार समिति

उदयभान सिंह, रविन्द्र सिंह चौहान

रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुकेश कुमार

संपादक

कृपाशंकर

कार्यकारी संपादक

प्रोफेसर (डॉ.) नीलम कुमारी

प्रबंध निदेशक

डॉ. अनिल कुमार निगम

प्रबंध संपादक

पंकज राणा

अंक संपादक

डॉ. दीपा रानी

सह अंक संपादक

मानस वर्मा

पृष्ठ संयोजन

वीरेंद्र पोखरियाल

संपादकीय कार्यालय

प्रेरणा शोध संस्थान न्यास

सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा -201309

फोन न. 0120 4565851

ईमेल : keshavsamvad@gmail.com

वेबसाइट : www.prernasamvad.in

स्वामी पंकज कुमार की ओर से मुद्रक/प्रकाशक रमन चावला द्वारा चन्द्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा.लि नोएडा से मुद्रित तथा केशव भवन 105 आर्यनगर सूरजकुंड रोड मेरठ से प्रकाशित

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा मेरठ की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा। संपादक

युवा आकांक्षाओं को धरती पर उतारा	-सुभाष चन्द्र सिंह	05
युवा भारत, सशक्त उत्तर प्रदेश	-डॉ. सरवन सिंह बघेल	08
भारतीय ज्ञान परंपरा का नवजागरण	-डॉ. अनिल कुमार निगम	12
जवान हौसलों ने भरी नई उड़ान	-सुभाष चन्द्र सिंह	16
स्टार्टअप से आत्मनिर्भरता तक	- मानस वर्मा	18
जब युवा कलम बने बदलाव की आवाज	-डॉ. दीपा रानी	21
युवा होनहारों ने सफलता के झंडे गाड़े	- अंजलि सिंह	24
कौशल से कॅरियर तक, आत्मनिर्भर बन रहा युवा	- रोशनी शंकर	26
अनोखी वैज्ञानिक उड़ान	- नन्द किशोर शर्मा	29
एआई ने बदला तकनीकी परिदृश्य	- डॉ. अपर्णा इड़ा श्री	32
एक क्लिक का विवेक, हजार अफवाहों पर ब्रेक	- डॉ. राजीव वर्मा	35
ओडीओपी : सफर लोकल से ग्लोबल तक	- डॉ. आभा सिंह	38
खेतों की पगडंडियों से राष्ट्रमंडल के मंच तक	- श्रेयांशी	41
युवा महिला उद्यमी किसी से पीछे नहीं	- सुनीता निगम	44
पर्यावरण संरक्षण : अभियान नहीं, जनआंदोलन	-प्रकाश श्रीवास्तव	48
सनातक सांस्कृतिक विरासत का अविरल प्रवाह	- प्रो. ओम प्रकाश सिंह	51
स्वरोजगार की नयी पटकथा	- डॉ. सुनील कुमार मिश्र	54
परम्परा और नयी सोच साथ-साथ	- आभांशु द्विवेदी	56
विरासत का गौरव, नवाचार का संकल्प	- अमित शर्मा	59
परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन	- डॉ. आनंद प्रकाश श्रीवास्तव	62
नवाचार एवं बौद्धिक संपदा में अपार संभावनाएं	- डॉ. दीपा त्यागी	65
विकसित यूपी की नई गाथा	- डॉ. अनुपमा भारद्वाज	68
सनातन संस्कार और युवा नेतृत्व	-पूनम कुमारी	71
कुटुंब का संस्कार युवा शक्ति का आधार	- डॉ. विनीत उत्पल	74
युवा शक्ति से समरस समाज की नई तस्वीर	- डॉ.रामशंकर	77
पंच परिवर्तन : समावेशी समाज की ओर	- विनीत वोहरा	80
नई शिक्षा नीति : शिक्षा का भारतीयकरण	- डॉ. अनुज कुमार	84
युवा चेतना से समर्थ भारत का निर्माण	- प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी	87

विरासत से विकास तक

उत्तर प्रदेश केवल भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य ही नहीं, बल्कि देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। भगवान राम, श्रीकृष्ण, गौतम बुद्ध, कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद और जनपक्षधर पत्रकारिता के अग्रदूत गणेश शंकर विद्यार्थी जैसी महान विभूतियों की यह धरती आज नई पीढ़ी के हाथों में है। यह पीढ़ी केवल गौरवशाली विरासत की उत्तराधिकारी ही नहीं, बल्कि नए उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की निर्माता भी है।

उत्तर प्रदेश का युवा बदलते भारत का केवल दर्शक नहीं, बल्कि उसके भविष्य की नई तस्वीर गढ़ने वाला सक्रिय भागीदार है। वह गांवों और कस्बों से निकलकर महानगरों और वैश्विक मंचों तक अपनी प्रतिभा और पहचान का परचम लहरा रहा है। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, पत्रकारिता, उद्योग, कृषि, खेल, कला, संस्कृति और सामाजिक सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में उसकी सक्रिय भागीदारी दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि युवा अब केवल अवसरों की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अपनी प्रतिभा, नवाचार और उद्यमशीलता के बल पर नए अवसरों का सृजन भी कर रहा है।

डिजिटल तकनीक ने इस परिवर्तन को नई गति दी है। डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, मोबाइल पत्रकारिता और सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति के ऐसे व्यापक मंच उपलब्ध कराए हैं, जहां प्रतिभा को भौगोलिक सीमाओं से परे पहचान मिल सकती है। उत्तर प्रदेश का युवा इस बदलाव का सक्रिय भागीदार बनकर स्थानीय मुद्दों को आवाज दे रहा है। अपने विचारों, रचनात्मकता तथा प्रतिभा को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर तक पहुंचा रहा है। इससे छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले युवाओं के लिए भी अपनी पहचान और संभावनाओं को विस्तार देने के नए रास्ते खुले हैं। शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भी युवा नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, डिजिटल उद्यमिता और उभरती तकनीकों ने उसकी कल्पना को नई उड़ान दी है। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन, डिजिटल बाजार, आधुनिक कृषि तकनीक और कृषि-आधारित उद्यम खेती को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। वहीं खेल, कला, संस्कृति और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उभरती प्रतिभाएं उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर को और अधिक सशक्त बना रही हैं।

इस परिवर्तन की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में युवा महिला शक्ति की बढ़ती भागीदारी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश की बेटियां आज शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, पत्रकारिता और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रही हैं। प्रशासनिक सेवाओं से लेकर पुलिस, स्टार्टअप, विज्ञान और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों तक उनकी बढ़ती भागीदारी समाज में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को रेखांकित करती है। किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन तभी संभव है, जब उसकी युवा महिला शक्ति को समान अवसर, सम्मान और नेतृत्व का अधिकार प्राप्त हो। वर्ष 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा। विकसित भारत 2047 का सपना आज के युवाओं के सपनों, कौशल, विचार और कर्म से ही साकार होगा। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति यदि शिक्षा में उत्कृष्ट, तकनीक में सक्षम, रोजगार और उद्यमिता में आत्मनिर्भर, विचारों में उदार तथा सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग बनती है, तो उत्तर प्रदेश भारत की विकास यात्रा का प्रमुख इंजन बनने की क्षमता रखता है। हालांकि इस यात्रा के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगारपरक कौशल, अवसरों की समान उपलब्धता, सही मार्गदर्शन जैसे मुद्दों पर निरंतर काम करने की आवश्यकता है। युवा ऊर्जा को सही दिशा, अवसर और मंच मिलना आवश्यक है। सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग, मीडिया और समाज-सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे युवाओं की प्रतिभा को अवसरों में और अवसरों को उपलब्धियों में बदलने वाला अनुकूल वातावरण तैयार करें।

उत्तर प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा यदि सही दिशा में प्रवाहित होती है, तो आने वाला समय केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए परिवर्तन का समय होगा। युवा केवल अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अपना मंच स्वयं बनाता है। यही युवा शक्ति विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है।

'केशव संवाद' का अक्टूबर माह का यह विशेषांक उत्तर प्रदेश के युवाओं के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ-साथ उनके लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर केंद्रित है। हमारा प्रयास है कि इस अंक के माध्यम से प्रदेश की युवा शक्ति की प्रतिभा, संभावनाओं, उपलब्धियों और चुनौतियों को व्यापक दृष्टि से सामने रखा जा सके। हमें विश्वास है कि यह विशेषांक पाठकों को नई दृष्टि, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा प्रदान करेगा।

इस अंक पर आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाओं और सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। जय हिंद!

युवा आकांक्षाओं को धरती पर उतारा

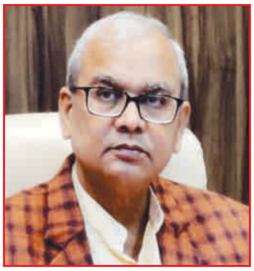

सुभाष चन्द्र सिंह
पूर्व सूचना आयुक्त, लखनऊ

युवा मुख्यमंत्री, युवा जोश, युवा जिज्ञासा और युवा महत्वाकांक्षा। इन सबका बेहतरीन समन्वय और साकार रूप देखना हो तो आप उत्तर प्रदेश आइये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में जब सरकार का नेतृत्व संभाला था तभी से प्रदेश के युवाओं के लिए रचनात्मक, समावेशी और नवाचार युक्त योजनाओं को क्रमशः धरती पर उतारा गया यानी उन्हें मूर्त रूप दिया जाने लगा। उत्तर प्रदेश पर आधारित युवा विशेषांक में योगी सरकार की युवा आधारित पहल और नवाचारों पर बहुत सारे लेखों में विविध योजनाओं का प्रायः जिक्र है। इस लेख में जितनी भी योजनाएं हैं उनको एकीकृत कर दिया जा रहा है। ये योजनाएं मुख्य रूप से स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली हैं।

एक-उत्तर प्रदेश उद्यमी विकास अभियान (CMYUVA) को जोर-शोर से शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने वाला बनाना है। जो महत्वाकांक्षी और श्रमशील युवा अपना काम-धाम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए हर साल एक लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त और गारंटी रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगले दस वर्षों में दस लाख युवाओं को इस योजना से अच्छारित करने का लक्ष्य है। यह योजना काफी समय से चल रही है। योजना में लागत का दस प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) की व्यवस्था है। यानि एक लाख रुपये ऋण पर 10 हजार का अनुदान और 5 लाख रुपये पर 50 हजार का अनुदान दिया जाता है। इसका लक्ष्य हर वर्ष एक लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और जहां तक संभव हो सके अन्य काबिल युवाओं को रोजगार या नौकरी देना है। न्यूनतम शिक्षा 8वीं कक्षा पास रखी गई है इसके लिए जरूरी है कि संबंधित युवा के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र हो।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और युवा रोजगार योजना से प्रदेश के करीब डेढ लाख युवा लाभान्वित हो चुके हैं जिनको नया स्वरोजगार या व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय मदद और ब्याज मुक्त कर्ज दिया गया है। इस योजना से ऐसे युवा लाभान्वित हुए हैं जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य है और जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।

दो-स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 25 दिसम्बर 2021 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुरू किया गया। पात्र युवा चाहे महिला हो या पुरुष, इन सभी को निःशुल्क टैबलेट/स्मार्ट फोन दिए जाने का प्रावधान है। स्नातक, स्नात्कोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा (डिप्लोमा), आईटीआई, राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों में अध्ययनरत चिकित्सा शिक्षा के छात्र और निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों में चिकित्सा शिक्षा के छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को तकनीक के माध्यम से शिक्षा में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना है। इसका लक्ष्य पहले चरण

में एक करोड़ विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट/स्मार्ट फोन देने का है। इस योजना में बाहरी राज्यों के वे विद्यार्थी भी पात्र हैं जो राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जो प्रदेश के बाहर किसी संस्थान में पढ़ते हैं वो भी इसके पात्र हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 60 लाख से अधिक विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट/स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि दिसम्बर माह तक शिक्षित नौजवानों को 25 लाख टैबलेट/स्मार्ट फोन दिए जाएंगे।

तीन- युवा रोजगार योजना के तहत उद्योग या विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए 25 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक बैंक ऋण दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट लागत का 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान (सब्सिडी) के रूप में दिया जाता है। इसमें आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है और उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल पास रखी गई है। इसमें आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, उसे किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, साथ ही राज्य सरकारा की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया हो।

चार- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के तहत राज्य के युवाओं को निःशुल्क तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यह योजना 14 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए है। इसका उद्देश्य युवाओं को विभिन्न सेक्टरों में प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाया जाना है। प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क है, सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। यह प्रशिक्षण सामान्य तौर पर 3 महीने, 6 महीने और जरूरत के अनुसार एक वर्ष भी होती है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके अंतर्गत, कम्प्यूटर और डेटा एंट्री ऑपरेशन, टैली, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेट्रिकल कार्य, ऑटोमोटिव (मोटर वाहन) ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग और स्वास्थ्य सेवा (हेल्थ केयर) का प्रशिक्षण दिया जाता है।

पांच - ओडीओपी से अब तक सर्वाधिक नौ लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। योगी जी के पहले कार्यकाल में ही इस महात्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की गई थी। इसका उद्देश्य स्थानीय हुनर और पारंपरिक कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए बड़े अवसर पर पैदा करना है। योगी जी भी इस योजना के बारे में उत्साह पूर्वक बताते हैं। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के साथ इस एक जिला, एक उत्पाद योजना का जरूर जिक्र करते हैं। इन तीनों के माध्यम से वह बताते है कि किस तरह पिछली सरकारों से बेहतर उनकी सरकार काम कर रही है। अखिलेश यादव के राज में एक जिला, एक माफिया (वन डिस्ट्रिक, वन माफिया) का जिक्र करते हुए वह एक जिला, एक उत्पाद (वन डिस्ट्रिक वन प्रोडेक्ट) का जिक्र करते हैं। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के सभी 75 जिलों के पारंपरिक, देशी और विशिष्ट उत्पादों को विशेष मदद देकर उनको बढ़ावा देना है। इसके तहत सभी जिलों में जिन उत्पादों को ओडीओपी के तहत प्रोत्साहन के लिए रखा गया है। उनकी सूची लंबी है। सरकार की ओर से दावा किया गया कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नौ लाख से अधिक युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार का अवसर मिला। सरकार द्वारा करीब डेढ़ लाख कारीगरों को मुफ्त प्रशिक्षण और टूल किट दी गई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा केवल खेल खेलने अथवा कदमताल करने का स्थान नहीं है, बल्कि समाज के श्रेष्ठ नागरिकों की रक्षा का एक अनकहा वादा है। - बाला साहब देवरस

‘एक जिला, एक उत्पाद योजना’ से यूपी का कायाकल्प

क्रम	जिला	उत्पाद	क्रम	जिला	उत्पाद	क्रम	जिला	उत्पाद
1	आगरा	चमड़ा उत्पाद एवं फुटवियर	26	फर्रुखाबाद	वस्त्र छपाई एवं जरी–जरदोजी	51	महोबा	गौरा पत्थर शिल्प
2	अलीगढ	ताले एवं हार्डवेयर	27	फतेहपुर	बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन	52	मैनपुरी	तारकशी कला
3	अंबेडकर नगर	वस्त्र उत्पाद	28	फिरोजाबाद	काँच उत्पाद	53	मथुरा	सैनिटेशन उपकरण एवं ठाकुर जी की पोशाक/सजावटी उत्पाद
4	अमेठी	मूंज उत्पाद	29	गौतम बुद्ध नगर	रेडीमेड गारमेंट्स	54	मऊ	वस्त्र उत्पाद
5	अमरोहा	ढोलक एवं वाद्य यंत्र	30	गाजियाबाद	इंजीनियरिंग उत्पाद	55	मेरठ	खेल उत्पाद
6	औरैया	देशी घी/डेयरी प्रसंस्करण	31	गाजीपुर	जूट वॉल हैंगिंग	56	मिर्जापुर	कालीन एवं पीतल उद्योग
7	अयोध्या	गुड़	32	गोंडा	दाल आधारित खाद्य प्रसंस्करण	57	मुरादाबाद	धातु शिल्प
8	आजमगढ़	काली मिट्टी की पॉटरी	33	गोरखपुर	टेराकोटा	58	मुजफ्फरनगर	गुड़
9	बागपत	होम डेकोर उत्पाद	34	हमीरपुर	फुटवियर	59	पीलीभीत	बाँसुरी एवं लकड़ी के उत्पाद
10	बहराइच	गेहूँ के डंठल की हस्तशिल्प वस्तुए	35	हापुड	होम डेकोर उत्पाद	60	प्रतापगढ	आँवला उत्पाद
11	बलिया	बिंदी	36	हरदोइ	हथकरघा एवं वस्त्र	61	प्रयागराज	मूंज उत्पाद
12	बलरामपुर	दाल आधारित खाद्य प्रसंस्करण	37	हाथरस	हींग प्रसंस्करण	62	रायबरेली	लकड़ी का काम
13	बाँदा	शजर स्टोन क्राफ्ट	38	जालौन	हस्तनिर्मित कागज	63	रामपुर	जरी–पैचवर्क एवं अप्लीक वर्क
14	बाराबंकी	हथकरघा/वस्त्र उत्पाद	39	जौनपुर	ऊनी दरी	64	सहारनपुर	लकड़ी की नक्काशी
15	बरेली	जरी–जरदोजी	40	झाँसी	सॉफ्ट टॉयज	65	संभल	सींग एवं हड्डी के उत्पाद
16	बस्ती	लकड़ी का शिल्प	41	कन्नौज	इत्र एवं परफ्यूम	66	संत कबीर नगर	पीतल के बर्तन/शिल्प
17	संत रवि दास नगर	कालीन	42	कानपुर देहात	एल्युमिनियम बर्तन	67	शाहजहाँपुर	जरी–जरदोजी
18	बिजनौर	लकड़ी का शिल्प	43	कानपुर नगर	चमड़ा उत्पाद	68	शामली	आयरन फैब्रिकेशन
19	बदायूँ	जरी–जरदोजी	44	कासगंज	जरी–जरदोजी	69	श्रावस्ती	जनजातीय शिल्प
20	बुलंदशहर	सिरेमिक उत्पाद	45	कौशांबी	खाद्य प्रसंस्करण	70	सिद्धार्थनगर	काला नमक चावल
21	चंदौली	जरी–जरदोजी एवं काला चावल	46	कुशीनगर	केले के रेशे के उत्पाद	71	सीतापुर	दरी
22	चित्रकूट	लकड़ी के खिलौने	47	लखीमपुर खीरी	जनजातीय शिल्प एवं गुड	72	सोनभद्र	कालीन
23	देवरिया	सजावटी उत्पाद	48	ललितपुर	जरी–सिल्क साड़ी	73	सुल्तानपुर	मूंज उत्पाद
24	एटा	घुँघरू एवं पीतल उत्पाद	49	लखनऊ	चिकनकारी एवं जरी–जरदोजी	74	उन्नाव	जरी–जरदोजी एवं चमड़ा उत्पाद
25	इटावा	वस्त्र एवं कढ़ाई	50	महाराजगंज	फर्नीचर	75	वाराणसी	सिल्क उत्पाद/बनारसी साड़ी

स्रोत: odopup.in ONE DISTRICT ONE PRODUCT UTTAR PRADESH (संबंधित लेख पेज 38 पर भी)

युवा भारत, सशक्त उत्तर प्रदेश

तकनीक से पारदर्शिता, व्यवस्था से सुरक्षा और प्रत्येक कार्मिक के श्रम को सम्मान, यही है 'नए यूपी' की नई पहचान

डॉ. सरवन सिंह बघेल
लेखक एवं पत्रकार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के किसी भी कस्बे में चले जाइए, शाम के वक्त चौराहे पर खड़े लड़कों की बातचीत सुन लीजिए। वहाँ फॉर्म की तारीखें हैं, रिजल्ट का इंतजार है, कोचिंग की फीस है, और कहीं भीतर एक सवाल है जो हर पीढ़ी पूछती आई है कि मेरा नंबर कब आएगा? यह सवाल छोटा नहीं है। भारत के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, और इस आबादी की सबसे बड़ी माँग पैसा नहीं, भरोसा है।

दिलचस्प बात यह है कि इस भरोसे को गढ़ने की कोशिश आज तीन जगहों से एक साथ हो रही है। संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी युवाओं से सीधे बैठकर बात कर रहे हैं। लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सपना आप लाइए, संसाधन हम देंगे। और लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति-पत्र बाँटते हुए तारीख नोट करा रहे हैं। ये तीनों अलग-अलग स्वर हैं, पर सुर एक है। यही सुर इस लेख का विषय है।

उत्तर प्रदेश : जब भर्ती का मतलब भर्ती हो गया : बहुत पुरानी बात नहीं है जब उत्तर प्रदेश में परीक्षा देना और नौकरी पाना दो बिल्कुल अलग घटनाएँ मानी जाती थीं। बीच में पेपर लीक होता था, रिजल्ट अटकता था, मामला अदालत जाता था और तब तक अभ्यर्थी की उम्र निकल जाती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में इसी पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि गलती युवाओं की नहीं थी, आयोगों में बैठे लोगों की थी।

आज तस्वीर दूसरी है। साढ़े नौ वर्षों में 9.30 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, और वह भी बिना किसी सिफारिश के। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हजारों युवाओं को नियुक्ति-पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री जी ने अगली घोषणा भी कर दी कृ आने वाले 6 महीनों में डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार, हर सप्ताह चरणबद्ध भर्तियों के साथ। किसी भी सरकार के लिए यह आसान वादा नहीं होता, क्योंकि इसमें तारीख भी दर्ज हो जाती है और जवाबदेही भी।

इस बदलाव के पीछे योजनाओं की एक पूरी शृंखला है, जो अलग-अलग जरूरतों को छूती है कृ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और युवा स्वरोजगार योजना उन्हें, जो नौकरी माँगने के बजाय देना चाहते हैं; अभ्युदय कोचिंग योजना

उन्हें, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो करना चाहते हैं पर फीस नहीं जुटा पाते; ओडीओपी और इन्वेस्ट यूपी उन्हें, जो अपने ही जिले में कुछ खड़ा करना चाहते हैं; खेलो इंडिया और मिशन शक्ति उन्हें, जिनका रास्ता मैदान से या हिम्मत से होकर जाता है।

आउटसोर्स कार्मिक : वह वर्ग जिसकी चर्चा कम हुई : सरकारी व्यवस्था की एक बड़ी परत ऐसी है जिस पर आम तौर पर बहस नहीं होती आउटसोर्स कार्मिक। दफ्तर खोलने से लेकर फाइल पहुँचाने तक, अस्पताल के वार्ड से लेकर कंप्यूटर की एंट्री तक, प्रदेश की व्यवस्था इन्हीं हाथों से चलती है। पर इनकी सेवा–शर्तें अक्सर अस्पष्ट रहीं, भुगतान में देरी होती रहीं, और बीच की एजेंसियों पर सवाल उठते रहे।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। संपूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के डिजिटल एकीकरण के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का निर्माण उन्होंने अपनी सरकार में करा दिया है। अब पूरा रिकॉर्ड एक जगह डिजिटल होगा, तो बीच का अँधेरा अपने–आप कम हो जाएगा भुगतान दिखता है, नियुक्ति दिखती है, और शोषण की गुंजाइश घटती है।

सरसंघचालक मोहन भागवत जी की दृष्टि : स्वतंत्रता दिवस पर मोहन भागवत जी ने विद्यार्थियों और जेन–जी युवाओं के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने भारत की युवा आबादी को देश का सबसे बड़ा 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' बताया, पर साथ ही एक चेतावनी भी दी जो याद रखने लायक है, यदि इस पीढ़ी को सही दिशा, शिक्षा, अवसर और उत्तरदायित्व का बोध न मिले, तो यही शक्ति समाज पर बोझ भी बन सकती है। भाषाओं और परंपराओं की इस विविधता के बीच संविधान और कानून की मर्यादा बनाए रखना उन्होंने आवश्यक बताया।

एक और अवसर पर उन्होंने जेन जी के बारे में जो कहा, वह और भी उल्लेखनीय है। उन्होंने इसे देश की सबसे ईमानदार पीढ़ी कहा, जो हर बात का तार्किक उत्तर चाहती है, और स्पष्ट किया कि विरोध–प्रदर्शन करना अपने–आप में राष्ट्रविरोधी नहीं है। संघ के मंचों से यह संदेश भी बार–बार दोहराया गया है कि राष्ट्र–निर्माण किसी सरकार या संगठन का ठेका नहीं। यह तय करना हर युवा का अपना काम है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है।

प्रधानमंत्री जी का भरोसा : लाल किले से इस बार मा. प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत 2047 और 'शक्ति की सप्तधारा' की बात करते हुए एक वाक्य कहा जो पूरे भाषण का सार था कि विकसित भारत का सबसे बड़ा साधक भी युवा है और सबसे बड़ा लाभार्थी भी वही। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे सपना लेकर आगे आएँ, संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। सस्ते डेटा और स्टार्टअप की जिस लहर ने पिछले वर्षों में छोटे शहरों के लड़के–लड़कियों को आगे बढ़ाया, वह इस भरोसे का प्रमाण भी है।

मुख्यमंत्री योगी जी : वादे से क्रियान्वयन तक - उत्तर प्रदेश में मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली की एक विशेषता है कि वे संख्या और तारीख के साथ बात करते हैं। पारदर्शी भर्ती, समयबद्ध परिणाम, स्वरोजगार की योजनाएँ, कोचिंग की सहायता और अब आउटसोर्स कार्मिकों के लिए UPCOS इन सबको जोड़कर देखा जाए तो एक ऐसे प्रदेश की रूपरेखा बनती है जहाँ तकनीक पारदर्शिता लाती है, व्यवस्था सुरक्षा देती है और हर हाथ के श्रम को सम्मान मिलता है। 'उत्तर प्रदेश युवा संवाद' जैसे मंचों के माध्यम से वे स्वयं युवाओं के प्रश्नों के सामने बैठने की परंपरा भी बना रहे हैं, जो नीति और जनता के बीच की दूरी को लगातार कम करती है।

आगामी युवा नीति : संक्षेप में - प्रदेश की आगामी युवा

युवा पीढ़ी के सवाल वाजिब

इन दिनों 'जेन जी' शब्द अखबारों और चर्चाओं में बार–बार लौट रहा है। कहीं इसे बेचैनी कहा जा रहा है, कहीं गुस्सा। मुझे लगता है दोनों ही अधूरे शब्द हैं। यह वह पीढ़ी है जिसके पास सूचना पहले पहुँचती है और जो हर बात का तर्क माँगती है। ऐसी पीढ़ी को उपदेश से नहीं, उत्तर से संतुष्ट किया जा सकता है। लाल किले से 80 वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने इसी पीढ़ी को ध्यान में रखकर कई घोषणाएँ कीं एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल का प्रशिक्षण, छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग, और 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए देशव्यापी स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, जिसका लक्ष्य 2036 के ओलंपिक तक भारत को पदक–शक्ति बनाना है। इसके साथ नागरिक सुरक्षा के नए नेटवर्क में युवाओं की भागीदारी, नवाचार के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कोष, और 2030 तक 6 G तकनीक में नेतृत्व की बात भी कही गई। पर घोषणाओं से बड़ी बात एक और है। सरकार अब युवाओं को केवल लाभार्थी नहीं, नीति–निर्माण का साझीदार मानने लगी है। जनवरी में हुए 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' में 3,000 से अधिक युवाओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी प्रस्तुतियाँ रखीं। मंच पर बैठकर सुनना, बोलने से कठिन काम है और यहीं इस बदलाव का असली संकेत है।

नीति का शीर्षक ही अपनी बात कह देता है 'सशक्त युवा, समर्थ उत्तर प्रदेश'। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के माध्यम से क्रियान्वित होने वाली इस नीति में युवा की आयु–सीमा 16 से 35 वर्ष रखी गई है, जबकि राष्ट्रीय नीति में

शिक्षा : ♦ प्रतिवर्ष 1.30 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को डीबीटी से ₹1,200कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पुस्तकें। ♦ ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 1.32 लाख विद्यालयों का कायाकल्प। ♦ 746कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 87,647 बालिकाएँ नामांकित; पीएम पोषण से 1.52 करोड़ विद्यार्थी आच्छादित। ♦ 71 नए राजकीय महाविद्यालय और अनेक नए विश्वविद्यालय 'एक मंडल, एक विश्वविद्यालय' की कल्पना अब हकीकत है। ♦ शिक्षा के अधिकार के तहत 2025–26 में 1.85 लाख बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश।

यह 15 से 29 वर्ष है। यानी तीस पार करके भी संघर्ष कर रहा व्यक्ति अचानक 'युवा' की परिभाषा से बाहर नहीं होगा।

आठ कार्यक्षेत्र - शिक्षा–कौशल, रोजगार– उद्यमिता, स्वास्थ्य, नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य, खेल–फिटनेस, कला–संस्कृति, पर्यावरण सुरक्षा तथा समावेशन–समता को एक ढाँचे में पिरोती है। प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश युवा कल्याण बोर्ड (अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी या नामित प्रतिनिधि द्वारा), हर जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला युवा कल्याण समिति, और निगरानी हेतु एक स्वतंत्र विशेषज्ञ आयोग प्रस्तावित है। MYUVA, युवा स्वरोजगार योजना, अभ्युदय कोचिंग, ODOP, इन्वेस्ट यूपी, आयुष्मान भारत, मिशन शक्ति और खेलो इंडिया जैसी बिखरी योजनाओं को एक सूत्र में पिरोया गया है, तथा एसडीजी लक्ष्यों, जी–20/वाई–20 मंचों, सिंगापुर की स्किल्सफ्यूचर और जर्मनी–दक्षिण कोरिया की द्वैध–व्यावसायिक प्रणाली को मानक बनाया गया है। प्रदेश के युवाओं की अपनी सफलता–गाथाएँ भी दस्तावेज़ का हिस्सा हैं, ताकि यह केवल आदेशों का पुलिंदा न रहे। इसी नीति के जन–संवाद रूप में 'उत्तर प्रदेश युवा संवाद' की रूपरेखा तैयार

किसान और अन्य क्षेत्र : ♦ किसान सम्मान निधि से देश के 11 करोड़ से अधिक किसान जुड़े; उत्तर प्रदेश में 3.12 करोड़ किसानों को ₹ 99,032.58 करोड़ हस्तांतरित। ♦ गन्ना किसानों को ₹ 3,12,928 करोड़ से अधिक का भुगतान; कृषि जीएसडीपी ₹2.96 लाख करोड़ से बढ़कर ₹6.95 लाख करोड़। ♦ ऑपरेशन कायाकल्प से विद्यालयों की संतृप्ति36 प्रतिशत से बढ़कर 96.30 प्रतिशत 150 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट और 75 अभ्युदय विद्यालय; पीएम श्री योजना में 1,722 विद्यालय। ♦ अनुसूचित जाति–जनजाति प्रशिक्षण योजना से 54,636 और अन्य पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम से 17,848 व्यक्ति प्रशिक्षित; पीएम विश्वकर्मा योजना से 4.20 लाख से अधिक लाभार्थी। ♦ प्रदेश की जीएसडीपी ₹ 13.30लाख करोड़ से बढ़कर ₹30.25 लाख करोड़; 2025 में 1.56 करोड़ से अधिक पर्यटक आए; 10 रामसर साइट और व्यापक सौर ऊर्जा विस्तार।

गरीब कल्याण : ♦ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है; उत्तर प्रदेश में 3.63 करोड़ राशनकार्डधारक इससे जुड़े हैं। ♦ आयुष्मान भारत से देश में 45 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित; उत्तर प्रदेश में 1.31 करोड़ परिवार और 9 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य कवर। ♦ स्वनिधि योजना से प्रदेश के 15.31 लाख से अधिक रेहड़ी–पटरी व्यवसायियों को सहारा मिला। ♦ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर मॉडल बना।

है। पहले लखनऊ में प्रदेश–स्तरीय आयोजन, फिर हर जनपद और विश्वविद्यालय तक विस्तार।

स्वतंत्रता दिवस 2026 पर लखनऊ में विधान भवन के प्रांगण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसी नीति की घोषणा को दोहराते हुए एक नया आयाम जोड़ा उन्होंने आज की पीढ़ी को 'जेन–जी और जेन एआई' कहकर संबोधित किया और निर्देश दिया कि नीति में डिजिटल सशक्तीकरण को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नीति बनाने से पहले 16–35 आयु वर्ग के युवाओं की वास्तविक आवश्यकताओं को समझा जाए और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो, ताकि हर पात्र युवा तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पहुँचे।

मोदी सरकार के 12 वर्ष : बीते बारह वर्षों की उपलब्धियों को गिनाना आसान है, पर हर आँकड़े के पीछे एक चेहरा है। पाँच करोड़ सैंतीस लाख आवास का मतलब है उतने ही परिवार जिनके सिर पर अब अपनी छत है। दस करोड़ तैंतीस लाख उज्ज्वला कनेक्शन का मतलब है उतनी रसोइयाँ जहाँ धुआँ कम हुआ। इसी दृष्टि से इन उपलब्धियों को देखा जाना चाहिए।

योगी सरकार के साढ़े नौ वर्ष : साढ़े नौ वर्ष किसी प्रदेश के जीवन में लंबा समय नहीं होता, पर उत्तर प्रदेश के लिए यह अवधि पहचान बदलने वाली रही। जिस राज्य का नाम कभी अव्यवस्था के साथ लिया जाता था, वहाँ आज बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत से घटकर 2.21 प्रतिशत है और स्टार्टअप इकोसिस्टम में यह देश का चौथा बड़ा राज्य है।

युवा और रोजगार : ♦ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से 1,47,312 युवाओं ने अपना उद्यम खड़ा किया, जिससे 4,51,775 से अधिक रोजगार बने। ♦ युवा स्वरोजगार योजना में 37,280 से अधिक युवा लाभान्वित, ₹ 940.86 करोड़ मार्जिन मनी और 2.98 लाख रोजगार। ♦ आईटीआई और कौशल विकास मिशन से 25.80 लाख युवा प्रशिक्षित, 10.20 लाख को रोजगार।

♦ 21 हजार से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत, जिनमें लगभग आधे महिलाओं द्वारा संचालित हैं; 8 यूनिकॉर्न। ♦ विभिन्न आयोगों और बोर्डों से 9 लाख से अधिक युवाओं का चयन। ♦ शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में 1 लाख से अधिक युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण; एआई प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति योजना शुरू। ♦ मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, राज्य खेल नीति–2023, और ओलंपिक स्वर्ण पदक पर ₹6करोड़ तक का पुरस्कार।

युवा एवं कौशल : ♦ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से देशभर में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण; उत्तर प्रदेश में 25.80 लाख प्रशिक्षित, जिनमें 10.20 लाख को रोजगार मिला। ♦ स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत 2.23 लाख स्टार्टअप पंजीकृत। ♦ स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना से 49.86 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित। ♦ पीएम विद्यालक्ष्मी योजना से उच्च शिक्षा के लिए बिना गारंटी का ऋण।

महिला, गरीब और किसान : ♦ 9.43 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से 1.06 करोड़ से अधिक महिलाएँ जुड़ीं; 18.55 लाख महिलाएँ लखपति श्रेणी तक पहुँचीं। ♦ महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017 के 13 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 36 प्रतिशत। यह शायद सबसे कम चर्चित पर सबसे गहरा बदलाव है। ♦ मिशन जीरो पावर्टी में 13.57 लाख निर्धन परिवारों को 17 योजनाओं से जोड़ा जा रहा है; नौ वर्षों में 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। ♦ सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹300 प्रतिमाह से बढ़कर ₹1, 500 प्रतिमाह; 67.50 लाख वृद्धजन, 26.81 लाख निराश्रित महिलाएँ और 11.57 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित। ♦ 2017 की ऋण माफी से 86 लाख से अधिक लघु और सीमांत किसान लाभान्वित; धान–गेहूँ खरीद में लाखों किसानों को हजारों करोड़ का भुगतान। ♦ फल–सब्जी उत्पादन में प्रदेश देश में प्रथम 400 लाख टन प्रतिवर्ष; 86,128 सोलर पंप स्थापित।

भारतीय ज्ञान परंपरा का नवजागरण

डॉ. अनिल कुमार निगम
वरिष्ठ पत्रकार

भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक शक्ति है। यदि युवा इसे आधुनिक विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता से जोड़ दें, तो यह वैश्विक नेतृत्व का आधार बन सकती है। भारत की पहचान केवल एक प्राचीन सभ्यता के रूप में नहीं है, बल्कि विश्व की सबसे समृद्ध ज्ञान परंपराओं के केंद्र के रूप में भी रही है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, आयुर्वेद, योग, गणित, खगोल विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शन, संगीत, साहित्य और लोकज्ञान जैसी विधाओं ने भारत को 'विश्वगुरु' की प्रतिष्ठा दिलाई। इस ज्ञान परंपरा का एक बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश रहा है। काशी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, सारनाथ और कुशीनगर जैसे नगर भारतीय संस्कृति और ज्ञान के जीवंत प्रतीक हैं।

आज जब भारत नई शिक्षा नीति (NEP 2020) और 'भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge Systems-IKS)' को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बना रहा है, तब यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश का युवा भारतीय ज्ञान परंपरा में रुचि रखता है? क्या वह इसका उपयोग कर रहा है? क्या वह इस क्षेत्र में नवाचार और शोध कर रहा है? उत्तर स्पष्ट रूप से हां है। हालांकि इसकी गति और स्वरूप अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न है, लेकिन युवाओं की रुचि लगातार बढ़ रही है।

भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? : भारतीय ज्ञान परंपरा केवल धार्मिक ग्रंथों या आध्यात्मिक चिंतन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक समग्र और वैज्ञानिक पद्धति है जो हजारों वर्षों के अनुभव, शोध और सामाजिक विकास पर आधारित है। इसमें वेद, उपनिषद, पुराण, योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, संस्कृत भाषा एवं साहित्य, गणित, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, कृषि विज्ञान, जल प्रबंधन, वास्तुकला, हस्तशिल्प, लोककला, संगीत, नृत्य, नाटक, नैतिक शिक्षा तथा जीवन मूल्यों जैसी विविध ज्ञान परंपराएं समाहित हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली मनुष्य, प्रकृति और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने पर बल देती है तथा सतत् विकास, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त करती है।

उत्तर प्रदेश के युवाओं में बढ़ती रुचि : पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के युवाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति रुचि उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। इसके पीछे अनेक कारण हैं–

नई शिक्षा नीति (NEP–2020) : नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान प्रणाली को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में IKS आधारित पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा अभियान : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) भारतीय ज्ञान प्रणाली पर विशेष पाठ्यक्रम, शोध और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म : यूट्यूब, पॉडकास्ट, ऑनलाइन

शोध एवं नवाचार

आईआईटी कानपुर, बीएचयू वाराणसी, लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों में भारतीय गणित, आयुर्वेद, जल प्रबंधन, पर्यावरण और पारंपरिक ज्ञान पर शोध हो रहा है।

केस स्टडी -1 : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), **वाराणसी :** बीएचयू भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ संस्कृत, आयुर्वेद, दर्शन और भारतीय संगीत के साथ–साथ आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है। आज अनेक छात्र आयुर्वेद, योग और भारतीय दर्शन पर शोध कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के युवा शोधकर्ता पारंपरिक औषधीय ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे यह सीख मिलती है कि परंपरा और आधुनिक विज्ञान एक–दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

केस स्टडी -2 : योग को करियर बनाने वाले युवा : उत्तर प्रदेश के अनेक युवा योग प्रशिक्षक के रूप में देश और विदेश में कार्य कर रहे हैं। मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और नोएडा में अनेक योग स्टूडियो और ऑनलाइन योग प्लेटफॉर्म युवाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। आज ऑनलाइन योग कक्षाओं के माध्यम से हजारों लोग भारतीय योग परंपरा से जुड़ रहे हैं। इससे भारतीय ज्ञान परंपरा रोजगार और उद्यमिता का भी आधार बन सकती है।

केस स्टडी -3 : वाराणसी के युवा बुनकर और डिजिटल मार्केटिंग : वाराणसी के युवा उद्यमियों ने बनारसी साड़ी जैसी सदियों पुरानी पारंपरिक कला को आधुनिक डिजिटल तकनीक और ई–कॉमर्स से जोड़कर उसे वैश्विक पहचान दिलाने का उल्लेखनीय कार्य किया है। आज के युवा उद्यमी अपनी वेबसाइट विकसित कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्टोर संचालित कर रहे हैं तथा ई–कॉमर्स पोर्टलों के माध्यम से अपने उत्पादों को देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप, मध्य–पूर्व और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचा रहे हैं। वे पारंपरिक बनारसी डिजाइनों को आधुनिक फैशन की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तुत कर युवा ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप बनारसी बुनाई की समृद्ध विरासत को नया बाजार मिला है, स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि हुई है और अनेक युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर सृजित हुए हैं।

केस स्टडी -4 : अयोध्या और धार्मिक पर्यटन में युवाओं की भूमिका : अयोध्या के विकास के साथ बड़ी संख्या में युवा सांस्कृतिक पर्यटन, डिजिटल गाइड सेवा, धार्मिक कंटेंट निर्माण, स्थानीय हस्तशिल्प, होम–स्टे और पर्यटन उद्यमिता से जुड़ रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति को आधुनिक डिजिटल माध्यमों से विश्व तक पहुंचा रहे हैं।

व्याख्यान, ई–पुस्तकें और सोशल मीडिया ने भारतीय ज्ञान को युवाओं तक सरल भाषा में पहुंचाया है।

योग और आयुर्वेद की वैश्विक लोकप्रियता : आज लाखों युवा योग प्रशिक्षक, आयुर्वेद विशेषज्ञ और वेलनेस उद्यमी बनने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

युवा नवाचार भी कर रहे : आज का युवा भारतीय ज्ञान परंपरा को केवल इतिहास के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि उसे आधुनिक तकनीक से जोड़ रहा है।

स्टार्टअप और उद्यमिता : लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी के अनेक युवा आयुर्वेदिक उत्पाद, प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन, ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ, योग ऐप, ध्यान (Meditation) प्लेटफॉर्म और पारंपरिक हस्तशिल्प आधारित स्टार्टअप चला रहे हैं।

डिजिटल कंटेंट क्रिएशन : डिजिटल क्रांति ने भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश के हजारों युवा यूट्यूब, पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा को आधुनिक शैली में

प्रस्तुत कर रहे हैं। वे संस्कृत भाषा सीखने और सिखाने, श्रीमद्भगवद्गीता के संदेशों को सरल भाषा में समझाने, भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत पर शोधपरक वीडियो बनाने, योग एवं ध्यान का प्रशिक्षण देने तथा वैदिक विज्ञान, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन जैसे विषयों को लोकप्रिय बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही युवा कंटेंट क्रिएटर्स भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने, युवाओं में अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक जीवनशैली, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

चुनौतियां भी कम नहीं हैं : यद्यपि उत्तर प्रदेश के युवाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है, फिर भी इसके व्यापक प्रसार और प्रभावी उपयोग के मार्ग में अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रामाणिक और शोध–आधारित स्रोतों की सीमित उपलब्धता है, जिसके कारण अनेक युवा अपूर्ण या भ्रामक जानकारी पर निर्भर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय ज्ञान परंपरा को केवल धार्मिक या

पत्रकारिता के विद्यार्थी भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक

भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक प्रचार–प्रसार में मीडिया और पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता के विद्यार्थियों और युवा मीडिया पेशेवरों के लिए यह एक नया, समसामयिक और संभावनाओं से भरपूर क्षेत्र है। वे अपनी रचनात्मकता, शोध क्षमता और डिजिटल कौशल के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुँचा सकते हैं।

युवा पत्रकार क्या कर सकते हैं? ♦ लोक संस्कृति का दस्तावेजीकरण : भारत की समृद्ध लोक संस्कृति, लोक उत्सवों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत पर डॉक्यूमेंट्री, फीचर और डिजिटल स्टोरी तैयार कर सकते हैं।

विलुप्त होती लोककलाओं को नई पहचान : लुप्तप्राय लोककलाओं, हस्तशिल्प, लोकनाट्य, लोकसंगीत और पारंपरिक कलाकारों पर शोधपरक रिपोर्टिंग कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान कर सकते हैं।

पारंपरिक ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण : योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक कृषि, जल संरक्षण, वास्तु, पर्यावरण संरक्षण और अन्य भारतीय ज्ञान परंपराओं के वैज्ञानिक एवं शोध–आधारित पक्ष को तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

भारतीय भाषाओं और संस्कृति का डिजिटल प्रचार : हिंदी, संस्कृत एवं क्षेत्रीय भाषाओं में पॉडकास्ट, ब्लॉग, वीडियो, वेब स्टोरी, सोशल मीडिया कंटेंट और डिजिटल आर्काइव तैयार कर भारतीय ज्ञान को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं।

फैक्ट-चेकिंग और मिथकों का सत्यापन : भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े भ्रामक तथ्यों, फेक हिस्ट्री और सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले मिथकों की तथ्यपरक जांच (Fact-checking) कर समाज को सही जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।

डिजिटल स्टोरीटेलिंग और डेटा पत्रकारिता : इन्फोग्राफिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, इंटरैक्टिव मैप, पॉडकास्ट और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को युवाओं के लिए अधिक रोचक और सुलभ बना सकते हैं।

स्थानीय नायकों और अनसुनी कहानियों को मंच : गुरुकुलों, पारंपरिक वैद्यों, लोक कलाकारों, शिल्पकारों और ग्रामीण नवाचारकर्ताओं की प्रेरक कहानियों को मुख्यधारा की मीडिया में स्थान दिला सकते हैं।

भारतीय ज्ञान आधारित स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा : योग, आयुर्वेद, जैविक खेती, पारंपरिक हस्तशिल्प, सांस्कृतिक पर्यटन और भारतीय भाषाओं से जुड़े स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियां प्रकाशित कर युवा उद्यमियों को प्रेरित कर सकते हैं।

सांस्कृतिक पर्यटन का प्रभावी प्रचार : काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, सारनाथ और कुशीनगर जैसे सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्थलों पर गुणवत्तापूर्ण यात्रा–वृत्तांत और डिजिटल कंटेंट तैयार कर पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक विमर्श से जोड़ना : अंतरराष्ट्रीय मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और बहुभाषी कंटेंट के माध्यम से भारतीय ज्ञान प्रणाली को वैश्विक शोध, शिक्षा और नवाचार के विमर्श का हिस्सा बना सकते हैं।

आध्यात्मिक विषय मान लेने की प्रवृत्ति भी इसकी व्यापक स्वीकार्यता में बाधा बनती है, जबकि इसका दायरा विज्ञान, गणित, चिकित्सा, पर्यावरण, कृषि, दर्शन और जीवन प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों तक विस्तृत है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर शोध और नवाचार की संस्कृति अभी अपेक्षित स्तर तक विकसित नहीं हो पाई है। साथ ही, इस ज्ञान को रोजगार, उद्यमिता और आधुनिक उद्योगों से सीधे जोड़ने की दिशा में भी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल प्लेटफॉर्म और भारतीय ज्ञान परंपरा के बीच प्रभावी समन्वय का अभाव भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके अलावा, भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी और संस्कृत में गुणवत्तापूर्ण, अद्यतन और शोधपरक अध्ययन सामग्री की कमी के कारण अनेक विद्यार्थी इस विषय का गहन अध्ययन नहीं कर पाते।

क्या किया जाना चाहिए? : भारतीय ज्ञान परंपरा को युवाओं के जीवन, शिक्षा और करियर से प्रभावी रूप से जोड़ने के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। सबसे पहले विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के स्तर पर ऐसे व्यावहारिक एवं कौशल–आधारित पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए, जिनसे विद्यार्थी भारतीय ज्ञान प्रणाली के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन और रोजगार से जोड़कर समझ सकें।

भारतीय ज्ञान पर आधारित स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि युवा पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक और व्यवसाय के साथ जोड़कर नए अवसरों का सृजन कर सकें। साथ ही, भारतीय इतिहास, संस्कृति, लोककला और पारंपरिक विज्ञान से संबंधित गुणवत्तापूर्ण डिजिटल कंटेंट का निर्माण और प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे यह ज्ञान अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंच सके। स्थानीय इतिहास, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों पर शोध को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को विशेष पहल करनी चाहिए।

लोककलाओं, लोकसाहित्य और सांस्कृतिक विरासत का डिजिटलीकरण कर उन्हें संरक्षित करने के साथ–साथ वैश्विक मंचों तक पहुँचाना भी समय की आवश्यकता है। युवा शोधकर्ताओं को भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषयों पर कार्य करने के लिए फेलोशिप, शोध अनुदान और नवाचार प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए प्राचीन ग्रंथों का विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद, डिजिटलीकरण और सरल व्याख्या की जानी चाहिए ताकि यह ज्ञान वैश्विक स्तर पर सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त, भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आधारित नवाचार प्रतियोगिताएँ, हैकाथॉन, शोध सम्मेलन, स्टार्टअप चुनौतियां और युवा महोत्सव आयोजित किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, अनुसंधान की प्रवृत्ति और उद्यमिता का विकास हो। यदि इन प्रयासों को समन्वित रूप से लागू किया जाए, तो भारतीय ज्ञान परंपरा केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर बनकर नहीं रहेगी बल्कि ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की एक सशक्त आधारशिला सिद्ध होगी।

निष्कर्ष : उत्तर प्रदेश का युवा भारतीय ज्ञान परंपरा को केवल अतीत की धरोहर के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के रूप में देखने लगा है। योग, आयुर्वेद, भारतीय भाषाएं, लोककला, सांस्कृतिक पर्यटन, डिजिटल कंटेंट, स्टार्टअप और शोध जैसे क्षेत्रों में उसकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति, भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS), डिजिटल तकनीक और राज्य की सांस्कृतिक विरासत ने इस रुचि को नई दिशा दी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को केवल सांस्कृतिक गौरव तक सीमित न रखकर उसे रोजगार, अनुसंधान, नवाचार, मीडिया, उद्यमिता और वैश्विक संवाद से जोड़ा जाए। यदि उत्तर प्रदेश का युवा अपनी परंपरा की जड़ों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जोड़ने में सफल होता है, तो वह न केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करेगा, बल्कि भारत को पुनः ज्ञान–आधारित वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

तुम वह बदलाव करो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो।
- महात्मा गांधी

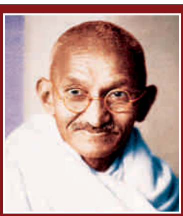

जवान हौसलों ने भरी नई उड़ान

- सुभाष चंद्र सिंह, पूर्व सूचना आयुक्त, लखनऊ

योगी सरकार आने के बाद मार्च 2017 से अब तक हजारों युवाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कहना न होगा कि इस युवा महत्वाकांक्षा को राज्य सरकार ने उड़ने के लिए नए पंख दिए। उत्तर प्रदेश के अनेकानेक युवाओं ने सरकार के प्रोत्साहन, प्रेरणा और प्रभावोत्पादक मार्गदर्शन से अपने-अपने क्षेत्र में अप्रतिम उपलब्धियां हासिल की। केशव संवाद के इस विशेषांक के अनेक लेखों में इनका जिक्र आया है। यहां हम कुछ युवाओं के कमाल के बारे में बता रहे हैं।

ताइक्वांडो में शानदार पदक

बाराणसी मंडल के अश्विनी कुमार पांडे और शिवानी पांडे ने थाईलैंड में इसी वर्ष 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित 9वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाडियों के बीच दोनों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का तिरंगा लहराया और भारतीय समाज का मान बढ़ाया। इस अतंरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में करीब 4000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अश्विनी कुमार पांडेय ने सीनियर पुरुष अंडर–54 किलोग्राम वर्ग में प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शिवानी पांडेय ने सीनियर महिला अंडर–53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। शिवानी पांडेय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में एमए (अर्थशास्त्र) की छात्रा हैं जबकि अश्विनी कुमार पांडेय बीकॉम आनर्स के छात्र हैं।

योग में कांस्य पदक

मेरठ मंडल के अनुज कुमार योगी ने अंतरराष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर उत्तर प्रदेश का नाम देश के पटल पर अंकित कर दिया। मेरठ के पांचली गांव निवासी अनुज ने यह पदक पुदुच्चेरी सरकार द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीता। राज्य के मुख्यमंत्री रंगास्वामी ने उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। यह प्रतियोगिमा इसी साल 4 जनवरी से 7 जनवरी को संपन्न हुई। योगी स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में एमपीएड के प्रथम वर्ष के छात्र हैं।

पैरालंपिक में दो पदक

आगरा मंडल के पैरालंपिक खिलाड़ी जतिन कुशवाहा ने विदेश में दो पदक जीत कर देश का नाम विश्व पटल पर अंकित किया। नवम्बर 2024 में बहरीन में संपन्न अंतरराष्ट्रीय बोशिया चैलेंजर सीरीज में दो पदक जीता। सीनियर वर्ग के एकल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक और युगल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता। जतिन कुशवाहा मूल रूप से आगरा के कमला नगर के रहने वाले हैं।

क्रिकेट के 'सम्राट'

देवी पाटन के लक्ष्यराय चंदानी युवा क्रिकेटर हैं। गोंडा जिले के निवासी 17 वर्षीय चंदानी भारत की अंडर–19 के उप कप्तान हैं। उन्होंने श्रीलंका दौरे में शानदार प्रदर्शन करते हुए टेस्ट मैच में दोहरा शतक (207) रन और नाबाद शतक बनाया। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उनकी इस उपलब्धि के लिए मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने सम्मानित किया। चंदानी का अब अंडर–19 का कप्तान बनाया गया है।

अब माउंट एवरेस्ट का सपना

गोरखपुर मंडल की पर्वतारोही और साइकिलिस्ट दिव्या सिंह ने माउंट ऐवरेस्ट के बेस कैंप में साइकिल से पहुंच कर प्रदेश और देश की महिलाओं का मान बढ़ाया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लाहोल–स्पीति स्थित 20,049 फीट ऊंचे माउंट यूनम की चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। दिव्या माउंट यूनम फतह करने वाली गोरखपुर की पहली महिला है। पर्वतारोही ग्रुप में 10 लोग शामिल थे। खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों में दिव्या सहित केवल चार पर्वतारोही माउंट यूनम की चोटी तक पहुंच पाए। उनका अगला सपना माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना है।

फूलों के कचरे से धूप अगरबत्ती

कानपुर मंडल के कानपुर निवासी अंकित अग्रवाल ने गजब का स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने तो फूलों के कचरे से धूप और अगरबत्ती बनाने वाले स्टार्टअप PHOOL की शुरूआत की। यह पहल मंदिरों के कचरे को रोकती है, गंगा नदी को गंदगी से बचाती है और महिलाओं को रोजगार देती है। सबसे पहले मंदिरों से बासी और चढ़ाए गए फूल रोज जमा किए जाते हैं, फूलों को छांटकर सुखाया जाता है और उनका पाउडर बनाते हैं तदोपरांत प्राकृतिक चीजों को मिलाकर हाथ से धूप और अगरबत्ती बनायी जाती है। इससे पर्यावरण की बड़ी रक्षा हो रही है। बिना चारकोल के 100 प्रतिशत प्राकृतिक उत्पाद बनते हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं को काम और सम्मानजनक आय प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ी बात कचरा–प्रबंधन हो रहा है। धार्मिक कचरे का सही उपयोग हो रहा है।

नारी-गरिमा को आकार

कानपुर मंडल की ही तुलसी वर्मा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का सबसे अच्छा लाभ ले रही है। तुलसी की कहानी स्वरोजगार और सरकारी सहायता का अनुपम उदाहरण है। पैंसे की कमी से जूझ रही तुलसी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण लेकर अपना प्रिंटिंग व्यवसाय शुरू किया। आज उनकी प्रिंटिंग यूनिट में पैकेजिंग और स्टीकर प्रिंटिंग का काम होता है। उन्होंने करीब एक दर्जन लोगों को नौकरी दी। कानपुर मंडल में तुलसी वर्मा की ही तरह साढ़े तीन हजार युवा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से ऋण लेकर अपना रोजगार कर रहे हैं।

स्टार्टअप से आत्मनिर्भरता

मानस वर्मा
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपनों का भूगोल बदल रहा है। अवसरों की तलाश अब केवल दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु की ओर जाने वाली राह नहीं रही। लखनऊ की प्रयोगशाला से नोएडा के स्टार्टअप हब तक, कानपुर के छात्रावास से पूर्वांचल के छोटे कस्बों तक–युवा अपने विचारों को उद्यम में बदलने का साहस कर रहे हैं। कोई तकनीक से स्थानीय समस्याएँ सुलझा रहा है, तो कोई परंपरागत व्यवसाय को नवाचार से नया स्वरूप दे रहा है। यह बदलाव केवल करियर का नहीं, युवा सोच और आर्थिक संस्कृति का परिवर्तन है। प्रश्न है, क्या उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी अब नौकरी खोजने से आगे बढ़कर रोजगार और अवसर रचने वाली पीढ़ी बन रही है?

स्टार्टअप प्रदेश बनता उत्तर प्रदेश : भारत की युवा आकांक्षाओं को स्टार्टअप संस्कृति ने नई आर्थिक शक्ति में बदलना शुरू कर दिया है। 31 मार्च 2026 तक देश में 2.23 लाख से अधिक स्टार्टअप DPIIT से मान्यता प्राप्त कर चुके थे, जिन्होंने 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए। इसी अवधि में अकेले उत्तर प्रदेश में 21,960 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और उनसे 2.11 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार दर्ज किए गए। स्टार्टअप संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश अब महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद देश में तीसरे स्थान पर है।दिल्ली और गुजरात से भी आगे निकल चुका है।

यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020 में 1,401 नए स्टार्टअप मान्यता प्राप्त हुए थे; यह संख्या 2021 में 1,981, 2022 में 2,583, 2023 में 3,432 और 2024 में 3,487 रही। यह निरंतर विस्तार बताता है कि प्रदेश में उद्यमिता अब केवल नोएडा जैसे बड़े औद्योगिक केंद्रों तक सीमित नहीं, बल्कि युवा नवाचार और रोजगार–सृजन की नई आर्थिक संस्कृति का रूप ले रही है।

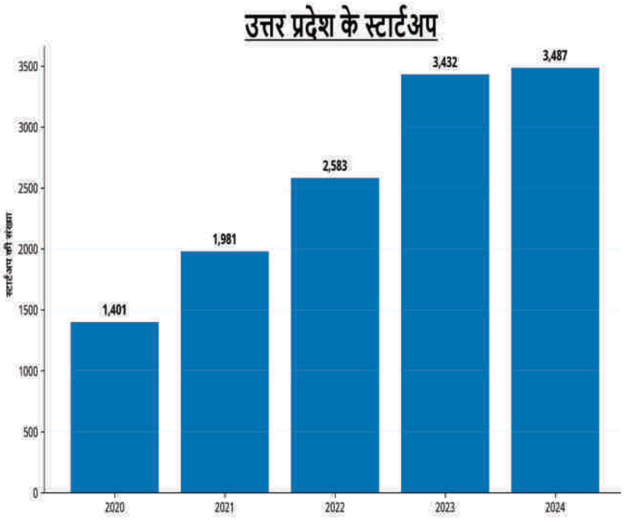

स्रोत: लोकसभा, अतारांकित प्रश्न सं. 4845, 1 अप्रैल 2025; भारत सरकार

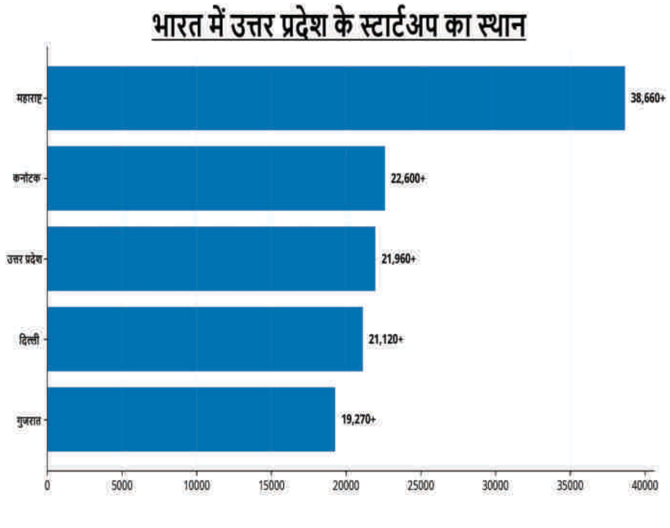

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ,17 अप्रैल 2026

नीति से नई उड़ान : उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 : युवा विचार को सफल उद्यम में बदलने के लिए उत्साह के साथ पूँजी, मार्गदर्शन और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र भी आवश्यक है। इसी दिशा में जुलाई 2026 में अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 प्रदेश की उद्यमिता यात्रा को नई गति देने का प्रयास है। नीति–तंत्र में शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए ₹17,500 प्रतिमाह निर्वाह भत्ता, प्रोटोटाइप विकास हेतु ₹5 लाख तक तथा उत्पाद को बाजार तक पहुँचाने के लिए ₹7.5 लाख तक की सीड/मार्केटिंग सहायता जैसे प्रावधान उपलब्ध हैं। महिलाओं तथा पूर्वांचल–बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों के उद्यमों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन समावेशी विकास की दिशा को रेखांकित करते हैं। विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और इनक्यूबेटरों को जोड़ता तंत्र नवाचार को कक्षा से बाजार तक पहुँचाने का माध्यम बन सकता है।

जब युवा समस्या में अवसर देखते हैं : स्टार्टअप का अर्थ केवल ऐप बनाना, निवेश जुटाना या ऊँची वैल्यूएशन हासिल करना नहीं है; उसकी वास्तविक शक्ति किसी समस्या को पहचानकर उसका टिकाऊ समाधान खोजने में है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविध प्रदेश में ऐसी संभावनाएँ हर ओर मौजूद हैं। किसान के लिए एग्रीटेक, कचरा प्रबंधन में सर्कुलर इकोनॉमी, रेहड़ी–पटरी वालों के लिए आधुनिक समाधान, स्वास्थ्य में हेल्थ–टेक, शिक्षा में एड–टेक, ODOP उत्पादों के लिए डिजिटल बाजार, पर्यटन में तकनीक और छोटे व्यवसायों के लिए AI–हर चुनौती एक नए उद्यम का आधार बन सकती है। जब युवा स्थानीय आवश्यकता को नवाचार से जोड़ता है, तो यात्रा समस्या से समाधान, समाधान से उद्यम और उद्यम से रोजगार तक पहुँचती है। यही वह बिंदु है जहाँ स्टार्टअप केवल व्यवसाय नहीं रहता, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन जाता है।

जमीन से शार्क टैंक तक : माणिक सहगल और रासा काट्र्स

कभी–कभी बड़ा नवाचार किसी बड़ी तकनीकी समस्या से नहीं, बल्कि सड़क किनारे खड़े एक छोटे विक्रेता की चुनौती को समझने से जन्म लेता है। माणिक सहगल ने भारत के असंगठित स्ट्रीट–फूड विक्रेताओं की सीमित पहुँच, पहचान और डिजिटल बाज़ार से दूरी में ऐसा ही अवसर देखा। 2022 में रासा काट्र्स ने इन छोटे उद्यमियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर ऑनलाइन ऑर्डर, बेहतर बाजार पहुँच और व्यावसायिक पहचान उपलब्ध कराने का प्रयास किया। आज इसका कार्यालय नोएडा स्थित आईआईएम लखनऊ इन्क्यूबेशन सेंटर में है।

जनवरी 2023 में रासा काट्र्स की यात्रा शार्क टैंक इंडिया Season 2 तक पहुँची। तीन वर्ष बाद, 2026 में सहगल के अनुसार प्लेटफॉर्म से लगभग 5,000 विक्रेता जुड़े हैं और यह (ONDC) तक पहुँच चुका है। यह कहानी बताती है कि स्टार्टअप की असली सफलता केवल वैल्यूएशन नहीं, बल्कि उस नवाचार में है जो छोटे उद्यमी को डिजिटल अर्थव्यवस्था का सहभागी बना सके।

सिर्फ एक कहानी नहीं : उत्तर प्रदेश के नए उद्यमी -

माणिक सहगल की कहानी अकेली नहीं है; उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और छोटे शहरों में भी समस्या को समाधान में बदलती नई उद्यमी पीढ़ी उभर रही है। लखनऊ में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्र ने 'JustBin' विकसित किया है, जो संस्थानों के 'scrap rooms' में पड़े अनुपयोगी सामान को पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण से जोड़कर कचरे को संसाधन में बदलने का प्रयास है। वहीं वाराणसी में IIT-BHU समर्थित eVerseAI कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीक के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के डेयरी क्षेत्र में छोटे किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है; इसे लगभग ₹40 लाख का संस्थागत सहयोग मिला है।

इस परिवर्तन का एक और उत्साहजनक पक्ष महिला उद्यमिता है–2026 में प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप की संख्या 9,600 से अधिक बताई गई। ये उदाहरण बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप कहानी अब केवल नोएडा–लखनऊ की नहीं; विश्वविद्यालय से गाँव तक नवाचार अपनी नई जमीन तलाश रहा है।

AI : अगली स्टार्टअप क्रांति का इंजन : AI अब भविष्य

नहीं, उद्यमिता का वर्तमान है। फरवरी 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित India AI Impact Summit 2026 ने इसी परिवर्तन को वैश्विक मंच दिया। प्रधानमंत्री ने AI को समावेशन, सशक्तीकरण और मानव–केंद्रित विकास का माध्यम बनाने पर बल दिया। सम्मेलन में लगभग 6 लाख लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी हुई, जबकि इसके घोषणापत्र को 92 देशों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिला। AI value chain में घोषित निवेश प्रतिबद्धताएँ 250 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक आँकी गईं।

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए AI कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा, पर्यटन और MSME जैसी स्थानीय समस्याओं को वैश्विक स्तर के स्टार्टअप अवसरों में बदल सकता है। प्रश्न अब यह है कि क्या अगला बड़ा AI समाधान नोएडा की किसी लैब, कानपुर के किसी छात्र या लखनऊ के किसी युवा उद्यमी से निकलेगा?

नोएडा से पूर्वांचल तक : आगे का रास्ता - उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप यात्रा की वास्तविक सफलता तब होगी, जब नवाचार की धारा नोएडा–गाजियाबाद और लखनऊ से आगे बढ़कर वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, बुंदेलखंड और छोटे जिलों तक पहुँचे। इसके लिए 'UP Startup 2030 सूत्र' स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय विचारों की प्रयोगशाला बनें, इनक्यूबेटर विचार को उद्यम में बदलें, सरकार वित्तीय सहायता और सुगम व्यवस्था दे, उद्योग बाजार व मार्गदर्शन उपलब्ध कराए और AI उत्पादकता तथा विस्तार का माध्यम बने। StartInUP के आधिकारिक नेटवर्क में प्रदेश के विभिन्न जिलों में मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर मौजूद हैं। इसलिए अगली चुनौती केवल स्टार्टअप की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि हर जिले में नवाचार को अवसर और स्थानीय प्रतिभा को उद्यम में बदलना है।

नौकरी नहीं, भविष्य गढ़ती पीढ़ी : उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसकी युवा आबादी नहीं, बल्कि उसके युवाओं की कल्पना, नवाचार और उद्यम का साहस है। जब नीति अवसर दे, शिक्षा प्रयोग को प्रोत्साहित करे और तकनीक विचारों को गति दे, तब स्टार्टअप केवल कंपनियाँ नहीं बनाते, वे आत्मनिर्भर भविष्य गढ़ते हैं। नया उत्तर प्रदेश वही होगा, जहाँ युवा अवसर खोजें नहीं, अवसर रचें।

स्रोत : DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार; लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 4845, 1 अप्रैल 2025; PIB, 17 अप्रैल 2026। Invest UP एवं StartInUP, उत्तर प्रदेश सरकार। Raasa Karts; Founder disclosures; JICA QUEST- DPIIT, भारत सरकार; StartInUP, उत्तर प्रदेश सरकार; Invest UP आदि। प्रधानमंत्री के उद्घाटन संबोधन का आधिकारिक विवरण। India AI Impact Summit के आधिकारिक परिणाम एवं आँकड़े StartInUP।

तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा। - सुभाष चन्द्र बोस

युवा कलम बने बदलाव की आवाज

डॉ. दीपा रानी
सहायक प्रोफेसर, भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) दिल्ली

कहते हैं कलम की ताकत तलवार से अधिक धारदार होती है। कलम नये विचारों को जन्म देती है। जब पत्रकार की कलम सत्य के साथ चलती है तो वह समाचार नहीं लिखती बल्कि लोकतन्त्र में सभी के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। सत्ता से सीधे सवाल कर आम जनमानस की आवाज़ को बुलन्द करती है।

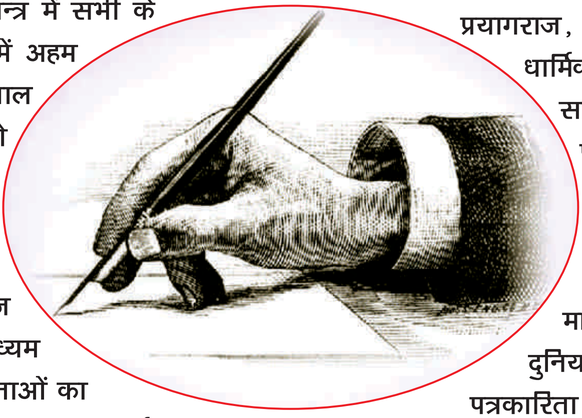

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यह सत्ता और समाज के बीच संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम है। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल घटनाओं का संकलन या प्रसारण नहीं, बल्कि जनमत का निर्माण, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण और राष्ट्र के विकास में सक्रिय सहभागिता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के युवा पत्रकारों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश की युवा ऊर्जा, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक परिवर्तन की अपार संभावनाओं का केंद्र है। यही युवा आज पत्रकारिता के माध्यम से समाज की संवेदनाओं का स्वर बनकर आम जनमानस और लोकतंत्र को सशक्त बना रहे हैं और साथ ही विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय पत्रकारिता और हिन्दी साहित्य की ऐतिहासिक भूमि का सदैव से केंद्र रहा है। यहां के जिले जैसे प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और आगरा लंबे समय से साहित्य, विचार और जनचेतना के केंद्र रहे हैं और आज भी हिन्दी पत्रकारिता में यहाँ के अधिकतर युवा प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में अप्रतिम योगदान दे रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जनजागरण और सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से प्रकाश में लाने के महत्वपूर्ण अभियानों में यहाँ की पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का कार्य किया। अनेक समाचार पत्रों और निर्भीक पत्रकारों ने अंग्रेजी शासन के दमन के विरुद्ध जनमत तैयार किया और स्वतंत्रता की भावना को जन-जन तक पहुँचाया। यह परंपरा केवल इतिहास का विषय नहीं है, बल्कि आज भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है ।

उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ के कई जिले जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, चित्रकूट और कुशीनगर, केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा के प्रतीक हैं। युवा पत्रकार इन सांस्कृतिक धरोहरों, लोक परंपराओं, लोकभाषाओं, लोक कला, योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक माध्यमों की सहायता से देश और दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ की पत्रकारिता सांस्कृतिक संरक्षण के साथ-साथ राष्ट्रीय पहचान को भी सुदृढ़ बना रही है।

उत्तर प्रदेश की पुण्य धरा ने केवल स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार और समाज सुधारक ही नहीं दिये, अपितु ऐसे निडर और ईमानदार पत्रकार भी दिए हैं, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता को सत्य, न्याय और राष्ट्रहित के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ की पत्रकारिता की परंपरा संघर्ष, साहस और सामाजिक उत्तरदायित्व की ऐसी विरासत है, जिसने भारतीय लोकतंत्र को सदैव सशक्त और समृद्ध बनाया है।

पत्रकारिता के पुरोधा कहे जाने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी, बनारसीदास चतुर्वेदी, विद्या भास्कर से लेकर एस. पी. सिंह और आज के युवा पत्रकारों तक उत्तर प्रदेश की

पत्रकारिता सत्य, साहस और सामाजिक उत्तरदायित्व की एक सतत परंपरा रही है। यही विरासत नई पीढ़ी के पत्रकारों को निष्पक्ष, संवेदनशील और उत्तरदायी पत्रकारिता की प्रेरणा देती है। आज युवा पीढ़ी में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जैसे अमन गुप्ता (उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड) जिन्होंने ने बुंदेलखंड के जल संकट, पर्यावरण, किसानों और ग्रामीण भारत की चुनौतियों पर अपनी जमीनी रिपोर्टिंग से यह सिद्ध किया है कि सच्ची पत्रकारिता वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को देश के सामने रख सके और सरकारों से न्याय दिला सके। अब तक केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के कई पत्रकारों को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। जिसमें एबीपी न्यूज में कार्य कर रही श्रीमती चित्रा त्रिपाठी जी हैं जिन्हें 2015 के जर्नलिज्म के सर्वोच्च सम्मान रामनाथ गोयनका अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया। वह मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली हैं।

इसी प्रकार वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले आशुतोष मिश्रा जो इंडिया टुडे ग्रुप में एडिटर के पद पर कार्यरत हैं उन्हें भी उनकी मणिपुर से ग्राउंड रिपोर्टिंग कवरेज के लिए पत्रकारिता के सर्वोच्च सम्मान रामनाथ गोयनका अवॉर्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है।

इक्कीसवीं सदी की पत्रकारिता ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखे हैं। आज इंटरनेट की सुलभता, डिजिटल तकनीक ने समाचारों की गति, स्वरूप और पहुँच तीनों को बदल दिया है । आज युवा पत्रकार केवल समाचार कक्ष तक सीमित नहीं है, उनके हाथ में स्मार्ट फोन और इंटरनेट है और सामने पूरा विश्व एक मंच के रूप में उपस्थित है। मोबाइल पत्रकारिता, डेटा पत्रकारिता, पॉडकास्ट, डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने युवाओं को अभिव्यक्ति के नए अवसर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अनेक युवा इन माध्यमों का उपयोग करते हुए गाँवों, कस्बों और शहरों की समस्याओं, उपलब्धियों और संभावनाओं को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना रहे हैं।

डिजिटल युग ने अनेक अवसर जरूर दिए हैं, परन्तु साथ में चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं। आज फेक न्यूज, आधी-अधूरी जानकारी, कृतिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा निर्मित भ्रामक सामग्री, ट्रोल संस्कृति और सनसनीखेज प्रस्तुति पत्रकारिता की विश्वसनीयता के सामने गंभीर प्रश्न खड़े कर रही हैं। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के युवा पत्रकारों के लिए तथ्य-जाँच (फैक्ट चेक), नैतिकता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता पहले से अधिक आवश्यक हो गई है। आज सभी पत्रकारों को फैक्ट चेकिंग टूल को गहराई से समझने और जानने की जरूरत है। पत्रकारिता की शक्ति उसकी गति में नहीं, बल्कि उसकी विश्वसनीयता में निहित होती है। पत्रकारिता का वास्तविक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है।

उत्तर प्रदेश का विशाल ग्रामीण क्षेत्र आज भी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय प्रशासन और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर युवा पत्रकार गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। वे उन सभी मुद्दों और विषयों को सामने ला रहे हैं जो प्रायः मुख्यधारा की मीडिया में अपना स्थान नहीं बना पाते। आज हमारा देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस विकसित राष्ट्रीय संकल्प की सफलता केवल आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि जागरूक, उत्तरदायी नागरिकों से सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश के युवा पत्रकार यदि शासन और समाज के बीच पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संवाद को सुदृढ़ करते हैं, तो वे इस राष्ट्रीय लक्ष्य के वास्तविक सहभागी बनेंगे।

लोकतंत्र में एक जागरूक नागरिक वही बन सकता है जिसे सही, संतुलित और तथ्यपरक जानकारी प्राप्त हो। आज का भारत केवल समस्याओं पर चर्चा नहीं, बल्कि समाधान की खोज भी चाहता है। इसी कारण समाधानपरक या रचनात्मक पत्रकारिता का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अनेक

युवा पत्रकार केवल नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, बल्कि समाज में हो रहे सकारात्मक प्रयासों को भी प्रमुखता से सामने ला रहें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, जैविक खेती, महिला उद्यमिता, जल संरक्षण, स्टार्टअप संस्कृति, युवा नवप्रवर्तन, स्थानीय कारीगरों की उपलब्धियाँ और सामाजिक सेवा के उदाहरण समाज में आशा और विश्वास का वातावरण निर्मित करते हैं। ऐसी पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को गति देती है।

आज आवश्कता है, नई शिक्षा नीति 2020, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 जैसे राष्ट्रीय अभियानों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के युवा अधिक से अधिक ख़बरों को अपने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के बीच साझा करें ताकि इसका लाभ हमारी युवा पीढ़ी को मिल सके। आज युवा पत्रकार शोध–आधारित पत्रकारिता, डेटा विश्लेषण, खोजी पत्रकारिता और रचनात्मक पत्रकारिता के माध्यम से न केवल समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि नीति–निर्माण और जनजागरण में भी सार्थक योगदान दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश का युवा आज परिवर्तन का प्रतीक है। यदि उसकी पूर्ण ऊर्जा पत्रकारिता की नैतिकता, तकनीकी दक्षता और राष्ट्रीय दृष्टि से जुड़ जाए, तो वह केवल समाचारों का सृजन नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण में सहभागी बनेगा जहाँ लोकतंत्र और अधिक मजबूत, जागरूक तथा समृद्ध होगा।

गांव की मिट्टी का अंदाज 'निराला'

वाराणसी मंडल के जौनपुर जिले में साधारण परिवार से जुड़े सतीश निराला भुतहां गांव निवासी हैं। पिछले चार–पांच वर्षों में सोशल मीडिया पर नई पहचान बनकर उभरे हैं। सतीश निराला का शुरू में एक फेसबुक एकांउट था। उसकी सफलता से उत्साहित होकर बाद में दूसरा फेसबुक एकाउंट शुरू किया। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी आए। इनके विषय सामाजिक कमियों, कुरीतियों, सामाजिक विडम्बनाओं, बेराजगारी, ब्यूरोक्रेसी और आमजन की समस्या पर केन्द्रित रहते हैं। इनकी प्रस्तुति आमजन के मानस की पीड़ा को उजागर करने वाली होती है। सुविधा और संसाधन के नाम पर इनके पास एक मोबाइल और माइक है। अब सहयोगी के रूप में उनका 12 वर्षीय लड़का अक्षत सिंह, जो कक्षा सात में पढ़ता है, जुड़ गया है। दोनों पिता–पुत्रों की कोशिश है कि गांव और आस–पास, अधिकतम जिले तक की समस्याओं को सामने लाएं। राष्ट्रीय विषयों पर भी इनका ध्यान केंद्रित रहता है। फेस बुक **'सतीश निराला'** पर इनके डेढ़ लाख फॉलोवर, दूसरे फेसबुक एकाउंट **'समस्या और समाधान'** पर साढ़े तीन लाख फॉलोवर, इंस्टाग्राम **'वॉयस ऑफ विलेजमैन'** पर करीब ढाई लाख फॉलोवर तथा यूट्यूब **'वॉयस ऑफ विलेजमैन'** पर 73 हजार फॉलोवर हैं। फेसबुक एकाउंट **समस्या और समाधान** को मई माह में पांच करोड़ लोगों ने देखा और इसी दौरान डेढ़ लाख फॉलोवर भी बढ़े।

देश की स्थिति तब तक नहीं बदली जा सकती, जब तक लाखों युवा इसकी समुन्नति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित न कर दें।
- डॉ. केशव राव बलिराम हेडगेवार

युवा होनहारों ने सफलता के झंडे गाड़े

अंजलि सिंह
मीडिया विद्यार्थी, आईएमएस, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश में युवाओं की एक ऐसी तस्वीर भी है, जो खेतों, छोटे कस्बों, विद्यालयों, खेल मैदानों और सामाजिक अभियानों में दिखाई देती है। यहां का युवा अब केवल नौकरी की तलाश करने वाला वर्ग नहीं रह गया है। वह खेती में नए प्रयोग कर रहा है, विज्ञान को रोजमर्रा की समस्याओं से जोड़ रहा है, खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और समाज के लिए काम कर रहा है।

बाराबंकी की पूजा पाल : समस्या से निकला वैज्ञानिक समाधान - बाराबंकी की पूजा पाल की कहानी बताती है कि नवाचार के लिए महंगी प्रयोगशाला हमेशा जरूरी नहीं होती। कक्षा आठ में पढ़ते समय उन्होंने देखा कि गांव के पास चलने वाली थ्रेशर मशीन से निकलने वाली धूल बच्चों और आसपास के लोगों के लिए परेशानी पैदा करती है। इसी अनुभव से उन्होंने धूल रहित थ्रेशर का मॉडल तैयार किया। स्थानीय सामग्री से बनाए गए इस मॉडल का उद्देश्य थ्रेशिंग के दौरान उड़ने वाली भूसी और धूल को अलग करना था। पूजा का मॉडल इंस्पायर अवार्ड मानक की राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक पहुंचा और उन्हें जापान के साकुरा साइंस हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। 2025 में उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला। उनकी कहानी का संदेश है कि नवाचार की शुरुआत जिज्ञासा और अपने आसपास की समस्या को पहचानने से होती है।

प्रवीण कुमार : सीमाओं से आगे बढ़ता खेल का हौसला- गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र के प्रवीण कुमार ने पैरा-एथलेटिक्स में भारत को गौरवान्वित किया है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने के बाद पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद टी 64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 2.08 मीटर की छलांग के साथ उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। 2026 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका जीवन उन युवाओं के लिए संदेश है जिन्हें किसी शारीरिक या सामाजिक बाधा के कारण अपने सपनों पर संदेह होता है।

गुरलीन चावला : बुंदेलखंड में खेती का नया प्रयोग - झांसी की गुरलीन चावला ने बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर ऐसा प्रयोग किया, जिसने यह धारणा चुनौती दी कि इस फसल के लिए केवल ठंडे पहाड़ी क्षेत्र ही उपयुक्त हैं। कानून की पढ़ाई कर रहीं गुरलीन ने पहले घर पर स्ट्रॉबेरी उगाने का प्रयोग किया और बाद में खेत में इसका विस्तार किया। उनके प्रयासों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक रूप से सराहा। झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को घर, खाली स्थान और छत पर बागवानी तथा स्ट्रॉबेरी उत्पादन के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया।

शुभावरी चौहान : युवा किसान से बाजार तक - सहारनपुर की 19 वर्षीय शुभावरी चौहान ग्रामीण युवा उद्यमिता की एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। 2026 के फार्म एंड फूड पुरस्कारों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा किसान के रूप में सम्मानित किया गया। वे गन्ने की खेती के साथ उससे मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करती हैं और उनकी प्रीमियम गुड़ तथा संबंधित उत्पादों की पहुंच भारत से बाहर पेरिस, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका तक बताई गई है। शुभावरी जैसी युवा किसान बताती हैं कि गांव का युवा कृषि को आधुनिक व्यवसाय में बदलकर भी आगे बढ़ सकता है।

रामकुमार सिंह जादौन : सामाजिक सेवा को जीवन का हिस्सा बनाना - जालौन के रामकुमार सिंह जादौन को 2025 में

उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार वे कई वर्षों से सामाजिक संगठनों और संस्थानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, बालिकाओं की शिक्षा, गौ सेवा और समाज सुधार से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रहे हैं। उनका काम दिखाता है कि सामाजिक बदलाव को स्थानीय गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। नियमित रक्तदान, शिक्षा के लिए जागरूकता या पर्यावरण संरक्षण जैसी पहल भी समुदाय में प्रभाव पैदा कर सकती है।

यशस्वी जायसवाल : संघर्ष से अंतरराष्ट्रीय पहचान तक - भदोही के सुरियावां से आने वाले

यशस्वी जायसवाल उस युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने से पीछे नहीं हटता। कम उम्र में क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। आज वे भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख युवा खिलाड़ियों में शामिल हैं। राष्ट्रीय टीम में जगह बनाकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनका सफर छोटे शहरों और गांवों के युवाओं को भरोसा देता है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लक्ष्य बड़ा रखा जा सकता है।

पर्यावरण से उद्यमिता तक : युवाओं का बदलता योगदान -

उत्तर प्रदेश में प्रेरक युवा केवल कुछ चर्चित नामों तक सीमित नहीं हैं। मेरठ की ऐहा दीक्षित ने बहुत कम उम्र में पर्यावरण संरक्षण को अभियान बनाया। एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन के अनुसार, उन्होंने चार वर्ष की उम्र से पौधे लगाना शुरू किया और 2023 तक 20 हजार से अधिक पौधों की देखभाल तथा रोपण से जुड़े अभियान में भाग लिया। उनके समूह ने छोटे वन, हरित क्षेत्र और औषधीय उद्यान विकसित करने की दिशा में भी काम किया।

प्रदेश के युवाओं को संस्थागत समर्थन देने की कोशिश भी तेज हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत 21 से 40 वर्ष के युवाओं को उद्योग या सेवा आधारित परियोजनाओं के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याज–मुक्त और बिना गारंटी ऋण देने का प्रावधान है। योजना का लक्ष्य हर वर्ष एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना और दस वर्षों में दस लाख युवाओं तक पहुंच बनाना है। 2026–27 के राज्य बजट में इस अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति मजबूत हुई है। स्टार्टअप इंडिया की 2026 की राज्य रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया। राज्य में इनोवेशन हब, उद्यमिता सहायता और उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने वाली व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। जून 2026 में लखनऊ में आयोजित माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के लगभग 1,500 से अधिक युवा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया।

इन कहानियों की अहमियत इस बात में भी है कि इनमें सफलता का रास्ता एक जैसा नहीं है। किसी के पास खेत है, किसी के पास खेल का मैदान, किसी के पास विज्ञान का छोटा–सा मॉडल और किसी के पास समाज के लिए काम करने का संकल्प। फिर भी सभी में पहल करने, सीखते रहने और दूसरों के लिए रास्ता खोलने की समान भावना दिखाई देती है।

इन उदाहरणों को साथ रखें तो उत्तर प्रदेश के युवा की भूमिका कई स्तरों पर सामने आती है। कोई खेत में नई फसल उगाकर किसानों को नई दिशा देता है, कोई गांव की समस्या का वैज्ञानिक समाधान खोजता है, कोई खेल के मैदान में देश का झंडा ऊंचा करता है और कोई पर्यावरण या सामाजिक सेवा के जरिए समुदाय को जोड़ता है।

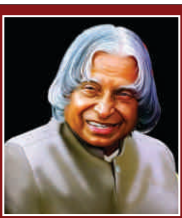

सपना वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने नहीं देता। - डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

कौशल से कॅरियर तक, आत्मनिर्भर बन रहा युवा

रोशनी शंकर
मीडिया विद्यार्थी, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति अब केवल नौकरी की तलाश में नहीं है। वह अपने कौशल को अवसर में बदलने और अवसर को रोजगार में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कोई आईटी और डिजिटल सेवाओं में अपनी जगह बना रहा है, कोई पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ रहा है, तो कोई पारंपरिक हुनर को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़कर अपना कारोबार खड़ा कर रहा है। बदलते उत्तर प्रदेश में युवा अब जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की राह पर भी दिखाई दे रहे हैं।

यही बदलाव कौशल विकास को महत्वपूर्ण बनाता है। आज डिग्री के साथ व्यावहारिक दक्षता, डिजिटल समझ, संवाद क्षमता और बदलती तकनीक सीखने की क्षमता भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और युवा राज्य में कौशल विकास केवल रोजगार की योजना नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक बदलाव का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।

लाखों युवाओं तक पहुंचा कौशल प्रशिक्षण : युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) लगातार काम कर रहा है। राज्य के 2026–27 के बजट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में UPSDM के माध्यम से 9.25 लाख युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर प्रमाणित किया गया है। इनमें 4.22 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

ये आंकड़े बताते हैं कि कौशल विकास अब राज्य की रोजगार नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। प्रशिक्षण में कंप्यूटर, इलेक्ट्रिशियन, हेल्थकेयर, रिटेल, ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन, ब्यूटी एंड वेलनेस, सिलाई और फैशन डिजाइनिंग जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

लेकिन बदलती अर्थव्यवस्था ने कौशल की परिभाषा भी बदल दी है। अब युवाओं को केवल पारंपरिक ट्रेडों में प्रशिक्षित करना पर्याप्त नहीं है। डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में भी युवाओं की दक्षता बढ़ानी होगी।

जिस जिले की पहचान, उसी क्षेत्र का कौशल : उत्तर प्रदेश में कौशल विकास की एक बड़ी संभावना स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। प्रदेश के प्रत्येक जिले की अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान है। यदि युवाओं को उसी स्थानीय अर्थव्यवस्था की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए तो रोजगार के साथ-साथ स्थानीय उद्योगों को भी नई ताकत मिल सकती है।

वाराणसी में पर्यटन, वस्त्र और हस्तशिल्प, मुरादाबाद में पीतल उद्योग, भदोही में कालीन, कानपुर में चमड़ा और विनिर्माण, नोएडा में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पूर्वांचल में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र युवाओं के लिए बड़ी संभावनाएं पैदा करते हैं। यानी कौशल विकास का अगला चरण केवल 'ट्रेनिंग सेंटर तक युवा पहुंचें' नहीं, बल्कि 'स्थानीय उद्योग की जरूरत तक प्रशिक्षण पहुंचे' होना चाहिए।

हुनर से स्वरोजगार की राह : कौशल विकास का सबसे बड़ा प्रभाव तब दिखाई देता है जब प्रशिक्षित युवा नौकरी खोजने के बजाय अपना काम शुरू करने की स्थिति में पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP), मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) जैसी पहलों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

कल्पना कीजिए-किसी युवा को सिलाई का प्रशिक्षण मिलता है और वह अपना छोटी यूनिट शुरू करता है। कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखकर स्थानीय दुकानदारों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराता है। कोई हस्तशिल्प को ई-कॉमर्स से जोड़ता है। कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करता है। ऐसे मामलों में एक प्रशिक्षित युवा केवल अपना रोजगार नहीं बनाता, बल्कि धीरे-धीरे दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकता है। यही वह बिंदु है जहां कौशल, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता एक-दूसरे से जुड़ते हैं।

गांव के युवा के लिए भी नए अवसर : उत्तर प्रदेश की बड़ी युवा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए कौशल विकास की असली परीक्षा गांव और छोटे कस्बों में है। कृषि आधारित व्यवसाय, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, ड्रोन तकनीक, सौर ऊर्जा, मोबाइल रिपेयरिंग, डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स और स्थानीय पर्यटन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण ग्रामीण युवाओं के लिए आय के नए रास्ते खोल सकता है।

इसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि युवाओं को रोजगार के लिए अनिवार्य रूप से बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। यदि स्थानीय स्तर पर कौशल, पूंजी और बाजार उपलब्ध हो जाएं तो गांव और छोटे शहर भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन सकते हैं।

AI के दौर में नया हुनर : कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI ने रोजगार की दुनिया को तेजी से बदलना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एआई और डिजिटल कौशल सीखना महत्वपूर्ण होगा। एआई का इस्तेमाल केवल सॉफ्टवेयर कंपनियों तक सीमित नहीं है। कृषि में फसल संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य सेवाओं में डेटा विश्लेषण, शिक्षा में व्यक्तिगत सीखने की व्यवस्था, पर्यटन में डिजिटल सेवाएं और छोटे कारोबारों में मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में भी इसका उपयोग बढ़ रहा है। इसलिए आज के युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल शायद कोई एक तकनीक नहीं, बल्कि 'लगातार सीखते रहने की क्षमता' है।

डिग्री के साथ हुनर भी : शिक्षा और कौशल को अलग-अलग देखने की बजाय दोनों को साथ लेकर चलना होगा। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं को भी उद्योग की वास्तविक जरूरतों से परिचित कराना जरूरी है। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री विजिट और रोजगार मेलों को शिक्षा का नियमित हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे विद्यार्थी डिग्री हासिल करने के साथ-साथ कार्यस्थल की वास्तविक परिस्थितियों को भी समझ पाएंगे।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश का U-Rise डिजिटल प्लेटफॉर्म भी सीखने और करियर के अवसरों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

महिलाओं के लिए कौशल का मतलब आत्मनिर्भरता : कौशल विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। घर की जिम्मेदारियों के साथ काम करने वाली महिलाओं के लिए डिजिटल वर्क, ई–कॉमर्स, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, ब्यूटी एवं वेलनेस, हेल्थकेयर और छोटे उद्यमों जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण आय के नए अवसर पैदा कर सकता है। महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रशिक्षण केंद्र, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय सहायता को साथ लेकर चलना होगा। यदि एक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो उसका लाभ केवल उसके परिवार को नहीं, बल्कि पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलता है।

प्रशिक्षण से आगे-रोजगार की गारंटी जरूरी : कौशल विकास की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि प्रशिक्षण और वास्तविक रोजगार के बीच की दूरी कम हो। किसी युवा को प्रमाणपत्र मिल जाना सफलता का अंतिम पैमाना नहीं हो सकता। असली सफलता तब होगी जब वह प्रशिक्षण के बाद सम्मानजनक और टिकाऊ रोजगार प्राप्त करे या अपना उद्यम शुरू कर सके। इसके लिए उद्योगों को प्रशिक्षण प्रक्रिया से सीधे जोड़ना होगा। कंपनियों की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार हों, प्रशिक्षण के दौरान व्यावहारिक काम कराया जाए और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अप्रेंटिसशिप तथा प्लेसमेंट का रास्ता उपलब्ध कराया जाए। इसी तरह प्रशिक्षण के बाद भी युवाओं को कुछ समय तक करियर काउंसलिंग, मेंटरशिप और बाजार की जानकारी उपलब्ध कराना उपयोगी होगा।

अब ‘कौशल’ से ‘सामर्थ्य’ की ओर : उत्तर प्रदेश में कौशल विकास की यात्रा एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद अब अगला लक्ष्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता, रोजगार की स्थिरता और उद्यमिता की सफलता होना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि कौशल विकास को शिक्षा, उद्योग, स्टार्टअप, वित्त और बाजार से एक साथ जोड़ा जाए। विश्वविद्यालय विचार दें, प्रशिक्षण संस्थान हुनर विकसित करें, उद्योग रोजगार और अप्रेंटिसशिप दें, सरकार वित्तीय एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराए और डिजिटल प्लेटफॉर्म बाजार तक पहुंच बनाने में मदद करें। तभी कौशल विकास एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से आगे बढ़कर युवा आर्थिक सशक्तिकरण का आंदोलन बन सकेगा।

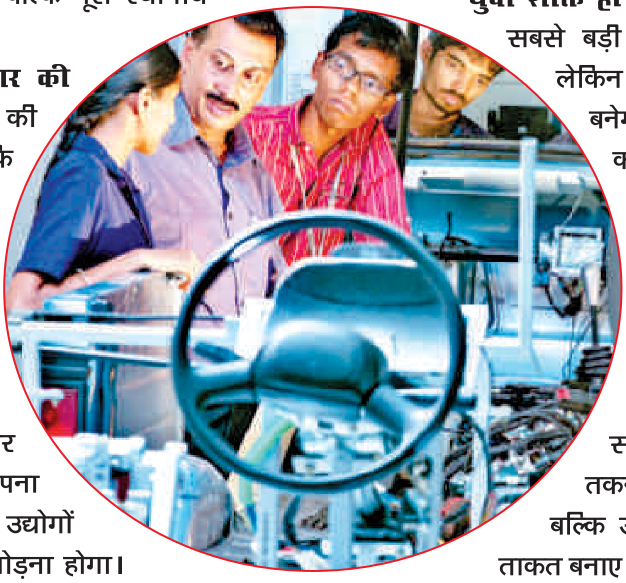

युवा शक्ति ही आर्थिक शक्ति : उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है, लेकिन यह आबादी तभी आर्थिक शक्ति बनेगी जब युवाओं के हाथ में सही कौशल और उनके कौशल के सामने सही अवसर होगा। आज जरूरत ऐसे युवा की है जो केवल नौकरी के लिए आवेदन न करे, बल्कि समस्या को पहचाने और उसका समाधान तलाशे; जो केवल बाजार में रोजगार न खोजे, बल्कि स्थानीय संसाधनों से नया बाजार बनाए; जो तकनीक को केवल इस्तेमाल न करे, बल्कि उसे अपने काम और कारोबार की ताकत बनाए।

कौशलयुक्त युवा उत्तर प्रदेश की नई विकास कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। यदि प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उद्योगों से जुड़ाव, डिजिटल दक्षता, उद्यमिता और रोजगार के अवसरों को एक साथ आगे बढ़ाया जाए, तो उत्तर प्रदेश का युवा न केवल अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे सकता है। कौशल से रोजगार, रोजगार से उद्यम और उद्यम से आत्मनिर्भरता, यही उत्तर प्रदेश के युवा की नई विकास यात्रा है।

शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। - डॉ. भीमराव आंबेडकर

अनोखी वैज्ञानिक उड़ान

नन्द किशोर शर्मा
पूर्व प्रवक्ता, दिल्ली शिक्षा विभाग

विज्ञान हमारे दैनिक जीवन और समाज की प्रगति का मुख्य आधार है। यह हमारे जीवन को सरल बनाता है, अंधविश्वास को दूर करता है तथा चिकित्सा, परिवहन, संचार तकनीक और कृषि जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाकर मानव सभ्यता को नई ऊँचाइयाँ प्रदान करता है। विज्ञान के माध्यम से ही आज हम संचार क्रांति, चिकित्सा क्रांति, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नए–नए आयाम गढ़ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य है। यहाँ के युवा विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध के माध्यम से प्रदेश को विज्ञान एवं शोध के क्षेत्र में देश के एक अग्रणी प्रदेश के रूप में स्थापित कर अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। प्रदेश के युवा विज्ञान, अंतरिक्ष और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राज्य सरकार 'टेक युवा–समर्थ युवा' तथा रिसर्च फैलोशिप जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अनुसंधान में नए अवसर प्रदान कर रही है।

इसके अलावा, राज्य सरकार विज्ञान पार्क, साइंस सिटी और नक्षत्रशालाओं की स्थापना के जरिए युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। वर्तमान में प्रदेश में डिप्लोमा स्तर की 184 संस्थाएँ संचालित हैं, वहीं 36 नए राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 251 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 1,90,064 सीटें हैं, जिनमें युवा विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें से 47 संस्थानों में महिलाओं के लिए विशेष शाखाएँ हैं तथा 12 स्वतंत्र महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं।

विज्ञान, तकनीक और शोध के क्षेत्र में यहाँ के युवा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में डीप–टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म (U-Hub) की स्थापना तथा आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और ड्रोन तकनीक जैसे क्षेत्रों में नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 'टेक युवा–समर्थ युवा' जैसी पहलों के जरिये युवाओं को नए विचारों और वैज्ञानिक शोध को व्यवसाय में बदलने के लिए सहायता मिल रही है। टाटा टेक्नोलॉजी और आईटीआई के सहयोग से युवाओं को आधुनिक उद्योगों की माँग के अनुसार ढाला जा रहा है।

विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कई युवा वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। कुछ प्रमुख प्रेरणादायक सफल युवाओं का संक्षिप्त विवरण प्रदेश के सभी युवाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रेरित करेगा।

अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला : लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट हैं, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने। इन्होंने जून 2006 में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विंग में कमीशन प्राप्त किया। आप एक कुशल कमांड लीडर और टेस्ट पायलट हैं, जिनके पास अनेक विमानों को उड़ाने का 2,000 घंटे से अधिक का अनुभव है। वर्ष 2019 में इन्हें इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए

चुना गया था और रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कठोर प्रशिक्षण मिला।

इन्होंने ऐतिहासिक Axiom Space मिशन-4 के तहत पायलट के रूप में 25 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी तथा लगभग 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे। अंतरिक्ष मिशन के दौरान इनके अदम्य साहस, असाधारण नेतृत्व और योगदान के लिए देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार 'अशोक चक्र' से सम्मानित किया गया।

डॉ. ऋतु करिधाल श्रीवास्तव : उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली डॉ. ऋतु करिधाल को भारत की 'रॉकेट वूमेन' के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की एक बेहद वरिष्ठ और प्रख्यात वैज्ञानिक हैं। बचपन से ही इन्हें अंतरिक्ष और सितारों में गहरी रुचि थी। इन्होंने भौतिकी में बीएससी और एमएससी की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की।

इनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में भारत का मंगलयान मिशन शामिल है, जिसमें इन्होंने डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर के रूप में कार्य किया। इन्होंने मंगलयान की ऑटोनॉमी प्रणाली को डिजाइन और निष्पादित करने में मुख्य भूमिका निभाई। चंद्रयान मिशनों में भी इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। इन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 'इसरो यंग साइंटिस्ट अवार्ड' से सम्मानित किया जा चुका है।

आशीष मिश्रा : उन्नाव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आशीष मिश्रा युवा अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आशीष मिश्रा विशेष रूप से नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स और थ्रॉटलिंग वाल्वों के विकास में सहायक सदस्य रहे हैं, जो चंद्रयान-3 के लैंडिंग प्रयास के लिए महत्वपूर्ण रहे।

खुशबू मिर्जा : जब भी भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता की चर्चा की जाएगी, तब अमरोहा की रहने वाली एवं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा खुशबू मिर्जा का नाम गर्व से लिया जाएगा। साधारण परिवार से निकलकर अंतरिक्ष विज्ञान की ऊँचाइयों तक पहुँची खुशबू ने चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 मिशन का हिस्सा बनकर न केवल अमरोहा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के संकेत की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अनिल पाल : जौनपुर के बरसठी विकासखंड स्थित दतांव गाँव के निवासी अनिल पाल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में वैज्ञानिक बनकर जिले का नाम रोशन किया है। सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। देशभर में कुल 31 चयनित अभ्यर्थियों में 16वाँ स्थान प्राप्त कर 29 वर्षीय अनिल पाल द्वारा हासिल की गई यह शानदार सफलता ग्रामीण क्षेत्र के हर संघर्षरत युवा के लिए एक महान प्रेरणा है।

मुकेश वर्मा : जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के एक सामान्य किसान परिवार के युवक मुकेश वर्मा का चयन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में वैज्ञानिक सहायक के पद पर हुआ है। इन्होंने ओबीसी वर्ग में

आॅल इंडिया 45वीं रैंक प्राप्त की है। इसके अलावा, BARC के आधिकारिक तकनीकी प्रशासन में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के लिए मुकेश कुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में मिलता है।

वैश्विक शोध और नवाचार

डॉ. योगेश्वर नाथ मिश्रा : आजमगढ़ के एक सामान्य किसान परिवार से संबंध रखने वाले डॉ. मिश्रा बचपन से ही कुशाग्रबुद्धि के छात्र रहे हैं। इनके पिता ने पूरे प्रयास से इन्हें पढ़ाया, जिसके लिए उन्हें खेती की जमीन भी बेचनी पड़ी। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉ. मिश्रा ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी और नासा की टीम के साथ मिलकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

इन्होंने दुनिया की सबसे तेज लेजर इमेजिंग टेक्नोलॉजी विकसित करने में बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने दुनिया का सबसे तेज कैमरा बनाया। वर्तमान में आप नासा की नौकरी छोड़कर देश सेवा के लिए तत्पर हैं और आईआईटी जोधपुर में कार्यरत हैं। इनका लक्ष्य भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाना तथा यहाँ एक विश्वस्तरीय लैब बनाना है।

डॉ. गौरव कुमार मिश्रा : डॉ. गौरव कुमार मिश्रा लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में एक युवा वैज्ञानिक हैं, जो एक प्रसिद्ध लाइकेनोलॉजिस्ट हैं। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से भौतिकी में बीएससी एवं एमएससी की शिक्षा प्राप्त की है। इन्हें लाइकेन वर्गीकरण, जैव विविधता और पर्यावरण निगरानी के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए प्रतिष्ठित SIRE फेलोशिप के लिए जाना जाता है।

राहुल सिंह : मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इस युवा नवप्रवर्तक (Innovator) ने लगातार तीन बार इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान हासिल किया। इन्होंने कम उम्र में ही बिना चार्जिंग की बैटरी चालित ट्रैक्टर, इको–फ्रेंडली साइकिल और छोटे ड्रोन जैसी बेहतरीन स्वदेशी तकनीक विकसित की।

उत्तर प्रदेश में विज्ञान और शोध का भविष्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप–टेक स्टार्टअप्स और आधुनिक डेटा केंद्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में नए U-Hub तथा शोध पीठों की स्थापना से युवाओं को तकनीकी शिक्षा, रोजगार और अनुसंधान के लिए नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

सरकार विज्ञान अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों को 10 लाख से 20 लाख रुपये तक की प्रोजेक्ट फंडिंग दे रही है। इसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन, शोध पीठों की स्थापना, फैलोशिप में वृद्धि और आधुनिक विज्ञान केंद्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश के युवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शोध के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का नवाचार एवं अनुसंधान के माध्यम से विकास कर नए–नए कीर्तिमान स्थापित कर सकें तथा उत्तर प्रदेश को विज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त कर परचम लहरा सकें।

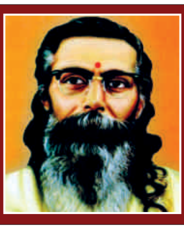

हम अंपनी सम्पूर्ण शक्ति से देशभक्ति की ज्योति जगाएँ। उसे देशव्यापी व प्रखर बनायें। उस प्रकाश में सम्पूर्ण अज्ञानान्धकार लुप्त हो जाएगा।

- श्री गुरुजी

एआई ने बदला तकनीकी परिदृश्य

डॉ. अपर्णा इड़ा श्री
सह प्राध्यापक, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दिल्ली विवि.

उत्तर प्रदेश पारंपरिक रूप से अपनी कृषि–आधारित अर्थव्यवस्था और समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता रहा है। विगत वर्षों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, एआई तकनीक और स्टार्टअप हब ने राज्य की छवि बदली है। इसी वजह से वर्तमान में यह राज्य देश के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर चुका है। यह इकोसिस्टम राज्य के 75 जिलों में से 49 जिलों में कार्यरत है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन चुका है।

उत्तर प्रदेश का हालिया एआई तकनीकी परिदृश्य राज्य के विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश को युवा–नेतृत्व वाले आर्थिक इंजन में बदलने की एकीकृत रणनीति को दर्शाता है। अवसंरचना, कौशल विकास और उद्यम सशक्तीकरण को एकीकृत करके राज्य ने एक सुसंगत एआई डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। जमीनी स्तर पर उद्यम संचालन "मुख्यमंत्री युवा योजना" के तहत यूपीआईकॉन के "यूथ अड्डा" द्वारा क्रियान्वित है, जो सरकारी सहायता को ग्राहकों के लिए सुलभ केंद्रों में परिवर्तित करता है। इतना ही नहीं, एकल–खिड़की ऋण सुविधा, अनुपालन और 100 से अधिक सरल फ्रेंचाइजी मॉडल भी उपलब्ध हैं।

इस नेटवर्क को तकनीकी आधार प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण समझौता इंडिया एआई और यूपीडेस्को के बीच हुआ है, जिसके तहत टियर–II, टियर–III और ग्रामीण जिलों में 65 डेटा और एआई प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं, जहाँ विशेष कंप्यूटिंग क्षमता और वास्तविक दुनिया का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस संरचना को एआई–प्रज्ञा कौशल विकास पहल द्वारा बल दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और उभरती प्रौद्योगिकियों में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना है। ये पूरक नीतियाँ मिलकर तकनीकी कौशल विकास और उद्यम निर्माण के बीच की खाई को पाटती हैं। साथ ही, अग्रणी प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करती हैं, स्थानीय लघु एवं मध्यम उद्यमों का डिजिटलीकरण करती हैं और डिजिटल इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश को नवाचार, ऋण जुटाने और युवा–संचालित विकास के लिए एक अग्रणी क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करती हैं।

इस नीतिगत पहल के मूल में राज्य भर में वितरित डेटा और एआई प्रयोगशालाओं द्वारा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को मौलिक रूप से विकेंद्रीकृत करना है, जिससे लखनऊ और गोरखपुर में NIELIT सुविधाओं के साथ–साथ पीलीभीत जैसे स्थानों से भी उद्योग–साझेदारी वाली प्रयोगशाला सुचारु रूप से कार्य कर सके। यह रोडमैप तकनीकी सशक्तीकरण के लिए एक व्यापक भौतिक नेटवर्क तैयार करता है। इन प्रयोगशालाओं ने उच्च–प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्षमता, विशेषीकृत सॉफ्टवेयर सूट, चयनित डेटासेट और लक्षित शिक्षण मॉड्यूल को सुगम किया है। इस वजह से स्थिर और सैद्धांतिक शिक्षा पर निर्भर रहने के बजाय यह वास्तविक दुनिया से जुड़े ज्ञान की बात करता है।

एआई तकनीक रीयल टाइम पर काम करने का बेहतरीन उदाहरण है। इसके माध्यम से क्राउड मॉनिटरिंग द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर और गोरखनाथ मंदिर में फुटफॉल काउंटिंग और रियल–टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित कर रहा है। यह तकनीक सुरक्षा के साथ–साथ आने–जाने वाले श्रद्धालुओं के डेटा और फ्लो पैटर्न को ग्राफिक्स के रूप में प्रदर्शित करती है ताकि प्रबंधन समिति को अधिक से अधिक डेटा प्राप्त हो सके और भविष्य में आने वाली किसी भी प्रकार की

जानी–अनजानी चुनौती का आसानी से सामना किया जा सके।

पहले बच्चे कंप्यूटर गेम्स मनोरंजन के लिए खेलते थे, लेकिन अब यह प्रोफेशन का रूप ले चुका है, जिसमें गेम डिजाइनर बड़े और जटिल गेमिंग वर्ल्ड बनाने के लिए प्रोसीजरल कंटेंट जनरेशन एआई टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हफ्तों का काम कुछ घंटों में हो जाता है। इसे विकसित करने वाले युवा महज 18 से 20 वर्ष की आयु के होते हैं, जो वर्तमान में एआई गेम को जीवनयापन के विकल्प के रूप में देखते हैं।

कहा जा सकता है कि एआई के आने से पुराने शैक्षिक और प्रोफेशनल कार्यों को करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। यह दृष्टिकोण उभरती प्रौद्योगिकी में संरचनात्मक कौशल अंतर को सीधे लक्षित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय छात्र निष्क्रिय डिजिटल उपभोक्ताओं से सक्रिय डेवलपर्स में परिवर्तित हों, जो उद्यम–स्तरीय AI समाधानों का निर्माण, परीक्षण और तैनाती करने में सक्षम हों।

केस स्टडी-1

औद्योगिक आपूर्ति का डिजिटलीकरण - 'मोग्लिक्स'

संस्थापक - राहुल गर्ग : औद्योगिक वस्तुओं के लिए सुगम B2B लेनदेन को सुविधाजनक बनाना मोग्लिक्स की व्यावसायिक रणनीति का मुख्य आधार है। यह प्लेटफॉर्म आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं और कंपनियों को एक साथ जोड़कर उत्पादों की प्रभावी खरीद–बिक्री को आसान बनाता है। मोग्लिक्स मुख्य रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले सफल लेनदेन पर कमीशन या शुल्क लेकर आय अर्जित करता है, जो इसके लेनदेन–आधारित व्यापार मॉडल को दर्शाता है। इसके अलावा, यह कंपनी आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) अनुकूलन, विक्रेता वित्तपोषण (वेंडर फाइनेंसिंग) और थोक छूट (बल्क डिस्काउंट) जैसी मूल्यवर्धित सेवाएँ प्रदान करके भी अपना मुनाफा कमाती है।

खरीद दक्षता में सुधार करने, एक भरोसेमंद एवं पारदर्शी बाज़ार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के कारण मोग्लिक्स ने औद्योगिक खरीद उद्योग में एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है, जिससे यह भारत में B2B वाणिज्य के डिजिटल रूपांतरण में अग्रणी बन गया है।

केस स्टडी-2

एड-टेक में क्रांति 'फिजिक्स वाला' (Physics Wallah) संस्थापक : अलख पांडे, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)

इस संस्था ने देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग (JEE/NEET) की महँगी कोचिंग के विकल्प के रूप में बेहद किफायती दामों पर एआई–एकीकृत और इंटरैक्टिव डिजिटल शिक्षा की शुरुआत की। यह शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की शुरुआत थी, जो प्रयागराज के एक छोटे से कमरे से शुरू होकर आज भारत के सबसे बड़े एड–टेक 'यूनिकॉर्न' में बदल चुका है।

केस स्टडी-3

स्वास्थ्य सेवा में एआई – 'इन्नोवेसर' (Innovaccer)

संस्थापक : अभिनव शशांक और टीम (नोएडा, उत्तर प्रदेश) : यहां अस्पतालों और डॉक्टरों के पास उपलब्ध मरीजों के डेटा का विश्लेषण कर, उन पर आधारित एक क्लाउड एआई प्लेटफॉर्म तैयार कर स्वास्थ्य सेवा में पहली बार लोकतांत्रिक स्वास्थ्य सेवा की पहल हुई। इतना ही नहीं, यह प्लेटफॉर्म वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने वाले सबसे बड़े डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्मों में से एक है।

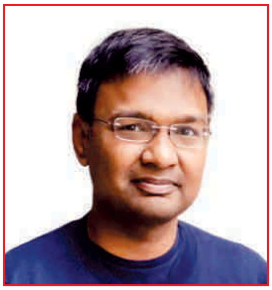

ये कुछ केस स्टडी सरकार, व्यक्तिगत क्षमता निर्माण के अलावा डिजिटल इंडिया की दूरदर्शिता का परिणाम हैं, जो युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत का कार्य कर रही हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे बीच हैं, जो सही सलाह और मार्गदर्शन के उपरांत अपनी पहचान बना रहे हैं और रोजगार ढूँढ़ने वाले न बनकर रोजगार देने वाले बनना पसंद कर रहे हैं।

वर्तमान समय में सरकार द्वारा अनेक ऐसी योजनाएँ हैं, जो समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से अवसर प्रदान कर रही हैं, जैसे महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग इत्यादि। उसी क्रम में तकनीकी ज्ञान भी प्रत्येक वर्ग को समान अवसर दे रहा है, जिससे समाज का प्रत्येक तबका अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर समय के साथ चल सके।

एआई-प्रज्ञा - सुरक्षित प्रशासन और महिला सुरक्षा की दिशा में पहल : 'एआई–प्रज्ञा' का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उस

रणनीतिक रोडमैप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी निगरानी के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

राज्य भर में महिलाओं के लिए एआई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एआई–प्रज्ञा और महिला एआई मिशन जैसे डिजिटल कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और स्मार्ट पुलिसिंग के माध्यम से प्रमुख नगर निगमों में शातिर अपराधी गिरोहों को पकड़ने और उन पर निगरानी के लिए स्मार्ट सीसीटीवी और चेहरे की पहचान करने वाले उपकरणों की तैनाती पर कार्य किया जा रहा है और बहुत से मामलों में सफलता भी हाथ लगी है।

उदाहरण के लिए, लखनऊ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौराहों और महिलाओं की भारी आवाजाही वाले क्षेत्रों में लगभग 700 से अधिक स्मार्ट एआई कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 100 कैमरे चेहरे की पहचान तकनीक से लैस हैं। कुछ कैमरों को संदिग्ध व्यवहार का पता लगाने और अपराध परिदृश्यों की पहचान के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जैसे महिलाओं के कॉलेजों और बाजारों के पास लड़कियों या पुरुषों का झुंड बनाकर खड़ा होना, लव–जिहाद की प्रेरित मानसिकता से भरे लोगों द्वारा नाबालिग बच्चियों को बहला–फुसलाकर प्रेम के जाल में फँसाना और धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या फिर एसिड अटैक जैसे असामाजिक कार्यों को अंजाम देने वाले मानसिक रूप से पीड़ित लोगों की पहचान और उचित कार्रवाई करना।

इसके साथ–साथ गौतमबुद्धनगर जैसे कुछ स्थानों पर नाइट विजन और भीड़ विश्लेषण वाले एआई कैमरे लगाए गए हैं, जो संवेदनशील इलाकों में हिंसक व्यवहार को तुरंत ट्रैक कर लेते हैं। इनमें क्राइम जीपीटी और एकीकृत नियंत्रण कक्ष का उपयोग यूपी पुलिस स्टैक टेक्नोलॉजीज के सहयोग से कर रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन और पारिवारिक लाभ योजनाओं की निगरानी के लिए एआई का प्रयोग किया जा रहा है। इससे आवेदकों की सटीक जाँच होती है। वाधवानी एआई (Wadhwani AI) जैसी संस्थाओं के साथ साझेदारी की जा रही है, जिससे एआई–संचालित मोबाइल टूल्स के द्वारा नवजात शिशुओं का वजन और शारीरिक विकास मापा जा सके। इन आवश्यक जानकारियों की मदद से भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की जटिल समस्याओं से बचा जा सके।

प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वोकेशनल कोर्स में 'AI फॉर ऑल' (AI for All) कोर्स को अनिवार्य किया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में दो लाख से अधिक बच्चों को एआई टूल्स और कोडिंग की बेसिक शिक्षा मुफ्त दी जा रही है। इसके साथ–साथ स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास एआई सीसीटीवी के माध्यम से कड़ी निगरानी की जा रही है, जिससे आज के युवाओं को ड्रग पेडलर्स, मानव देह व्यापार गिरोहों इत्यादि असामाजिक तत्वों से बचाया जा सके।

उत्तर प्रदेश राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थलों और कला परंपराओं को एआई ग्राफिक्स, डिजिटल कला और वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से पुनर्जीवित और प्रदर्शित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और स्थानीय डिजिटल कलाकारों द्वारा अयोध्या (श्रीराम मंदिर), काशी (वाराणसी के घाट) और मथुरा–वृंदावन के काल्पनिक 3D हाई–डेफिनिशन ग्राफिक्स तैयार किए जा रहे हैं।

भारत की नियति उसके युवाओं के हाथों में है। - श्री अरविंद

एक क्लिक का विवेक, हजार अफवाहों पर ब्रेक

डॉ. राजीव वर्मा
सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय, गाजियाबाद

मोबाइल पर एक संदेश आता है, साथ में सरकारी दस्तावेज जैसा चित्र और उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील होती है। संदेश किसी परिचित ने भेजा हो तो हम सहज ही विश्वास कर उसे बिना जांचे आगे बढ़ा देते हैं। कुछ ही मिनटों में वह कई व्हाट्सऐप समूहों, फेसबुक पेजों और अन्य सामाजिक माध्यमों तक पहुंच जाता है। लेकिन हम अक्सर यह जांचना भूल जाते हैं कि क्या साझा की जा रही सूचना वास्तव में सही है? यही सामान्य–सी लगने वाली प्रक्रिया आज एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि तकनीक ने अफवाहों को फैलाने की गति और उनके प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया है।

जब अफवाह को मिल जाए तकनीक का सहारा : आज अफवाहों का स्वरूप बदल चुका है। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति सामग्री बनाकर कुछ ही क्षणों में हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। समस्या तब गंभीर होती है, जब तकनीक के सहारे झूठ को सच जैसा बनाया जाए। पुरानी तस्वीर को नई घटना से जोड़ना, बयान को तोड़–मरोड़कर पेश करना, नकली सरकारी आदेश बनाना या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से किसी व्यक्ति का झूठा वीडियो तैयार करना आज की प्रमुख चुनौतियां हैं। समस्या केवल फेक न्यूज की नहीं, बल्कि ऐसी सूचना–परिस्थिति की है, जहां सच और झूठ एक ही स्क्रीन पर समान दिखाई देते हैं। इस बदलती सूचना–परिस्थिति का प्रभाव विशेष रूप से युवाओं पर पड़ता है क्योंकि वे डिजिटल माध्यमों के सबसे सक्रिय उपयोगकर्ताओं में हैं। भर्ती, परीक्षा, सरकारी योजना या स्थानीय घटना से जुड़ी गलत सूचना युवाओं को तत्काल निर्णय लेने या दूसरों को सक्रिय करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस प्रकार डिजिटल सूचना वास्तविक सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करती है।

उत्तर प्रदेश की हाल की घटनाएं इस खतरे को समझने का अवसर देती हैं। मई 2026 में हापुड़ में महाराणा प्रताप जयंती के दौरान हुई हिंसा के वीडियो को झूठे दावे के साथ प्रसारित किया गया कि मेरठ में छह मस्जिदें तोड़ी गईं और 52 मुस्लिम परिवारों के घर जला दिए गए। फैक्ट–चेक में सामने आया कि वीडियो हापुड़ का था, जहां रैली में शामिल युवाओं और एक दुकानदार के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। यह उदाहरण दिखाता है कि वास्तविक घटना को गलत संदर्भ देकर आसानी से भ्रामक कहानी में बदला जा सकता है। युवा वर्ग सूचना को सबसे पहले प्राप्त कर उसे तेजी से आगे बढ़ाता है, इसलिए वह फेक न्यूज रोकने की पहली सामाजिक शक्ति भी बन सकता है। संदिग्ध संदेश को आगे भेजने से पहले उसकी सत्यता जांच लेना गलत सूचना की पूरी श्रृंखला को रोक सकता है।

यह समस्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और युवा प्रदेश में और महत्वपूर्ण हो जाती है। गांवों, कस्बों, नगरों और महानगरों में पढ़ने वाला, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला,

मीडिया मॉनिटरिंग

उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली भ्रामक, आपत्तिजनक और संवेदनशील सूचनाओं की निगरानी कर रहे हैं। फर्जी सूचनाओं की पहचान कर उनके खंडन और आवश्यक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है।

रोजगार की तलाश करने वाला और अपना व्यवसाय शुरू करने वाला युवा डिजिटल माध्यमों से गहराई से जुड़ा है। यहां किसी परीक्षा की तिथि, भर्ती, छात्रवृत्ति, सरकारी योजना या प्रशासनिक आदेश से जुड़ी गलत सूचना हजारों युवाओं को प्रभावित कर सकती है। इसी प्रकार किसी स्थानीय घटना से संबंधित अपुष्ट वीडियो या संदेश सामाजिक वातावरण को प्रभावित कर सकता है। इसलिए गलत सूचना से मुकाबला केवल सरकारी स्तर पर नहीं, बल्कि समाज और विशेषकर युवाओं की सजग भागीदारी से ही प्रभावी बनाया जा सकता है। हालांकि, इस दिशा में सरकार भी कई पहल कर रही है।

सरकारी प्रयासों से आगे : केंद्र सरकार के अनुसार, फर्जी–भ्रामक सूचनाओं और AI–निर्मित सामग्री से निपटना बड़ी चुनौती है। पीआईबी तथ्य जाँच इकाई (PIB Fact Check Unit - FCU) ऐसी सूचनाओं की जांच कर उनकी वास्तविकता स्पष्ट करती है। अप्रैल 2026 तक FCU 2,913 फैक्ट–चेक प्रकाशित कर चुकी थी। सरकारी प्रयासों के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं में मीडिया साक्षरता भी आवश्यक है। इसका अर्थ केवल इंटरनेट चलाना नहीं, बल्कि स्रोत परखना, तथ्य–राय में अंतर करना, संदर्भ समझना और प्रमाण देखना है।

युवा केवल सूचना के उपभोक्ता ही नहीं बल्कि उसके प्रहरी भी बनें। इसके लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मीडिया साक्षरता को नागरिक शिक्षा का हिस्सा बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों को वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से यह सिखाया जा सकता है कि किसी वायरल तस्वीर की जांच कैसे करें, किसी वीडियो का मूल स्रोत कैसे खोजें, फर्जी सरकारी आदेश और वास्तविक अधिसूचना में अंतर कैसे करें तथा AI–जनित सामग्री के प्रति सावधानी कैसे बरतें। प्रदेश के महाविद्यालयों में 'पहले जांच, फिर साझा' जैसे छोटे–छोटे अभियान चलाए जा सकते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल गलत सूचना पहचानना ही नहीं है बल्कि व्यापक उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है, जो डिजिटल दुनिया में उपलब्ध सूचनाओं को समझें, उन पर प्रश्न करें और प्रमाण के आधार पर अपनी राय बनाएं। यही आवश्यकता हमें एक कदम आगे बढ़कर 'विवेकशील डिजिटल नागरिक' की भूमिका की ओर ले जाती है।

सिर्फ ऑनलाइन नहीं, विवेकशील भी बनें : विद्वानों का मानना है कि गलत सूचनाओं का प्रभाव व्यापक होता है। किसी भी लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका मतदान केंद्र तक सीमित

नहीं होती। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक उपलब्ध सूचनाओं को समझने, प्रश्न करने और प्रमाण के आधार पर अपनी राय बनाने की क्षमता रखते हों। गलत सूचना नागरिकों को भ्रमित कर सकती है, सामाजिक विश्वास को कमजोर कर सकती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा कर सकती है।

इसलिए आज के युवा के सामने चुनौती केवल यह नहीं है कि वह ऑनलाइन रहे या न रहे। वास्तविक चुनौती यह है कि वह ऑनलाइन रहते हुए कितना विवेकशील रहे। उसे यह समझना होगा कि किसी सूचना को तुरंत साझा करना केवल एक डिजिटल क्रिया नहीं है। उसके पीछे सामाजिक और कभी–कभी वास्तविक जीवन के परिणाम भी हो सकते हैं। हमें ऐसी युवा पीढ़ी चाहिए जो वायरल होने की होड़ में शामिल होने के बजाय सत्य की खोज करे, जो किसी पोस्ट की लोकप्रियता से प्रभावित होने के बजाय उसके प्रमाण को देखे और किसी संदेश को आगे बढ़ाने से पहले यह सोचे कि उसका प्रभाव किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज पर क्या पड़ेगा?

फैक्ट–चेकिंग कुछ सेकंड का काम है, लेकिन उसका सामाजिक दायित्व बड़ा है। किसी सूचना को तुरंत साझा करने के बजाय रुककर उसका स्रोत और तारीख जांचें। सरकारी योजनाओं या आदेशों के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें। संदिग्ध तस्वीरों की रिवर्स इमेज सर्च और वीडियो के मूल स्रोत व संदर्भ की जांच करें। सरकारी

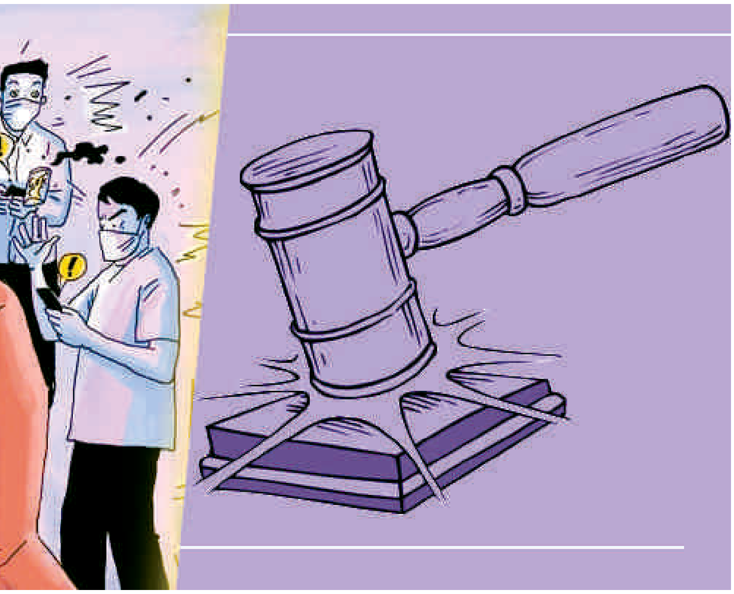

मोबाइल में आई हर सूचना के साथ उनका विवेक भी सक्रिय हो। आज के युग में जिम्मेदार नागरिक वही है जो हर महत्वपूर्ण सूचना की सत्यता जांचता हो, क्योंकि एक जागरूक क्लिक हजारों गलत क्लिकों को रोक सकता है।

उत्तर प्रदेश में भी डिजिटल सूचना के इस बदलते परिदृश्य को देखते हुए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, साइबर अपराध नियंत्रण और जन–जागरूकता के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया तंत्र और साइबर सेल के माध्यम से वायरल सूचनाओं, फर्जी दावों, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अपराधों के प्रति नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सरकारी प्रयास तभी अधिक प्रभावी होंगे, जब युवा स्वयं जिम्मेदार डिजिटल नागरिक की भूमिका निभाएंगे।

सूचनाओं के लिए पीआईबी तथ्य जाँच इकाई (PIB Fact Check Unit - FCU) की मदद ली जा सकती है। हालांकि, हर सूचना की जांच संभव नहीं है इसलिए नागरिक का विवेक ही पहली और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है।

आज प्रत्येक युवा को अपने डिजिटल व्यवहार में एक नियम जोड़ना होगा कि किसी भी सूचना को आगे बढ़ाने से पहले उसकी जांच करें। किसी खबर को आगे बढ़ाने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन गलत सूचना से पैदा हुई भ्रांति को दूर करने में कई दिन लग सकते हैं। खासकर युवा वर्ग के लिए यह जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी डिजिटल सक्रियता सूचना के प्रसार की गति को कई गुना बढ़ा सकती है।

युवा शक्ति यदि इस अंतर को समझ ले, तो वह केवल फेक न्यूज़ का शिकार होने से स्वयं को ही नहीं बचाएगी, बल्कि अपने परिवार, समाज और प्रदेश को भी सूचना के इस नए संकट से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आखिरकार, सशक्त लोकतंत्र की पहचान यह है कि उसके नागरिकों के

साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूकता

उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए साइबर क्राइम पुलिस और साइबर सेल के माध्यम से अभियान चलाए जा रहे हैं। यह मीडिया साक्षरता के व्यापक उद्देश्य से सीधे जुड़ता है।

उत्तर प्रदेश में युवाओं को डिजिटल तकनीक, कंप्यूटर और आधुनिक कौशल से जोड़ने के लिए विभिन्न कौशल-विकास एवं डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता के साथ सूचना-साक्षरता को भी मजबूत करने की आवश्यकता है।

स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।
-लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

ओडीओपी : सफर लोकल से ग्लोबल तक

डॉ. आभा सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग
महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

किसी क्षेत्र की पहचान केवल उसके इतिहास से नहीं बनती, बल्कि उस कौशल से भी बनती है जिसे वहाँ के लोग पीढ़ियों से सहेजकर रखते हैं। जब ये हुनर आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों से जुड़ता है, तब वह स्थानीय उत्पादन से आगे बढ़कर वैश्विक पहचान बन जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक जनपद, एक उत्पाद योजना इसी सोच का परिणाम है, जिसने स्थानीय उद्योगों को नया जीवन देने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी खोले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का महत्व इस बात से भी बढ़ता है कि इसकी विशिष्टता के कारण ही इसको बाद में केंद्र सरकार और अन्य राज्यों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया हैं।'

उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका लगभग हर जनपद अपनी किसी विशिष्ट कला, हस्तशिल्प या पारंपरिक उद्योग के लिए जाना जाता है। वाराणसी की बनारसी साड़ी, लखनऊ की चिकनकारी, कन्नौज का इत्र, मुरादाबाद का पीतल शिल्प, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, भदोही के कालीन, फिरोजाबाद का काँच उद्योग, अलीगढ़ के ताले और मेरठ का खेल उद्योग केवल व्यापारिक सामग्री नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय अर्थव्यवस्था की पहचान भी हैं। समय के साथ इन पारंपरिक उद्योगों को बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, बिक्री के लिए आधुनिक साधनों का अभाव, बिचौलियों पर निर्भरता तथा डिजिटल माध्यमों से दूरी जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अनेक कारीगरों की आय प्रभावित हुई और नई पीढ़ी भी इन पारंपरिक व्यवसायों से

दूर होने लगीं। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य केवल उत्पादों की बिक्री बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक जिले की पारंपरिक पहचान को पुनर्जीवित कर उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना था।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। इसमें प्रत्येक जिले के उस उत्पाद का चयन किया जाता है जो वहाँ की पहचान, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हो। इसके बाद कारीगरों और उद्यमियों को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिज़ाइन सुधार, उत्पादनों की गुणवत्ता बढ़ाना, आकर्षक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, उत्पादनों को खरीदारों तक पहुँचाने में सहायता प्रदान करना और बैंक ऋण जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी हैं। कई स्थानों पर सामूहिक सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ छोटे उद्यमी आधुनिक मशीनों और परीक्षण सुविधाओं का उपयोग कर अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, ई–कॉमर्स मंचों और डिजिटल मीडिया माध्यमों से उनके उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार यह योजना केवल उत्पादन नहीं, बल्कि उत्पादन से लेकर व्यापार तक की पूरी प्रक्रिया को सशक्त बनाती है।

यदि इस योजना की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण खोजा जाए तो वह है डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग। आज किसी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता के साथ–साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसकी जानकारी कितने लोगों तक पहुँचती है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के प्रसार ने उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे कारीगर को भी वैश्विक बाजार से जोड़ दिया है।

पहले जहाँ किसी स्थानीय उत्पाद को अपने जिले से बाहर पहचान दिलाना कठिन था, वहीं आज वह सोशल मीडिया, ई–कॉमर्स वेबसाइटों और डिजिटल प्रचार के माध्यम से देश–विदेश के ग्राहकों तक आसानी से पहुँच रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप बिजनेस और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ार्मस ने छोटे उद्यमियों के लिए ऐसे अवसर खोले हैं जिनकी कल्पना कुछ वर्ष पहले तक करना कठिन थी। अब कोई कारीगर अपने उत्पाद की तस्वीर, निर्माण प्रक्रिया का वीडियो या उसकी ऐतिहासिक कहानी सीधे ग्राहकों तक पहुँचा सकता है। इससे न केवल बिक्री बढ़ती है, बल्कि उत्पाद की एक अलग पहचान बनती है। यही कारण है आज डिजिटल मीडिया, एक जनपद एक उत्पाद योजना की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है।

डिजिटल माध्यमों के साथ जीआई टैग (Geographical Indication-GI Tag) की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जीआई टैग किसी उत्पाद की उस विशिष्ट पहचान का कानूनी प्रमाण है जो उसे किसी विशेष जनपद या क्षेत्र, परंपरा या निर्माण पद्धति से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए बनारसी साड़ी, लखनऊ की चिकनकारी, कन्नौज का इत्र और भदोही के कालीन जैसे उत्पाद केवल वस्तुएँ नहीं हैं, बल्कि अपने–अपने क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान हैं। ऑनलाइन खरीदारी के दौर में ग्राहक सबसे पहले उत्पाद की प्रामाणिकता पर भरोसा करना चाहता है।

जीआई टैग यह भरोसा प्रदान करता है कि वह उत्पाद वास्तव में उसी क्षेत्र का है जिसके लिए वह प्रसिद्ध है। इससे जहां एक तरफ नकली सामग्री पर रोक लगाने में सहायता मिलती है वहीं दूसरी तरफ वास्तविक कारीगरों को उनके कार्य का उचित मूल्य भी प्राप्त होता है। यही वजह है कि आज जीआई टैग केवल कानूनी सुरक्षा का माध्यम ही नहीं, बल्कि डिजिटल ब्रांडिंग का भी मजबूत आधार बन गया है। जब किसी उत्पाद के साथ उसकी भौगोलिक पहचान और सांस्कृतिक कहानी भी डिजिटल माध्यमों पर प्रस्तुत की जाती है, तब उसका बाजार मूल्य और ग्राहकों का भरोसा दोनों बढ़ जाते हैं।

उत्तर प्रदेश के अनेक जिले इस परिवर्तन के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरठ का खेल उद्योग बड़ी तेजी से अपनी वेबसाइटों, डिजिटल कैटलॉग और

सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से विदेशी खरीदारों तक पहुँच रहा है। कन्नौज का इत्र डिजिटल स्टोरीटेलिंग के माध्यम से अपनी पारंपरिक निर्माण प्रक्रिया और ऐतिहासिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी और मुरादाबाद का पीतल शिल्पकार्य भी ऑनलाइन मंचों के माध्यम से नई पहचान प्राप्त कर रहे हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि डिजिटल माध्यम केवल उत्पाद बेचने का साधन नहीं हैं, बल्कि वे स्थानीय पहचान को वैश्विक मंच तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम भी बन चुके हैं।

इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सकारात्मक प्रभाव उत्तर प्रदेश के युवाओं पर देखने को मिलता है। आज रोजगार का अर्थ केवल सरकारी या निजी नौकरी तक सीमित नहीं रह गया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने युवाओं के सामने अनेक नए विकल्प खड़े कर दिये हैं। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रबंधन, उत्पाद फोटोग्राफी, वीडियो निर्माण, वेबसाइट विकास, ई–कॉमर्स प्रबंधन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO), ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल विज्ञापन जैसे क्षेत्र आज एक जनपद एक उत्पाद योजना से जुड़े उद्योगों की महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ बन चुके हैं। इसका मतलब है कि कोई युवा स्वयं उत्पादन किये बिना भी स्थानीय उद्योगों से जुड़कर सफल उद्यमी या पेशेवर बन सकता है। पत्रकारिता, जनसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और डिजाइन जैसे विषयों के विद्यार्थी भी इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार और स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना केवल पारंपरिक व्यापार संरक्षण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि डिजिटल उद्यमिता और युवा नेतृत्व वाले आर्थिक विकास का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है।

आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विश्लेषण और डिजिटल व्यापार जैसे क्षेत्र भी इस योजना को नई दिशा दे रहे हैं। भविष्य में इन स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन ब्रांडिंग, बहुभाषी प्रचार सामग्री, वैश्विक बाजार का विश्लेषण और ग्राहकों की पसंद के अनुसार व्यापार की रणनीति तैयार करने में नई तकनीकों की भूमिका और बढ़ेगी। यदि उत्तर प्रदेश का युवा इन तकनीकों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ता है, तो वह केवल अपने लिए रोजगार ही नहीं बनाएगा, बल्कि अपने जिले की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊँचाइयों तक ले जा सकेगा।

अंततः यह कहा जा सकता है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय अर्थव्यवस्था, जीआई टैग और डिजिटल तकनीक का ऐसा समन्वित विकास मॉडल है जिसने युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। इसने यह सिद्ध किया है कि यदि परंपरागत कौशल को आधुनिक तकनीक, डिजिटल प्रचार और वैश्विक बाजार से जोड़ा जाए तो स्थानीय उत्पादन विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश का युवा अपने जनपद की विशेषता को पहचाने, उसे डिजिटल माध्यमों से दुनिया तक पहुँचाए और 'लोकल टू ग्लोबल' की इस यात्रा का सक्रिय भागीदार बने। यही एक जनपद एक उत्पाद योजना की वास्तविक सफलता है और यही विकसित उत्तर प्रदेश तथा आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला भी है।

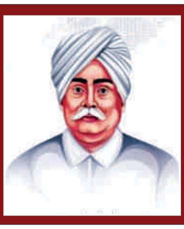

युवाओं को राष्ट्र के भविष्य के निर्माण के लिए आगे आना चाहिए। **-लाला लाजपत राय**

खेतों की पगडंडियों से राष्ट्रमंडल के मंच तक

श्रेयांशी
शोधार्थी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

"जहाँ पसीने की हर बूँद में संकल्प पलता है,
वहीं विजय का तिरंगा सबसे पहले खिलता है।"

उत्तर प्रदेश केवल भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की भूमि नहीं है; यह खेल–प्रतिभाओं की भी उर्वर धरती है। गंगा–यमुना के दोआब से लेकर पूर्वांचल के गाँवों तक, बुंदेलखंड की कठोर मिट्टी से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अखाड़ों और खेतों तक यहाँ की पगडंडियों पर दौड़ते, मिट्टी में कुश्ती लड़ते, निशाना साधते और सीमित साधनों में सपनों को सींचते युवाओं ने राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय खेल–मंच पर भी भारत का गौरव बढ़ाया है।

उत्तर प्रदेश के खेल–इतिहास को यदि गाँवों के नामों के साथ पढ़ा जाए तो यह किसी प्रेरक महाकाव्य से कम नहीं लगता। सिसौली की अलका तोमर, पुरबालियान की दिव्या काकरान, कालिना के सौरभ चौधरी, भैंसा के रवि कुमार, ददूपुर की पूनम यादव, इकलौता की पारुल चौधरी और सिरसा के गुलवीर सिंह,ये केवल खिलाड़ी नहीं, बल्कि उस युवा उत्तर प्रदेश की जीवंत तस्वीर हैं, जहाँ अभाव प्रतिभा को रोक नहीं पाता।

किसी भी महान खिलाड़ी की यात्रा पदक से नहीं, बल्कि उस छोटे से मैदान से शुरू होती है जहाँ वह पहली बार अपने सपने को पहचानता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं की यही विशेषता है। गाँव का अखाड़ा हो या विद्यालय का मैदान, गन्ने के खेत की मेड़ हो या कच्ची सड़क,यहीं से अनेक राष्ट्रीय सितारों की यात्रा प्रारंभ हुई।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुश्ती परंपरा ने देश को अनेक प्रतिभाएँ दी हैं। मेरठ जिले के सिसौली गाँव की अलका तोमर इसका प्रेरक उदाहरण हैं। उन्होंने 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 59 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय महिला कुश्ती को नई पहचान दी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाया मुजफ्फरनगर के पुरबालियान गाँव की दिव्या काकरान ने। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बीच संघर्ष करते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में भारत का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतकर सिद्ध किया कि बेटियां अवसर मिलने पर मिट्टी को भी सोना बना सकती हैं।

वाराणसी की धरती ने भी कुश्ती के क्षेत्र में अपना परचम फहराया। नरसिंह पंचम यादव, जिनका संबंध वाराणसी क्षेत्र से है, ने 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। उनके प्रदर्शन ने पूर्वांचल की कुश्ती परंपरा को राष्ट्रीय पहचान दी।

युवा खेल-प्रतिभाओं की एक और विशिष्ट पहचान है-

शूटिंग में मेरठ के निकट कालिना गाँव के सौरभ चौधरी ने छोटी उम्र में ही भारतीय शूटिंग को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। उन्होंने 2018 युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। गाँव में साधारण संसाधनों से शुरू हुआ उनका सफर अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज तक पहुँचा। मेरठ के भैंसा गाँव के रवि कुमार ने भी

अलका तोमर

दिव्या काकरान

नरसिंह पंचम यादव

सौरभ चौधरी

निशानेबाजी में देश का गौरव बढ़ाया। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। उनके पास प्रारंभिक दौर में अत्याधुनिक संसाधन नहीं थे; परिवार के सहयोग और अपने संकल्प के बल पर उन्होंने अपनी राह बनाई।

इन खिलाड़ियों की कहानियाँ बताती हैं कि प्रतिभा महानगरों की मोहताज नहीं। कभी-कभी भारत का अगला चैंपियन किसी महानगर के वातानुकूलित प्रशिक्षण केंद्र में नहीं, बल्कि गाँव की धूल में अपना पहला अभ्यास कर रहा होता है।

वाराणसी के ददूपुर गाँव की पूनम यादव की कहानी उत्तर प्रदेश की बेटियों के अदम्य साहस की कहानी है। किसान परिवार से आने वाली पूनम ने सीमित संसाधनों के बावजूद वेटलिफ्टिंग को अपना जीवन बनाया। 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक के बाद 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। गाँव लौटने पर उनका जिस प्रकार स्वागत हुआ, वह इस बात का प्रतीक था कि एक बेटी की विजय पूरे गाँव की विजय बन जाती है। पूनम की कहानी केवल पदक की कहानी नहीं है; यह उस सामाजिक परिवर्तन की कहानी है जिसमें ग्रामीण भारत की बेटियाँ परिवार की सीमाओं से निकलकर विश्व-मंच पर अपनी पहचान गढ़ रही हैं।

उत्तर प्रदेश की खेल-यात्रा में महिला खिलाड़ियों का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मेरठ की प्रियंका गोस्वामी ने 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। बस कंडक्टर की बेटी से राष्ट्रमंडल पदक विजेता बनने तक का उनका सफर कठिन परिश्रम, धैर्य और आत्मविश्वास की मिसाल है।

इसी श्रृंखला की नई और तेजस्वी कड़ी हैं मेरठ के इकलौता गाँव की पारुल चौधरी। कभी नंगे पाँव दौड़ने वाली यह बेटी आज भारत की अग्रणी लंबी दूरी की धाविकाओं में शामिल है। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश की ओर से भारतीय दल में पारुल का चयन इस बात का प्रमाण है कि गाँव की पगडंडी से शुरू हुई दौड़ अब विश्व के सिंथेटिक ट्रैक तक पहुँच चुकी है।

वर्ष 2026 ने उत्तर प्रदेश के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश के अनेक खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय दल में गुलवीर सिंह, कुलदीप कुमार, रोहित यादव, पारुल चौधरी, प्रियंका गोस्वामी, नीरू पाठक, अस्मिता डे, आदित्य प्रताप सिंह तथा पैरा एथलीट सागर थायत और श्रेयांश त्रिवेदी जैसे खिलाड़ी शामिल रहे।

इनमें अलीगढ़ के सिरसा गाँव के गुलवीर सिंह की कहानी विशेष रूप से प्रेरक रही। खेतों की पगडंडियों पर दौड़ते हुए उन्होंने ग्लासगो के अंतरराष्ट्रीय ट्रैक तक का सफर तय किया और 10,000 मीटर में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। राष्ट्रमंडल खेलों में इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने। गुलवीर की सफलता का अर्थ केवल एक रजत पदक नहीं है। इसका अर्थ है, गाँव की मिट्टी ने विश्व के ट्रैक पर अपनी पहचान लिख दी। उत्तर प्रदेश के इन युवाओं की यात्रा में एक समान सूत्र दिखाई देता है संकल्प, संघर्ष, अनुशासन और परिवार का विश्वास। इन खिलाड़ियों ने यह मिथक तोड़ा है कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के लिए केवल महानगरों में जन्म लेना आवश्यक नहीं है बल्कि वो दृढ़ संकल्प व मजबूत इरादों के साथ गाँव की पगडंडियों से राष्ट्रमंडल खेलो का सफर तय कर सकते है।

राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश का योगदान : कुश्ती, निशानेबाजी, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स और अन्य खेलों में प्रदेश के युवाओं ने भारत की पदक-यात्रा को गति दी है। 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर 2018 के गोल्ड कोस्ट, 2022 के बर्मिंघम और 2026 के ग्लासगो तक यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ी है। उपलब्ध अभिलेखों में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के कुश्ती, शूटिंग, भारोत्तोलन, हॉकी और एथलेटिक्स में पदक दर्ज हैं।

उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास को संस्थागत रूप देने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू खेल नीतियों का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक हो जाता है! उत्तर प्रदेश खेल नीति-2023 में जमीनी स्तर के खिलाड़ियों से लेकर एलीट खिलाड़ियों तक आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। जूनियर खिलाड़ियों के लिए ₹75,000, सब-जूनियर के लिए ₹50,000, विकासशील खिलाड़ियों के लिए ₹2 लाख और एलीट खिलाड़ियों के लिए ₹3 लाख तक वार्षिक सहायता का प्रावधान है। खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल-विज्ञान कर्मियों

के लिए ₹5 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा तथा वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर या उससे ऊपर के खिलाड़ियों के लिए पेंशन व्यवस्था भी नीति का हिस्सा है।

नीति का लक्ष्य केवल पदक जीतना नहीं, बल्कि खिलाड़ी के संपूर्ण जीवन-चक्र, प्रतिभा पहचान, प्रशिक्षण, पोषण, स्वास्थ्य, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर और करियर को सुरक्षित करना है। राज्य ने ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं के लिए आकर्षक पुरस्कार व्यवस्था भी विकसित की है। राज्य सरकार के उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार राष्ट्रमंडल खेलों/विश्व कप स्तर की उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पर ₹1.5 करोड़, रजत पर ₹75 लाख और कांस्य पर ₹50 लाख तक पुरस्कार का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। लगभग ₹700 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस संस्था में हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, तैराकी, साइकिलिंग सहित अनेक खेलों की अत्याधुनिक सुविधाएँ प्रस्तावित हैं। इसकी प्रशिक्षण क्षमता 1,080 खिलाड़ियों,540 पुरुष और 540 महिला खिलाड़ियों की है।

प्रियंका गोस्वामी पारुल चौधरी गुलवीर सिंह

यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की खेल-प्रतिभा को गाँव से विश्व-मंच तक पहुँचाने का संस्थागत सेतु है। प्रधानमंत्री मोदी "खेल" से "खिलाड़ी" और "खिलाड़ी" से "राष्ट्र" पर बल देते है। प्रधानमंत्री ने खेलों को राष्ट्रनिर्माण की व्यापक दृष्टि से जोड़ा है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया और टॉप्स जैसी पहलों ने प्रतिभा खोज, प्रशिक्षण और उच्चस्तरीय तैयारी के लिए नया वातावरण तैयार किया है।

खेलो इंडिया का मूल उद्देश्य ही जमीनी स्तर पर खेल-संस्कृति को पुनर्जीवित करना और प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाना है। 2018 से अब तक 63,000 से अधिक खिलाड़ी 'खेलों इंडिया गेम्स' में भाग ले चुके हैं। 31 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने 'खेलों इंडिया' तथा राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता को और विस्तारित करते हुए 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए ₹36,441 करोड़ का संयुक्त प्रावधान स्वीकृत किया।

यह उस सोच का विस्तार है जिसमें खेल को केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि युवा शक्ति को राष्ट्रशक्ति में बदलने का साधन माना गया है। आज आवश्यकता है कि गांव-गांव खेल मैदान हों, विद्यालयों में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक हों, प्रतिभाओं की वैज्ञानिक पहचान हो और आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रशिक्षण, पोषण तथा उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ। एक खिलाड़ी का संघर्ष व्यक्तिगत नहीं होता; उसके पीछे परिवार, गाँव और पूरे समाज की आशा होती है।

उत्तर प्रदेश के युवाओं में वह ऊर्जा है जो भारत को खेल महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आवश्यकता केवल इस ऊर्जा को सही दिशा देने की है। आज जब सिरसा का गुलवीर दौड़ता है, तो उसके साथ पूरा उत्तर प्रदेश दौड़ता है, जब इकलौता की पारुल ट्रैक पर उतरती है, तो हजारों बेटियों के सपने दौड़ने लगते हैं। जब कालिंदा का सौरभ निशाना साधता है, तो देश की उम्मीदें लक्ष्य पर टिक जाती हैं। जब ददूपुर की पूनम भार उठाती है, तो भारतीय नारी की शक्ति विश्व के सामने उठ खड़ी होती है। यही है खेलों में उत्तर प्रदेश के युवाओं की असली कहानी है। मिट्टी से मैदान तक, मैदान से राष्ट्रीय मंच तक और राष्ट्रीय मंच से राष्ट्रमंडल की रोशनी तक। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल शुरुआत है, जहाँ हर गाँव कह सकता है।

"हमारी मिट्टी में केवल अन्न ही नहीं,
विश्व-विजेता भी उगते हैं।"
"खेलेगा युवा-जीतेगा उत्तर प्रदेश,
जीतेगा उत्तर प्रदेश-तो जीतेगा भारत!"

दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। - चंद्रशेखर आजाद

युवा महिला उद्यमी किसी से पीछे नहीं

नवाचार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक कहानियां

सुनीता निगम
लेखिका

'जब एक महिला उद्यमी बनती है, तो वह केवल अपना भविष्य नहीं बदलती, बल्कि परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था के विकास की नई कहानी भी लिखती है।'

भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है इस विकास यात्रा में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, जो कभी केवल कृषि और पारंपरिक उद्योगों के लिए जाना जाता था, आज स्टार्टअप, एमएसएमई (MSME), डिजिटल उद्यमिता और महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों का उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। सरकार की स्टार्टअप नीति, ओडीओपी (One District One Product), मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, स्वयं सहायता समूहों और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने हजारों महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित किया है।

इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत स्थापित उद्यमशीलता विकास प्रकोष्ठ (Entrepreneurship Development Cell-EDC) का उद्देश्य राज्य के चुनिंदा विकासशील उद्यमों को मेंटरशिप, निवेश, बाजार और तकनीकी सहायता प्रदान करना है, इसमें महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

हाल ही में किए गए अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश की महिला उद्यमियों के सामने वित्त, डिजिटल कौशल और बाजार तक पहुंच जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं, लेकिन डिजिटल तकनीक और सरकारी योजनाओं ने उनके लिए नए अवसर के द्वार खोले हैं।

आज की युवा महिला उद्यमी नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाली नेतृत्वकर्ता बन रही हैं।

अदिति गुप्ता (लखनऊ) : सामाजिक उद्यमिता का सफल मॉडल - लखनऊ की युवा उद्यमी अदिति गुप्ता ने महिलाओं के मासिक धर्म (Menstrual Health) जैसे लंबे समय तक उपेक्षित विषय को सामाजिक उद्यमिता से जोड़कर एक नई दिशा दी। उन्होंने डिजिटल प्लेटफार्म, पुस्तकों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से किशोरियों और महिलाओं को वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराई। उनके प्रयासों ने मासिक धर्म से जुड़े मिथकों को चुनौती दी और स्वास्थ्य शिक्षा को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया।

प्रमुख उपलब्धियां

• डिजिटल माध्यम से लाखों लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचाई।

• स्कूलों और कॉलेजों में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए।

• सामाजिक समस्या का समाधान करते हुए एक सफल सामाजिक उद्यम स्थापित किया।

गजल अलग (नोएडा) : डिजिटल स्टार्टअप से राष्ट्रीय पहचान : नोएडा की गजल अलग भारत के प्रसिद्ध स्किनकेयर ब्रांड Mamaearth की सह–संस्थापक हैं। उन्होंने प्राकृतिक उत्पादों और डिजिटल मार्केटिंग को आधार बनाकर एक ऐसा ब्रांड तैयार किया जिसने ई–कॉमर्स की शक्ति का प्रभावी उपयोग किया। कुछ ही वर्षों में उनका स्टार्टअप देश के अग्रणी उपभोक्ता ब्रांडों में शामिल हो गया।

उनकी सफलता यह सिद्ध करती है कि सही उत्पाद, उपभोक्ता की आवश्यकता की समझ और डिजिटल प्लेटफार्म का प्रभावी उपयोग किसी भी युवा उद्यमी को वैश्विक स्तर तक पहुंचा सकता है।

प्रमुख उपलब्धियां

• महिला नेतृत्व वाले भारत के प्रमुख स्टार्टअप्स में स्थान।

• हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन।

• डिजिटल ब्रांडिंग और ई–कॉमर्स का उत्कृष्ट उदाहरण।

वाराणसी की महिला बुनकर और ओडीओपी मॉडल : वाराणसी की बनारसी साड़ी विश्वभर में प्रसिद्ध है। पहले अधिसंख्य महिला कारीगर केवल उत्पादन तक सीमित थीं, लेकिन ओडीओपी (One District One Product) योजना के बाद अनेक युवा महिलाओं ने स्वयं का उद्यम शुरू किया। उन्होंने ई–कॉमर्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों का उपयोग कर अपने उत्पादों को देश–विदेश के ग्राहकों तक पहुंचाया।

प्रमुख उपलब्धियां

• स्थानीय कला को वैश्विक बाजार मिला।

• ग्रामीण महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि।

• स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हुए।

लखनऊ की चिकनकारी महिला उद्यमी : लखनऊ की चिकनकारी केवल हस्तशिल्प नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक युवा महिला उद्यमियों ने पारंपरिक चिकनकारी को आधुनिक डिजाइन, ऑनलाइन बिक्री और सोशल मीडिया प्रचार से जोड़कर सफल व्यवसाय में बदला है।

इन उद्यमियों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षण दिया तथा उन्हें घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराया। आज इनके उत्पाद भारत के साथ–साथ यूरोप, अमेरिका और मध्य–पूर्व के बाजारों तक पहुंच रहे हैं।

प्रमुख उपलब्धियां

• पारंपरिक कला का संरक्षण।

• महिलाओं के लिए स्वरोज़गार।

• ई–कॉमर्स के माध्यम से निर्यात में वृद्धि।

सरकार के प्रयास : उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी स्टार्टअप नीति के माध्यम से युवाओं और विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। राज्य में इनक्यूबेशन सेंटर, नवाचार प्रयोगशालाएं, मेंटरशिप, सीड फंडिंग और निवेशकों से जुड़ने की व्यवस्था विकसित की गई है। महिला उद्यमियों को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

आज नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज

महिला उद्यमियों के समक्ष चुनौतियां

यद्यपि परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, फिर भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं-

- वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच
- निवेश जुटाने में कठिनाई
- सामाजिक रूढ़ियां
- डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता की कमी
- विपणन और ब्रांडिंग का अभाव
- परिवार और व्यवसाय के बीच संतुलन

उत्तर प्रदेश के 160 महिला उद्यमियों पर आधारित एक अध्ययन में वित्तीय संसाधनों, बाजार तक पहुँच, प्रशिक्षण और सामाजिक समर्थन को प्रमुख चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया गया है।

इसी प्रकार डिजिटल नवाचार पर आधारित एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि डिजिटल तकनीक अपनाने से महिला उद्यमियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ी है, लेकिन डिजिटल प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा की समझ को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

जैसे शहर स्टार्टअप हब के रूप में विकसित हो रहे हैं, जहाँ बड़ी संख्या में युवा महिलाएं ई–कॉमर्स, हेल्थ–टेक, एड–टेक, फिन–टेक और एग्री–टेक जैसे क्षेत्रों में सफल उद्यम स्थापित कर रही हैं।

स्टैंड-अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : किसी भी उद्यम की शुरुआत के लिए पूंजी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इस चुनौती को दूर करने के लिए स्टैंड–अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को बिना बड़ी गारंटी के छोटे व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों के माध्यम से महिलाएं अपने व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

इसी प्रकार स्टैंड–अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराती है। इससे हजारों महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर, बुटीक, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, डिजिटल सेवाएं, डेयरी, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र के अनेक व्यवसाय स्थापित किए हैं।

ओडीओपी : स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान : उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की सबसे सफल पहलों में से एक मानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले के पारंपरिक उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना है।

लखनऊ की चिकनकारी, वाराणसी की बनारसी साड़ी, भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल उद्योग, फिरोजाबाद के कांच उत्पाद और अलीगढ़ के ताले जैसे उत्पादों से जुड़ी हजारों महिलाएँ आज स्वरोजगार प्राप्त कर रही हैं। सरकार इन उद्यमियों को डिजाइन विकास, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, गुणवत्ता सुधार, प्रदर्शनियों में भागीदारी और ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने में सहायता प्रदान कर रही है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिला उद्यमियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

डिजिटल इंडिया : महिलाओं के लिए नए अवसर - डिजिटल तकनीक ने महिला उद्यमिता का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से महिलाएं अब अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार सोशल मीडिया, ई–कॉमर्स वेबसाइटों और डिजिटल मार्केटप्लेस पर आसानी से कर रही हैं। यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग, जीएसटी पंजीकरण, ई–मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रशिक्षण ने महिलाओं के लिए व्यवसाय करना पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल बना दिया है।

आज उत्तर प्रदेश की अनेक महिला उद्यमी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सऐप बिजनेस और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री कर रही हैं। इससे उनके ग्राहकों का दायरा स्थानीय बाजार से बढ़कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) : ग्रामीण

क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस मिशन के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित किया जाता है। उन्हें बचत, ऋण, कौशल विकास तथा सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

आज उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवारों की महिलाएं डेयरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उद्योगों से जुड़कर अपनी आय बढ़ा रही हैं। यह मिशन केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देता, बल्कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करता है।

कौशल विकास और बाजार तक पहुंच : राज्य सरकार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग, उत्पाद डिजाइन, वित्तीय प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण और उद्यम प्रबंधन का प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। साथ ही, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और ऑनलाइन मार्केटप्लेस से जोड़कर उनके उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे महिला उद्यमियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ी है। उनके उत्पादों को व्यापक पहचान मिली है।

उत्तर प्रदेश सरकार की स्टार्टअप नीति, ओडीओपी, मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा स्वयं सहायता समूह जैसी पहल ने महिला उद्यमिता को नई दिशा दी है। इन योजनाओं ने महिलाओं को वित्तीय सहायता, कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, बाजार और आत्मविश्वास प्रदान किया है। परिणामस्वरूप, प्रदेश की हजारों महिलाएं आज रोजगार मांगने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली उद्यमी बन रही हैं।

उत्तर प्रदेश की युवा महिला उद्यमियों की सफलता यह सिद्ध करती है कि अवसर, प्रशिक्षण, तकनीक और दृढ़ इच्छाशक्ति मिल जाए तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व कर सकती हैं। अदिति गुप्ता, गजल अलग, वाराणसी की महिला बुनकरों और लखनऊ की चिकनकारी उद्यमियों जैसी प्रेरक कहानियां बताती हैं कि उद्यमिता केवल आर्थिक प्रगति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक युवतियां नवाचार, डिजिटल तकनीक और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाएं। यदि सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और समाज मिलकर सहयोग करें, तो उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में महिला उद्यमिता का राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक मॉडल बन सकता है।

भविष्य की संभावनाएं

उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। राज्य सरकार उद्यमियों को निवेश, मेंटरशिप, बाजार, निर्यात और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार नए कार्यक्रम चला रही है। इससे महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप और एमएसएमई को भी नए अवसर मिल रहे हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान, सोशल कॉमर्स और वैश्विक ऑनलाइन मार्केटप्लेस के कारण उत्तर प्रदेश की महिला उद्यमियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है।

युवाओं में राष्ट्र को बदलने की शक्ति होती। - सरदार वल्लभभाई पटेल

पर्यावरण संरक्षण : अभियान नहीं, जनांदोलन

प्रकाश श्रीवास्तव
पर्यावरणविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता

जहां है हरियाली, वहां है खुशहाली।

छुट्टियां, हम सभी इस शब्द का अर्थ जानते हैं, लेकिन क्या कभी हमने इसके पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश की है? कभी मन में आया कि हमें छुट्टियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली और अन्य बड़े शहरों के लोगों के बीच एक नया चलन दिखाई दिया। लोग अधिक स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण की तलाश में पहाड़ों और जंगलों की ओर जाने लगे। तब क्या कभी यह सवाल मन में आया कि अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए हमें कहीं और क्यों जाना पड़ता है?

छुट्टियां जीवन का विकल्प होनी चाहिए, हमारी जीवनशैली की अनिवार्यता या मजबूरी नहीं। यदि हम 1980 और 1990 के दशक के बीच के समय को देखें तो वर्ष में सामान्यतः एक बार, विशेषकर गर्मियों की छुट्टियों में, लोग घूमने या अपने गांव-घर और रिश्तेदारों के पास जाने निकलते थे। आज सप्ताहांत और विशेषकर 'लॉन्ग वीकेंड' पर बड़ी संख्या में लोग शहरों से बाहर निकलते हैं। पर्यटन और यात्रा के बढ़ते अवसर निश्चित रूप से सकारात्मक हैं, लेकिन इसके साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या हमारे शहरों में ऐसा पर्यावरण उपलब्ध है, जहां लोग प्रतिदिन स्वच्छ हवा, हरियाली, खुले स्थान और प्राकृतिक परिवेश का आनंद ले सकें? इन प्रश्नों के मूल में एक महत्वपूर्ण उत्तर है कि हमने अपने जीवन को प्रकृति से दूर कर लिया है।

हमने लंबे समय तक विकास को पर्यावरण से जोड़कर नहीं देखा। हरे-भरे शहर, नीला आकाश, स्वच्छ नदियां और उपजाऊ मिट्टी किसी पर्यटन स्थल की विशेषता ही नहीं, बल्कि हमारी दैनिक जीवनशैली का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। आज हम छुट्टियों के लिए किसी हरे-भरे स्थान का विकल्प खोज लेते हैं, लेकिन यदि आने वाले समय में वे स्थान भी हमारे बड़े शहरों की तरह प्रदूषित और अनियोजित हो गए तो हम कहां जाएंगे?

इसलिए पर्यावरण संरक्षण कोई विकल्प नहीं, बल्कि हम सभी के भविष्य का प्रश्न है। यदि हवा स्वच्छ नहीं होगी, जल स्रोत सुरक्षित नहीं होंगे और मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होगी, तो विकास की उपलब्धियां भी हमारे जीवन की गुणवत्ता को सुरक्षित नहीं रख पाएंगी। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य की बड़ी युवा आबादी यदि पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो यह परिवर्तन केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकता है।

पौधरोपण से संरक्षण तक : उत्तर प्रदेश में पौधरोपण महाअभियान, 'एक पेड़ माँ के नाम' और मिशन लाइफ (LiFE) जैसी पहल के माध्यम से युवाओं को पौधरोपण, पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2026 में 'एक पेड़ माँ के नाम' पौधरोपण महायज्ञ-2026 की शुरुआत की।

पर्यावरण संरक्षण की वास्तविक सफलता केवल पौधा लगाने में नहीं, बल्कि उसके जीवित रहने और विकसित होने में है। इसलिए शैक्षणिक संस्थानों और युवा संगठनों को पौधरोपण के साथ सिंचाई, गुड़ाई, पौधों की निगरानी और संरक्षण का प्रशिक्षण भी देना आवश्यक है। युवाओं को यह समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी पौधा लगाने के साथ समाप्त नहीं होती; उसकी देखभाल और संरक्षण भी वर्षों की जिम्मेदारी है।

'मिशन 10,000 पेड़' से सामुदायिक भागीदारी : उत्तर प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ इनिशिएटिव के 'मिशन 10,000 पेड़' जैसे तीन वर्षीय अभियान भी युवाओं को सामूहिक भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे अभियानों में केवल एक ही प्रजाति के पौधों पर निर्भर रहने के बजाय नीम, सागौन, अंजीर, महुआ, आम और जामुन जैसे स्थानीय एवं उपयोगी पौधों के रोपण और संरक्षण पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार के प्रयास पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम न बनाकर समुदाय और युवाओं की साझा जिम्मेदारी में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

गंगा और युवा : नदी के साथ हरियाली की माला - गंगा नदी उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा है। अपने लगभग 2,525 किलोमीटर के संपूर्ण प्रवाह में गंगा उत्तर प्रदेश में लगभग 1,140 किलोमीटर बहती है। ऐसे में नदी और उसके तटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

गंगा किनारे स्थानीय प्रजातियों–नीम, पीपल, बरगद, अर्जुन और शीशम के वृक्षों की हरित पट्टी विकसित करने के प्रयास नदी के तटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। ऐसे अभियानों को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को पौधे गोद लेने, उनकी देखभाल करने और उनके विकास की निगरानी से जोड़ा जाना उपयोगी होगा।

बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का हरित आवरण : भारतीय वन सर्वेक्षण की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 2021 के 23,437.53 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 23,996.72 वर्ग किलोमीटर हो गया। यानी इसमें 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। 2023 में यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.96 प्रतिशत था। इसी अवधि में उत्तर प्रदेश का वन आवरण 14,927.37 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 15,045.80 वर्ग किलोमीटर हुआ, जबकि वृक्ष आवरण 8,510.16 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 8,950.92 वर्ग किलोमीटर हो गया।

यह वृद्धि उत्साहजनक है, लेकिन इसे केवल पौधरोपण की संख्या के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। पौधों की जीवित रहने की दर, स्थानीय प्रजातियों का चयन, संरक्षण और दीर्घकालीन निगरानी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसमें युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

स्कूलों से पर्यावरण चेतना की नई शुरुआत : जुलाई 2026 में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत विद्यालयों की भागीदारी भी सामने आई। ऐसे अभियानों की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल लगाए गए पौधों की संख्या नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी का विकास है।

उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में ईको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ (LiFE) पर्यावरणीय चेतना के महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहे हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थी जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, प्लास्टिक नियंत्रण और पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं।

यदि विद्यालय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर व्यवहार से जोड़ा जाए, तो इसका प्रभाव विद्यार्थियों के परिवार और समुदाय तक भी पहुंच सकता है।

'ग्रीन चौपाल' से गांवों तक हरियाली : इसी श्रृंखला में ग्रीन चौपाल जैसी पहल ग्रामीण समाज में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ाने के साथ ग्रामीण समुदाय को पर्यावरण–अनुकूल गतिविधियों से जोड़ना है। गांवों के युवाओं को जैविक खेती, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जोड़ना विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। ग्रामीण युवा यदि पर्यावरण संरक्षण को स्थानीय रोजगार और उद्यमिता से जोड़ें तो हरित विकास की संभावनाएं और मजबूत होंगी।

गंगा उत्सव, गंगा शपथ, रिवेराथॉन, नदी स्वच्छता अभियान, गंगा क्वेस्ट, प्लास्टिक–फ्री कैंपस, प्लास्टिक–फ्री अवेयरनेस कैंपेन, स्वच्छता ही सेवा जैसे अभियानों और राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है–यदि इन प्रयासों को वास्तव में व्यापक जनआंदोलन बनाना है तो युवाओं को केवल सहभागी नहीं, बल्कि प्रेरक और नेतृत्वकर्ता बनना होगा।

युवाओं को पर्यावरण संरक्षण को किसी सरकारी अभियान या एक दिन की गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन की कहानी के रूप में स्वीकार करना होगा। एक पौधा लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना, ऊर्जा की बचत करना और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करना ऐसे छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।

डिजिटल युवा, हरित भविष्य : उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति के पास सोशल मीडिया, तकनीक, नवाचार और संगठन क्षमता जैसी ताकतें हैं। यदि इन क्षमताओं को पर्यावरण संरक्षण से व्यापक रूप से जोड़ा जाए तो एक नई डिजिटल पर्यावरण क्रांति की शुरुआत हो सकती है।

युवा सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं को सामने ला सकते हैं, पौधों की निगरानी के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जल संरक्षण अभियानों को जनभागीदारी से जोड़ सकते हैं और पर्यावरण–अनुकूल जीवनशैली को लोकप्रिय बना सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी के पास वह क्षमता है कि वह किसी स्थानीय पर्यावरणीय पहल को कुछ ही समय में हजारों लोगों तक पहुंचा सकती है। आवश्यकता केवल सही दिशा और जिम्मेदार डिजिटल नेतृत्व की है।

भविष्य वही, जो प्रकृति के साथ हो : हमें ऐसा विकास चाहिए जिसमें आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण एक–दूसरे के विरोधी न हों। हमें ऐसे शहर चाहिए जहां स्वच्छ हवा और हरियाली सामान्य जीवन का हिस्सा हो। हमें ऐसी नदियां चाहिए जिनका पानी केवल तस्वीरों में नहीं, वास्तविक जीवन में भी स्वच्छ हो। हमें ऐसी मिट्टी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।

यदि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर लेती है तो आने वाला समय निश्चित रूप से अधिक हरित और सुरक्षित हो सकता है। तब वह नीला आसमान, वही स्वच्छ और निर्मल पानी और वही शुद्ध हवा हमारी तलाश का विषय नहीं होंगे। हमें स्वच्छ हवा के लिए पहाड़ों की ओर भागने या प्रकृति के लिए किसी 'लॉन्ग वीकेंड' की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होगी।

पर्यावरण संरक्षण हमारा भविष्य है और पर्यावरण संरक्षण में ही हमारा भविष्य है। अब यह कोई विकल्प मात्र नहीं, बल्कि एक अनिवार्य जिम्मेदारी बन चुका है।

देश का भविष्य उसके नागरिकों के चरित्र पर निर्भर करता है।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद

सनातक सांस्कृतिक विरासत का अविरल प्रवाह

प्रो. ओम प्रकाश सिंह
पूर्व निदेशक एवं प्रोफेसर, महामना मालवीय पत्रकारिता संस्थान

जहां प्रत्यक्षतः गंगा और यमुना का संगम होता है, अन्तः सलिला सरस्वती के मिलन के कारण इस स्थान का नाम त्रिवेणी है, इस तीर्थ का नाम प्रयाग है। प्रयागराज की इसी पावन धरती पर 2025 में महाकुंभ का आयोजन हुआ। महाकुंभ 2025 मुख्य रूप से दो स्तम्भों पर आधारित था – एक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा दूसरा युवा सेवा एवं आधुनिक तकनीक के माध्यम से युवा भागीदारी। उक्त दोनों की दृष्टि से महाकुंभ सार्थक रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 66 करोड़ स्नानार्थी इस अमृत स्नान के सहभागी रहे। 45 दिन तक चले उक्त महाकुंभ पूर्व के आयोजनों से भिन्न नजर आया।

सांस्कृतिक विरासत: महाकुंभ–प्रयागराज–2025 में कुछ नवीन प्रयोग भी हुए। उन नवीन प्रयोगों की जानकारी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश शासन ने पहली बार 120 दिनों अर्थात् चार महीने के लिए महाकुंभ मेला नामक जिले का निर्माण किया। प्रयागराज जिले की चार तहसीलों के कुल 67 गांव इसमें शामिल थे। सदर तहसील के 25 गांव, सोरांव तहसील के 03 गांव, फूलपुर तहसील के 20 और करछना तहसील के 19 गांव शामिल थे। कुंभ के इतिहास में यह नयी व्यवस्था जुड़ी। इस कारण यह संदर्भ विशेष है।

कुंभ का सम्बंध लौकिक के स्थान पर पारलौकिक अधिक है। इस परम्परा का शुभारम्भ दैवीय घटना क्रम से जुड़ा है। कहा जाता है कि देव और असुरों ने मिलकर जब समुद्रमंथन किया तो उससे अमृत कलश निकला, उसी अमृत कलश को लेकर हुए संघर्ष में कुछ अमृत बूंदें धरती पर स्थित भारतभूमि के चार स्थानों पर गिरीं। ये स्थान थे – प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक। इन स्थानों पर प्रत्येक बारह वर्ष के अन्तराल पर कुंभ मेल का आयोजन होता है। यह परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है।

इस प्रकार प्रयाग में धार्मिक मेला कुंभ की परंपरा अति प्राचीन है। इसका वर्णन पुराणों में है। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्रीरामचरितमानस में भी इसका उल्लेख इस प्रकार है–

वैसे तो कुंभ अथवा महाकुंभ को सामान्य रूप में स्नान पर्व के रूप में देखा जाता है। लेकिन महाकुंभ का आयोजन सिर्फ कुंभ स्नान तक ही नहीं सीमित है। इतना अवश्य है कि मुख्य पर्वों पर होने वाले स्नान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस कारण यह स्नान पर्व के रूप में दिखाई पड़ता है। महाकुंभ 2025 में कुंभ क्षेत्र के अंदर विविध प्रकार के आयोजनों ने हमारी संस्कृति विरासत को नवीन रूप देते हुए नयी पीढ़ी तक पहुंचाया।

कुंभ मेले की महत्ता और इसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में मानने की दृष्टि सिर्फ सनातन की नहीं है, वरन् यूनेस्को की भी है। यूनेस्को ने दिसम्बर 2017 में दक्षिण कोरिया के जूजू द्वीप में आयोजित यूनेस्को की अंतर–सरकारी समिति के 12 सत्र में कुंभ को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। इसे मानवता की अमूर्त विरासत का दर्जा दिया गया। यूनेस्को ने इसे पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा माना, जो बिना किसी भेदभाव के सामूहिक सद्भाव, सहिष्णुता और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देता है।

इस प्रकार यूनेस्को द्वारा कुम्भ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा देने के बाद पहली बार महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ। इसमें सांस्कृतिक विरासत से जुड़े आयोजन एवं प्रदर्शनियां मुख्य थीं।

महाकुंभ – 2025 में स्नान एक कार्यक्रम था। लेकिन महाकुंभ जिला क्षेत्र में निवास करने वाले अखाड़ों, कल्पवासियों, संन्यासियों, साधुओं और विभिन्न सम्प्रदायों के प्रमुखों आदि द्वारा बनाये गए निवास क्षेत्रों में यज्ञ, कीर्तन, भजन, पूजन, भंडारे आदि के आयोजनों में भारत की सनातन संस्कृति नवीन रूप में प्रस्तुत हो रही थीं।

महाकुंभ मेला क्षेत्र के कला ग्राम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा सेक्टर 7 में 12 ज्योर्तिलिंग के आकार में भव्य कलाग्राम स्थापित था। इसी के साथ–साथ 7 सांस्कृतिक आंगन भी बनाए गए थे। ये सभी पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर, कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर की थीम पर आधारित थे। वहां असम के बांस शिल्प, बंगाल की पेंटिंग, तमिलनाडु की पेंटिंग के साथ–साथ लगभग 230 प्रमुख शिल्पकारों ने अपने शिल्प का प्रदर्शन किया था।

माघ मकरगत रवि जब होई। तीरथपतिहिं आव सब कोई।।
देव दनुज किंनर नर श्रेणी। सादर मज्जहिहं सकल त्रिवेणी।।

यह वर्णन श्रीरामचरितमानस के बालकांड में है। इससे स्पष्ट है कि माघ महीने में मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ परम्परागत आस्था का मेला प्रारम्भ होता है। इस समय त्रिवेणी में स्नान के लिए देव, दनुज, किन्नर आदि तीरथपति प्रयाग आते हैं। इस पवित्र क्षेत्र में कल्पवास की भी परम्परा है। गृहस्थ एवं संन्यासी कल्पवास करते हैं। पद्म पुराण एवं ब्रह्म पुराण के अनुसार यह कल्पवास पौष मास की शुक्ल एकादशी से माघ मास की शुक्ल एकादशी तक चलता है। कल्पवास कुंभ की सांस्कृतिक विरासत का भाग है।

तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी क्षेत्र में कल्पवास की परम्परा कुंभ के सनातन प्रवाह का भाग है। यह सनातन संस्कृति का आधार है। प्राप्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि महाकुंभ मेले में अखाड़ों की संख्या के बाद दूसरी बड़ी संख्या कल्पवासियों की ही थी। कल्पवास सांस्कृतिक विरासत का ही भाग है। पद्म पुराण के अनुसार महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के 21 नियमों का उल्लेख किया है। इन नियमों में – सत्यवचन, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, दया, ब्रह्मचर्य, व्यसन त्याग, सूर्योदय से पूर्व सैय्या त्याग, तीन बार सुरसरि स्नान, त्रिकाल संध्या, पितरों को पिंडदान, मौन जप, सत्संग, क्षेत्र संन्यास, परनिन्दा त्याग, साधु–संत सेवा, संकीर्तन, एक समय भोजन, भूमि शयन्, अग्निसेवन त्याग एवं दान सम्मिलित है। यह सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है और महाकुंभ 2025 में भी कायम रही।

महाकुंभ 2025 के संस्कृति ग्राम में महाकुंभ के इतिहास, समुद्र मंथन और अमृत कलश की कथा को दर्शाने वाली पौराणिक प्रदर्शनियों के साथ–साथ कुंभ आयोजन के समय खगोलीय रूप में सूर्य, चन्द्रमा एवं बृहस्पति की स्थिति समझाने वाले विशेष स्टाल आकर्षण के केन्द्र थे। इसी क्रम में प्राचील काल में कुंभ मेले में आने वाले चीनी यात्रा ह्वेनसांग और अन्य इतिहासकारों और प्रमुख यात्रियों का यात्रा वृत्तांत भी प्रदर्शित था। महाकुंभ मेले में 'एक जिला एक उत्पाद' प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था।

महाकुंभ मेला 2025 में देश के प्रमुख कलाकारों द्वारा संगीत आदि की प्रस्तुति की गयी। इसमें डोना गांगुली द्वारा ओडिसी नृत्य, डॉ सुब्रमन्यम और कविता कृष्णमूर्ति द्वारा शास्त्रीय संगीत, सुरेश वाडेकर, हरिहरन, शंकर महादेवन और कैलाश खेर द्वारा भजन तथा नृत्यांगना सोनल मानसिंह द्वारा नृत्य की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण का केन्द्र थी।

महाकुंभ मेला जिला क्षेत्र में हिन्दू, सनातन के सभी समुदायों– शैव, वैष्णव एवं शाक्त के पंडाल लगे थे। प्रत्येक सम्प्रदाय के परिसर में आवासीय व्यवस्था के साथ–साथ, उपासना गृह, यज्ञस्थल, सभामंडप, भोजनालय आदि थे। पूरे महाकुंभ जिला क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सम्पूर्ण भारत की संस्कृति इस अस्थायी नगर में एक साथ दिखाई पड़ती थी। इसी के साथ विभिन्न पंडालों में भजन, सत्संग एवं सभाओं का आयोजन हिन्दू सनातन संस्कृति की चर्चा को नये रूप में रेखांकित कर रही थी। इनमें युवकों की उपस्थिति भी अधिक रूप में दिखाई पड़ी। इस प्रकार महाकुंभ 2025 भारत की सनातन सांस्कृतिक विरासत को युगानुरुप व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने वाला प्रमुख आयोजन था। महाकुंभ 2025 को मैंने नजदीक से देखा। उसमें सनातन सांस्कृतिक विरासत का अविरल प्रवाह दिखाई पड़ा। महाकुंभ 2025 में सेवा एवं प्रचार–प्रसार के क्षेत्र में युवकों की भूमिका मुख्य रही। युवाओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्मो का उपयोग कर महाकुंभ 2025 को व्यापक बनाया, जिसके कारण 66 करोड़ लोगों का आगमन में हुआ।

युवाओं का चिरस्मरणीय योगदान

महाकुंभ 2025 के दौरान जो मैंने देखा, उसके आधार पर कह सकता हूं कि महाकुंभ 2025 को सफल बनाने में युवाओं की भूमिका प्रमुख थी। अखाड़ों के साधु–संन्यासियों की सेवा में युवा ही नजर आ रहे थे। नेत्रकुंभ शिविर क्षेत्र में युवा चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे थे। स्नान घाटों की सफाई एवं लोगों की सहायता में एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड के युवा अपनी सेवाऐं दे रहे थे। ड्रोन के माध्यम से नियंत्रण तथा असहायों की सहायता में युवा लगे थे। विभिन्न सम्प्रदायों और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित भंडारों में सर्वत्र युवा व्यवस्था में लगे थे।

चिकित्सा सेवा का कार्य युवा चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा था। रेडक्रास और नर्सिंग सेवा भी युवाओं द्वारा की जा रहीं थीं। वृद्धों को स्नान एवं निःशुल्क व्हील चेयर की सुविधा युवाओं के माध्यम से साकार हुई थी। स्नान के दौरान पुलिस एवं सुरक्षा व्यवस्था में युवा स्काउटस सहयोग कर रहे थे। भूले–बिसरों को अपनों से मिलाने तथा यातायात व्यवस्था नियंत्रण में पुलिस की सहायता में युवा लोग थे।

प्रयागराज महानगर एवं आस–पास के जिलों के युवा स्कूटर, मोटरसाइकिल पर बैठाकर लोगों को महाकुंभ क्षेत्र के किसी भी भाग से त्रिवेणी संगम के समीप तक पहुंचा रहे थे। इतना ही नहीं जिन यात्रियों को बस, ट्रेन अथवा वायुयान पकड़ना था, उनको यातायात में जाम के कारण गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी, उनको गंतव्य तक स्कूटर, मोटरसाइकिल से पहुंचाने का कार्य दिन–रात युवा कर रहे थे। माला–फूल, लकड़ी भोजन सामग्री आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में युवकों की भूमिका प्रमुख थी। रा.स्व. संघ, विश्व हिन्दू परिषद, विद्यार्थी परिषद, भारत सेवा संघ, इस्कान, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी, आदि सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों के युवा महाकुंभ क्षेत्र में स्वच्छता, सेवा, सफाई, भोजन, सहायता आदि में अपनी भूमिका निभा रहे थे।

एक देश की शक्ति उसके युवाओं के उत्साह और आदर्शों में होती है।
- सरोजिनी नायडू

स्वरोजगार की नयी पटकथा

डॉ. सुनील कुमार मिश्र
सह आचार्य, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नई दिल्ली

देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य अब आर्थिक स्तर पर भी नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इस बात का संकेत उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में देखने को मिलता है। आर्थिक विकास की रफ्तार और जीडीपी में तेज बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। कुछ वर्ष पहले तक जिस प्रदेश की बीमारू राज्य के रूप में गिनती होती थी, और कहा जाता था कि यह राज्य रोजगार देने के मामले में कई राज्यों से पीछे है। कभी नौकरी की तलाश में मुंबई-दिल्ली जैसे शहरों की ओर पलायन करने वाले युवा अब अपने गाँव-शहर में ही उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार की नई पटकथा लिख रहे हैं।

विगत एक दशक में इस राज्य का कायाकल्प हो चुका है इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशल नेतृत्व एवं राज्य के युवा शक्ति में उनका निवेश नजर आता है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने अनेक योजनाओं को शुरू किया है जिसके केंद्र में युवा वर्ग है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो अथवा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, युवाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ ही उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कोई भी शिक्षित युवक स्वरोजगार के लिए 25 लाख तक की धनराशि रियायती ब्याज दर के साथ प्राप्त कर सकता है।

2018 में शुरू की गई इस योजना का मूल उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना है जिससे उनको उद्यमशीलता से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस योजना से हजारों युवा जुड़ चुके हैं, अपना उद्यम शुरू करके कई अन्य को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार ने इस योजना को उच्च शिक्षा से मुक्त रखा है और कोई भी हाई स्कूल उत्तीर्ण युवक इस योजना का लाभ ले सकता है। यह योजना ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से पिछड़े युवकों को तेजी से आकर्षित कर रही है, अपेक्षाकृत कम पढ़े-लिखे ग्रामीण युवा भी छोटे-मोटे उद्यम के लिए इस योजना से जुड़ रहे हैं। उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। आने वाले समय में यह योजना उत्तर प्रदेश के युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी ।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान भी युवा स्वावलंबन की दिशा में सकारात्मक परिणाम दे रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के माध्यम से कोई भी युवा नया उद्यम शुरू करने के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके 5 लाख तक की राशि प्राप्त कर सकता है, 3 साल के लिए यह धनराशि ब्याजरहित है। मात्र आठवीं पास कोई भी युवा इस अभियान से जुड़कर कोई भी छोटा उद्यम शुरू कर सकता है। सरकार इस अभियान के माध्यम से कौशल आधारित उन उद्यमों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है जो प्रोत्साहन न मिलने की वजह से या तो हाशिये पर हैं या फिर दम तोड़ चुकी हैं।

सरकार का मानना है कि प्रदेश के युवाओं में कौशल की कमी नहीं है, यदि उन्हें उचित सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाय

तो इससे न सिर्फ कौशल आधारित उद्यमों को नया जीवन मिलेगा अपितु प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी। युवाओं को कौशल आधारित शिक्षण–प्रशिक्षण की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास मिशन युवाओं को कौशल में निपुण बना रहा है जिससे वे बड़े शहरों की कंपनियों में नौकरी की जगह अपना उद्यम शुरू कर रहे हैं। सरकार ने युवा उद्यमी अभियान के माध्यम से प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान से ग्रामीण अंचल में कम पढ़े–लिखे युवा अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा अपितु उनके परिवार एवं प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर को दिया जा रहा प्रोत्साहन रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध हो रहा है जिससे शहरी क्षेत्र में संचालित छोटे उद्यमों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के अत्यंत छोटे उद्यम आकार ले रहे हैं एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्वावलंबन की दिशा में ले जा रही हैं जिसका सर्वाधिक लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं इस बात की पुष्टि भी करती हैं। स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करके सरकार ने महिला उद्यमियों के हाथ को भी मजबूत किया है जो ग्रामीण अंचलों में आर्थिक स्वावलंबन की नई परिभाषा गढ़ रही हैं। सरकारी आंकडें के अनुसार प्रदेश में एक करोड़ 6 लाख से अधिक महिलाएं 9.43 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जो अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने का कार्य कर रही हैं। राज्य में महिला श्रम भागीदारी एक दशक से कम समय में ही 14 प्रतिशत से 36 प्रतिशत के आंकडें को पार कर चुका है जो इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की स्थिति सकारात्मक है।

बेरोजगारी का चक्रव्यूह तोड़ा

सेंटर फॉर मोनिटरिंग इंडियन इकॉनमी की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 3.9 फीसदी है जबकि राष्ट्रीय औसत 7.7 फीसदी है। एक दशक पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 17.5 फीसदी थी। इन आकड़ों से स्पष्ट होता है कि बहुत तेजी से बेरोजगारी के चक्रव्यूह से निकल रहा है।

उपरोक्त आंकडे दर्शाते हैं कि पिछला एक दशक उत्तर प्रदेश के स्वावलंबन की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ ही रोजगार की स्थिति में भी सुधार देखने को मिला है। यह सुधार प्रदेश की बहुआयामी विकास प्रक्रिया को गति प्रदान कर रहा है जिसके केंद्र में प्रदेश का युवा नजर आता है। हम जानते हैं कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक प्रगति एक महत्वपूर्ण घटक है। जब आर्थिक प्रगति रुपी घटक युवाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायक होता है तो यह नये रोजगार सृजित करने का कारक बनता है। महिलाओं की श्रम भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, छोटे उद्यमों को आकार प्रदान करता है; तो निश्चित रूप से इससे सिर्फ आर्थिक सेहत ही नहीं सुधरती है अपितु यह सामाजिक बदलाव का मार्ग भी होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवा स्वावलंबन की दिशा में किया जा रहा प्रयास युवाओं को रोजगार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ ही उद्यमों को मजबूती प्रदान कर रहा है। प्रदेश में छोटी औद्योगिक इकाईयों के माध्यम से नित नये रोजगार सृजित हो रहे हैं। जिससे युवाओं को काम का अवसर प्राप्त हो रहा हैं।

रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी, छोटे उद्यमों की स्थापना, एवं कौशल आधारित योजनाओं के लिए अनुकूल वातावरण; प्रदेश की आर्थिक संरचना में बदलाव कर रहा है। देखा जाय तो प्रदेश के स्वावलंबी युवा सर्वाधिक आबादी वाले इस राज्य को एक संपन्न एवं समृद्ध राज्य बनाने में अपना योगदान देते हुए नजर आते हैं, ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश सरकार युवाशक्ति के रूप में देश में उपलब्ध सर्वाधिक मानव संसाधन को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के साथ ही उन्हें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करे जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक समृद्ध राज्य बन सके।

यौवन केवल आयु का विषय नहीं है, बल्कि यह मानसिक दृष्टिकोण का विषय है। हमारे देश में युवाओं की एक विशाल शक्ति है, जो आयु और मानसिकता दोनों दृष्टियों से युवा है। - के.एस.सुदर्शन

परम्परा और नयी सोच साथ-साथ

आभांशु द्विवेदी
मीडिया छात्र, आईएमएस, गाजियाबाद

जब कोई युवा उत्तर प्रदेश से अपना स्टार्टअप शुरू करता है, जब किसी गांव का कारीगर अपने उत्पाद को देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचाता है, जब कोई युवती अपने छोटे से उद्यम से कई लोगों को रोजगार देती है, या जब कोई युवा अपनी ग्राम सभा में विकास की नई सोच लेकर आता है, तब केवल एक व्यक्ति सफल नहीं होता, बल्कि पूरा प्रदेश आगे बढ़ता है।

आज उत्तर प्रदेश के युवा हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। स्टार्टअप से लेकर खेल तक, तकनीक से लेकर पारंपरिक उद्योगों तक, सामाजिक नेतृत्व से लेकर स्थानीय शासन तक, उनकी उपलब्धियां यह साबित कर रही हैं कि बदलाव केवल बड़े शहरों से नहीं, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों से भी शुरू हो सकता है।

बदलाव की असली पहचान : उत्तर प्रदेश के युवाओं की पहचान आज केवल नौकरी खोजने वालों के रूप में नहीं, बल्कि नए अवसर बनाने वालों के रूप में हो रही है। प्रदेश में 22,000 से अधिक DPIIT मान्यता वाले स्टार्टअप, 76 मान्यता वाले इनक्यूबेटर और स्टार्टअप के माध्यम से एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार बनाए जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे उद्यमों की है, जिन्हें युवा उद्यमियों ने स्थापित किया है। यह इस बात का संकेत है कि राज्य में नई सोच अब कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित नहीं रही।

इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश आज देश के आगे रहने वाले स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले राज्यों में शामिल है। लगभग 49 प्रतिशत स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों से चलाए जा रहे हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि नई सोच की नई लहर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और अन्य उभरते शहरों तक पहुंच चुकी है।

इन उपलब्धियों के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। लेकिन इन सभी आंकड़ों के पीछे एक साझा शक्ति है। उस पर अक्सर कम चर्चा होती है। वह शक्ति है उत्तर प्रदेश का युवा। आज का युवा केवल अपने लिए भविष्य नहीं बना रहा, बल्कि अपने गांव, अपने शहर और पूरे प्रदेश के विकास की दिशा तय कर रहा है। स्टार्टअप से लेकर स्थानीय उद्योगों तक, आधुनिक तकनीक से लेकर पारंपरिक शिल्प तक, हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

यही आज का बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। एक ऐसा उत्तर प्रदेश, जहां अपने दम पर आगे बढ़ना केवल एक विचार नहीं,

बल्कि युवाओं के नई सोच, नेतृत्व और संकल्प से आकार ले रही है। आने वाले वर्षों में प्रदेश की रोजगार और कमाई से जुड़ा, सामाजिक और तकनीकी प्रगति की सबसे मजबूत नींव यही युवा शक्ति बनने जा रही है।

जब कौशल बनता है अवसर : किसी भी राज्य की प्रगति केवल बड़े उद्योगों से नहीं होती, बल्कि उन युवाओं से होती है जो अपने कौशल के दम पर नए अवसर पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में यही परिवर्तन धीरे-धीरे दिखाई दे रहा है। युवा अब केवल नौकरी की तैयारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वयं रोजगार शुरू करने और स्थानीय संसाधनों को नए बाजारों से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इस परिवर्तन में कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के माध्यम से अब तक 14.13 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि 5.66 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल सर्टिफिकेट देना नहीं, बल्कि उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप युवाओं को तैयार करना है।

इसी प्रकार, जिन युवाओं के पास नया विचार था लेकिन रोजगार और कमाई से जुड़े संसाधनों की कमी थी, उनके लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एक सहायक माध्यम बनी। इस योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण की व्यवस्था है। इसके साथ 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे नए उद्यमियों को शुरुआत करने में सहायता मिलती है।

परंपरा से नई सोच तक का सफर : उत्तर प्रदेश की पहचान केवल आधुनिक उद्योगों से नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध पारंपरिक कला और शिल्प से भी जुड़ी है। लंबे समय तक अनेक पारंपरिक व्यवसाय नई पीढ़ी से दूर होते जा रहे थे। लेकिन आज कई युवा इन्हीं पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स के माध्यम से नई पहचान दे रहे हैं।

इस दिशा में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पहल ने स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस पहल के माध्यम से लाखों कारीगरों और सूक्ष्म उद्यमियों को प्रशिक्षण, टूलकिट, वित्तीय सहायता और मार्केटिंग सहयोग उपलब्ध कराया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि कई पारंपरिक उत्पाद अब वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज कई युवा अपने पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ने की बजाय उसे आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। यह केवल आय बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी प्रयास है। यही अपने दम पर आगे बढ़ने का वास्तविक स्वरूप है, जहां परंपरा और नई सोच साथ-साथ चलते हैं।

जब युवा बनते हैं बदलाव के भागीदार : रोजगार और कमाई से जुड़ा विकास तभी लंबे समय तक टिकने वाला होता है, जब समाज का विकास भी साथ चले। उत्तर प्रदेश के युवा आज केवल बिजनेस शुरू करने वाले लोग नहीं बन रहे, बल्कि अपने गांवों और समुदायों के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कई स्थानों पर युवा स्वच्छता, जल संरक्षण, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर स्थानीय स्तर पर पहल कर रहे हैं। वे केवल

समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिला रहे, बल्कि उनके समाधान का हिस्सा भी बन रहे हैं।

इसी प्रकार, युवक मंगल दल जैसे संगठन खेल, पर्यावरण संरक्षण, आपदा राहत और सामाजिक जागरूकता अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन गतिविधियों से युवाओं में नेतृत्व क्षमता, सामूहिक कार्य और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। ऐसे प्रयास यह दिखाते हैं कि विकास केवल रोजगार और कमाई से जुड़ा प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रक्रिया भी है।

चुनौतियां और आगे की राह : उत्तर प्रदेश के युवाओं ने यह सिद्ध किया है कि अवसर मिलने पर वे परिवर्तन के सबसे बड़े वाहक बन सकते हैं। फिर भी कई चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं की असमान उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तक पहुंच, शुरुआती निवेश की कमी और तेजी से बदलती तकनीकों के अनुरूप निरंतर कौशल विकास जैसी चुनौतियों पर लगातार काम करने की आवश्यकता है। साथ ही, स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्यमों को केवल शुरू करना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाना, नए बाजारों से जोड़ना और नई सोच को बढ़ावा देना भी उतना ही आवश्यक है। शिक्षा संस्थानों, उद्योगों और स्थानीय समुदायों के बीच मजबूत सहयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उत्तर प्रदेश का अपने दम पर आगे बढ़ना केवल योजनाओं या निवेश से तय नहीं होगी। इसकी वास्तविक ताकत वे युवा हैं जो नए विचारों को अवसर में बदल रहे हैं, स्थानीय समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं और अपने कौशल से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। जब युवा नेतृत्व, नई सोच और सामाजिक जिम्मेदारी एक साथ आगे बढ़ते हैं, तभी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सपना मजबूत आधार पर खड़ा होता है।

एक नजर में

- उत्तर प्रदेश में 22,000 से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कार्यरत हैं।
- प्रदेश में 76 स्टार्टअप इनक्यूबेटर नई कंपनियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं।
- स्टार्टअप के जरिए एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बने हैं।
- करीब 49 प्रतिशत स्टार्टअप टियर–2 और टियर–3 शहरों से संचालित हो रहे हैं।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 14.13 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- 5.66 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए ₹10 लाख तक ऋण की सुविधा उपलब्ध है।
- ओडीओपी पहल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

स्रोत : DPIIT, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)

फैक्ट फाइल

22,000+ स्टार्टअप
76 इनक्यूबेटर
एक लाख+ प्रत्यक्ष रोजगार
14.13 लाख+ लोगों को कौशल प्रशिक्षण
5.66 लाख+ लोगों को रोजगार
49: स्टार्टअप छोटे शहरों से
₹25 लाख तक स्वरोजगार ऋण
ओडीओपी से स्थानीय उत्पादों को नया बाजा

देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग और संघर्ष आवश्यक है।
- वीर सावरकर

विरासत का गौरव, नवाचार का संकल्प

अमित शर्मा
पत्रकार एवं शिक्षाविद्

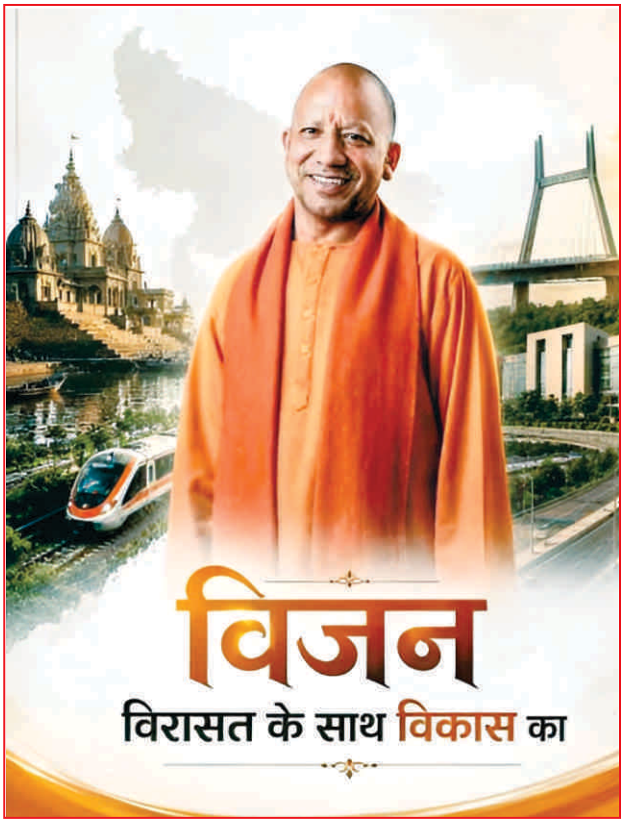

किसी राष्ट्र के युवा उसकी सशक्त ऊर्जा, रचनात्मक क्षमता और भविष्य की संभावनाओं के प्रतिनिधि होते हैं। युवाओं की सोच में नवीनता और कार्यों में उत्साह होता है। उनमें नए बदलावों के साथ चलने का साहस भी होता है। इसलिए किसी राष्ट्र की प्रगति और भविष्य की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी युवा शक्ति कितनी शिक्षित, जागरूक, कुशल और उत्तरदायी है।

भारत विश्व के सर्वाधिक युवा देशों में शामिल है। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे युवा राज्यों में एक है। उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या करीब 30 प्रतिशत है। प्रदेश में युवा आबादी का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से भी करीब 3 प्रतिशत ज्यादा है। देश के विभिन्न राज्यों में उत्तर प्रदेश युवा आबादी के मामले में शीर्ष राज्यों में शामिल है। युवाओं की यह संख्या केवल जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक जागरुकता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की शक्ति भी हैं। राज्य की सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना और राजनीतिक महत्त्व पूरे देश की दिशा को प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के युवाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

राष्ट्र चेतना : अर्थ और स्वरूप - राष्ट्र चेतना का अर्थ केवल देशभक्ति की भावनात्मक अभिव्यक्ति या राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक स्वरुप राष्ट्र के इतिहास, संस्कृति, संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता से निर्मित होता है। राष्ट्र चेतना व्यक्ति को अपने निजी हितों से ऊपर उठकर समाज और देश के व्यापक हित के बारे में सोचने तथा उसमें सक्रिय योगदान देने की प्रेरणा देती है। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, विविधता का सम्मान, समानता और सार्वजनिक जिम्मेदारी इसके महत्वपूर्ण आधार हैं। एक जागरूक युवा राष्ट्र की प्रगति को केवल सरकार का दायित्व नहीं मानता, बल्कि स्वयं को भी उसका सहभागी समझता है। इसलिए युवा राष्ट्र चेतना को केवल नारों या प्रतीकों तक सीमित रखने के बजाय अपने व्यवहार, विचार, कार्य और सामाजिक योगदान के माध्यम से साकार कर सकते हैं। यही चेतना उन्हें जिम्मेदार नागरिक और राष्ट्र निर्माण का सक्रिय भागीदार बनाती है।

उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना : उत्तर प्रदेश भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना की प्रमुख कर्मभूमि रहा है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, सारनाथ और कुशीनगर जैसे सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक

डिजिटल युग का युवा

केंद्रों ने भारत की बहुलतावादी विरासत और सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध किया है। स्वतंत्रता संग्राम में भी इस प्रदेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। 1857 की क्रांति में मेरठ से उठी विद्रोह की चिंगारी और काकोरी आंदोलन जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रम राष्ट्रीय संघर्ष के प्रेरक अध्याय हैं। रानी लक्ष्मी बाई, मंगल पांडे जैसे सेनानियों से लेकर चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों का बलिदान साहस और त्याग का संदेश देता है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय और प्रो. राजेंद्र सिंह 'रज्जू भैया' जैसे राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्तित्वों ने सामाजिक सेवा और राष्ट्रीय चेतना के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश की यह बहुआयामी ऐतिहासिक विरासत आज के युवाओं में सांस्कृतिक आत्मबोध, राष्ट्रीय गौरव और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करती है।

शिक्षा और युवा राष्ट्र चेतना : शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन या रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे जिम्मेदार, संवेदनशील और जागरूक नागरिक तैयार करना भी है, जो राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझें। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को संवैधानिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रीय एकता की भावना से परिचित कराना आवश्यक है। साथ ही, युवाओं को भारत के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और प्रेरक राष्ट्रीय परंपराओं का ज्ञान देते हुए उनमें तार्किक, विवेकपूर्ण और आलोचनात्मक सोच विकसित की जानी चाहिए। जब शिक्षा ज्ञान को संस्कार, कौशल को संवेदना और व्यक्तिगत सफलता को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ती है, तब वह सच्चे अर्थों में राष्ट्र चेतना का निर्माण करती है। ऐसे शिक्षित और जागरूक युवा लोकतंत्र तथा सशक्त राष्ट्र निर्माण की मजबूत आधारशिला बन सकते है।

कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भर युवा : आज के बदलते आर्थिक और तकनीकी परिवेश में केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है; युवाओं को नवाचार, तकनीक, व्यावसायिक दक्षता और उद्यमिता से भी जोड़ना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में कृषि, हस्तशिल्प, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं, विनिर्माण तथा स्थानीय उद्योगों के क्षेत्र में युवाओं के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। युवा केवल रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि अपने ज्ञान, कौशल और उद्यमशीलता के माध्यम से नए अवसर तथा रोजगार सृजित करने वाले भी बन सकते हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर युवा आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान देता है।

डिजिटल युग का युवा : डिजिटल युग ने युवाओं के लिए

ज्ञान, संवाद, नवाचार और सामाजिक भागीदारी के नए अवसर खोले हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से आज का युवा न केवल देश–दुनिया की घटनाओं से शीघ्र जुड़ता है, बल्कि अपने विचारों, प्रतिभा और सामाजिक सरोकारों को व्यापक मंच भी प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के युवा डिजिटल माध्यमों के जरिए स्थानीय संस्कृति, लोककला, पर्यटन, हस्तशिल्प और उद्यमों को राष्ट्रीय तथा वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। किंतु इस तकनीकी विस्तार के साथ फेक न्यूज, भ्रामक सूचनाएं, ऑनलाइन कट्टरता, साइबर अपराध और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसलिए डिजिटल साक्षरता, तथ्य–जांच और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार आज की राष्ट्र चेतना के आवश्यक अंग हैं। तकनीक का विवेकपूर्ण और सकारात्मक उपयोग युवा शक्ति को ज्ञान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की प्रभावी शक्ति में बदल सकता है।

स्थानीय विरासत, नवाचार और युवा उद्यमिता : उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और स्थानीय उद्योग युवाओं के लिए रोजगार तथा उद्यमिता की व्यापक संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। बनारसी साड़ी, लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद का पीतल शिल्प, भदोही के कालीन और फिरोजाबाद के कांच उद्योग जैसे उत्पाद प्रदेश की विशिष्ट पहचान हैं। आज का युवा आधुनिक तकनीक, डिजिटल विपणन और नवाचार के माध्यम से इन पारंपरिक उत्पादों को नए बाजारों से जोड़ सकता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ–साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी संभव होगा। युवा शक्ति 'स्थानीय से वैश्विक' की यात्रा को नई गति दे सकती है।

लोकतंत्र, सामाजिक समरसता और नागरिक जिम्मेदारी : राष्ट्र चेतना का एक महत्वपूर्ण आधार लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था और समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक भागीदारी है। युवा केवल राष्ट्र के भविष्य नहीं, बल्कि उसके वर्तमान के सक्रिय सहभागी भी हैं। इसलिए उन्हें मतदान, सार्वजनिक विमर्श, सामाजिक अभियानों और स्थानीय समस्याओं के समाधान में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विविधताओं से समृद्ध उत्तर प्रदेश में जाति, भाषा, क्षेत्र और आस्था की भिन्नताओं को विभाजन का कारण नहीं, बल्कि सामाजिक शक्ति के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। सामाजिक समरसता, परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाती है। एक जागरूक युवा अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ–साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से निर्वहन करता है। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्य भी राष्ट्र सेवा के व्यावहारिक रूप हैं। जब युवा व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के व्यापक हित में सक्रिय होते हैं, तभी राष्ट्र चेतना व्यवहार में साकार होती है।

युवा चेतना से सशक्त राष्ट्र : उत्तर प्रदेश का युवा केवल प्रदेश की जनसांख्यिकीय शक्ति नहीं, बल्कि भारत की वर्तमान ऊर्जा और भविष्य की संभावनाओं का प्रतिनिधि है। उसकी राष्ट्र चेतना को केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति या नारों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसका वास्तविक स्वरूप शिक्षा, कौशल, सांस्कृतिक आत्मबोध, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक भागीदारी और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व में प्रकट होता है। आज आवश्यकता है कि युवाओं को अपनी ऐतिहासिक विरासत से जोड़ते हुए उन्हें आधुनिक ज्ञान, तकनीक और नवाचार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। जब युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को व्यक्तिगत सफलता के साथ समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हित से जोड़ता है, तब वह परिवर्तन की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन जाता है। जागरूक, शिक्षित, आत्मनिर्भर और संस्कारवान युवा शक्ति प्रदेश के साथ–साथ एक सशक्त, समरस तथा विकसित भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला बनती है। युवा चेतना का यही जागरण राष्ट्र चेतना को नई ऊर्जा और भविष्य को नई दिशा प्रदान कर सकता है।

शिक्षा ही समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है।
-ईश्वरचंद्र विद्यासागर

परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन

डॉ. आनंद प्रकाश श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तर प्रदेश, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ही नहीं, अपितु सर्वाधिक युवा आबादी वाला राज्य भी है। यह प्रदेश-भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म और साहित्य की जीवंत धुरी भी है। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर और लखनऊ से आगरा तक फैली इसकी सांस्कृतिक चेतना हजारों वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा का प्रतिफल है। इस पावन भूमि के वातावरण में वेदों की ऋचाएं घुली हुई हैं, तो यहां राम और कृष्ण की लीलाएं भी जीवंत हैं। इस धरती ने बुद्ध, महावीर और गुरू गोरक्षनाथ के संदेशों को आत्मसात किया तो कबीर, तुलसीदास, सूरदास, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, फिराक गोरखपुरी, बिस्मिल्लाह खान, बिरजू महाराज, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और लोक गायिका मालिनी अवस्थी जैसी प्रसिद्ध शख्सियतों की जन्मस्थली भी यही है। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकउल्ला खां के बलिदान की कहानियां भी यहां घर-घर में सुनी-सुनाई जाती हैं।

"जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है" आज यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि सौ फीसदी हकीकत लगता है। शायद इसीलिए आज जब भूमंडलीकरण, डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का दौर, नौजवान होती पीढ़ी की सोच और जीवनशैली को तेजी से बदल रहा है, तब यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है? या वह आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है? यह सवाल केवल संस्कृति का नहीं, बल्कि आने वाले दौर के भारत की पहचान का भी है।

सोलहवीं सदी में महाकवि तुलसीदास ने "रामचरितमानस" में लिखा – "परहित सरिस धरम नहिं भाई। परपीड़ा सम नहिं अधमाई।।" यह केवल धार्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के मूल जीवन-मूल्यों- सेवा, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश है। लगभग छह सौ साल बाद भी यही मूल्य आज के युवाओं के चरित्र निर्माण की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत बहुआयामी है। यहां गंगा-जमुनी तहजीब, कथक नृत्य, बनारसी संगीत परंपरा, लखनऊ की नवाबी संस्कृति, ब्रज की रासलीला, अयोध्या की रामलीला, प्रयागराज का महाकुंभ, वाराणसी की आध्यात्मिक परंपरा और आगरा की स्थापत्य कला एक साथ मिलकर भारतीय संस्कृति का विराट स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। प्रदेश की भाषाई विविधता हिंदी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी

और उर्दू इस सांस्कृतिक संपदा को और समृद्ध बनाती है।

डिजिटल युग में उत्तर प्रदेश का युवा अभूतपूर्व अवसरों के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खेल, मीडिया और उद्यमिता के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी राज्य को नई पहचान दिला रही है। सोशल मीडिया ने बेशक उन्हें वैश्विक मंच दिया है, किंतु यही माध्यम उनकी सांस्कृतिक चेतना की परीक्षा भी ले रहा है। यदि डिजिटल मंचों का उपयोग केवल मनोरंजन तक सीमित रहे, तो विरासत से दूरी बढ़ेगी; जबकि यदि इन्हीं माध्यमों से लोककला, लोकभाषा, पारंपरिक संगीत और ऐतिहासिक धरोहरों का प्रचार–प्रसार किया जाए, तो यही तकनीक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम बन सकती है।

आज बहुत से युवा बनारसी बुनकरों, चिकनकारी, जरी–जरदोजी, टेराकोटा, काष्ठ शिल्प और स्थानीय उत्पादों को डिजिटल मंचों पर वैश्विक पहचान दिला रहे हैं। यह केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण का भी आधुनिक स्वरूप है। इसी दौर में क्षेत्रीय और स्थानीय पहचान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार भी 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) जैसी योजना चला रही है।

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था–"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।" यह पंक्ति आज भी उतनी ही सार्थक और प्रासंगिक है। यदि उत्तर प्रदेश का युवा अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोलियों से दूर हो जाएगा, तो वह अपनी सांस्कृतिक स्मृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देगा। निश्चित तौर पर अंग्रेज़ी और वैश्विक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन अपनी भाषा से आत्मीय संबंध बनाए रखना सांस्कृतिक आत्मविश्वास की पहली शर्त है।

संस्कृत साहित्य में भी कहा गया है– "विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते।।" तात्पर्य यह कि एक विद्वान और एक राजा की कभी तुलना नहीं की जा सकती। राजा केवल अपने ही देश में पूजा जाता है, जबकि विद्वान व्यक्ति को सभी जगह सम्मान मिलता है। यानी ज्ञान बहुत ज़रूरी है और वह बिना शिक्षा के संभव नहीं है। लेकिन यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति की नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया को भी रेखांकित करती है। प्रदेश के युवा यदि इस मूल्य–श्रृंखला को आत्मसात करें, तो वे आधुनिकता और परंपरा का संतुलित समन्वय स्थापित कर सकते हैं।

आज राज्य में युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए लगातार नई पहल की जा रही है। कॉलेजों में सांस्कृतिक क्लब, युवा सांस्कृतिक दूत और भजन क्लबिंग जैसी योजनाएं तथा विरासत संरक्षण संबंधी कार्यक्रम युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को स्थानीय रोजगार तथा आर्थिक विकास से जोड़ने की दिशा में भी कार्य हो रहा है।

हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति, त्वरित मनोरंजन, पश्चिमी जीवनशैली की अंधानुकरण प्रवृत्ति, लोक भाषाओं का घटता प्रयोग और पारंपरिक कलाओं के प्रति लगातार कम होती रुचि के कारण सांस्कृतिक संरक्षण के सामने गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। यदि नई पीढ़ी अपने इतिहास, साहित्य और सांस्कृतिक

प्रतीकों से अपरिचित रह जाएगी, तो भविष्य की सांस्कृतिक निरंतरता कमजोर हो सकती है।

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक शक्ति केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की संभावना भी है। धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, लोक कलाओं का संरक्षण, पारंपरिक शिल्प का डिजिटलीकरण और सांस्कृतिक उद्यमिता राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे सकते हैं। पिछले दिनों संपन्न हुआ प्रयाग महाकुंभ इसका शानदार उदाहरण है। प्रदेश को सांस्कृतिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

“हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी।“ पिछली सदी के शुरुआती दशक में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त रचित “भारत भारती” की ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक हैं। प्रदेश के नौजवानों को इस पर चिंतन-मनन करना चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि सांस्कृतिक विरासत केवल स्मारकों, मंदिरों, मस्जिदों, किलों या संग्रहालयों में सुरक्षित नहीं रहती; वह हमारे व्यवहार, भाषा, साहित्य, संगीत, उत्सव, त्यौहार, परिवार और जीवन-मूल्यों में भी जीवित रहती है। प्रदेश का युवा यदि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सोच और वैश्विक दृष्टि के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी उतना ही सम्मान देगा, तभी वह सच्चे अर्थों में विकसित नागरिक कहलाएगा। आधुनिकता और परंपरा परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे की पूरक हैं। आवश्यकता इस संतुलन को समझने की है।

उत्तर प्रदेश : युवा शक्ति के 8 सूत्र

- देश की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे बड़ी ताकत
- विरासत और विकास का अद्भुत संगम
- ODOP से युवाओं को रोजगार और पहचान
- डिजिटल मंचों से लोक संस्कृति को वैश्विक पहचान
- मातृभाषा ही सांस्कृतिक आत्मविश्वास की नींव
- धार्मिक पर्यटन से नए रोजगार के अवसर
- तकनीक और परंपरा का संतुलन ही भविष्य
- युवा शक्ति से उत्तर प्रदेश बनेगा उत्कृष्ट प्रदेश

साल 1980 में प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक एल्विन टॉफलर ने अपनी किताब “द थर्ड वेव” के जरिए दुनिया के सामने “एम क्यूब” यानी मनी, मसल, माइंड का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने विस्तार से बताया था कि जिसने भी इन तीनों (मनी, मसल, माइंड) में से किसी एक को भी साध लिया, वह दुनिया पर राज करेगा। आज लगभग पांच दशक बाद सूचना क्रांति के इस युग में माइंड यानी ज्ञान ही शक्ति का सबसे परिष्कृत और उच्चतम गुणवत्ता वाला स्वरूप बन गया है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस लिहाज़ से प्रदेश का नौजवान कहीं से कमतर नहीं है। सच कहें तो प्रदेश की युवा शक्ति इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरी है।

युवाओं के हाथों में केवल अपने भविष्य की नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना की भी मशाल है। यदि यह पीढ़ी अपनी विरासत को समझकर आगे बढ़ेगी, तो उत्तर प्रदेश केवल आर्थिक या तकनीकी विकास का ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक नेतृत्व का भी अग्रदूत बनेगा। यही इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ी उम्मीद है।

देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला और सबसे ज्यादा एक्सप्रेस-वे वाला उत्तर प्रदेश आज युवाओं की ताक़त के बूते एक्सप्रेस की रफ्तार से विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब लोग उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदेश के तौर पर जानेंगे।

शिक्षा और विवेक के बिना समाज की प्रगति संभव नहीं।
- राजा राममोहन राय

नवाचार एवं बौद्धिक संपदा में अपार संभावनाएं

डॉ. दीपा त्यागी
विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग
जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नोएडा

आज का समय केवल ज्ञान अर्जित करने का नहीं, बल्कि उस ज्ञान को नए विचारों और उपयोगी समाधानों में बदलने का है। इसी सोच को नवाचार (Innovation) कहा जाता है। जब कोई नया विचार, तकनीक, उत्पाद, प्रक्रिया या समाधान समाज की किसी समस्या को आसान बनाता है, तो वह नवाचार का रूप ले लेता है। वहीं, किसी व्यक्ति के मौलिक विचार, आविष्कार, डिजाइन, लेखन, सॉफ्टवेयर या रचनात्मक कार्य को कानूनी संरक्षण देने वाली व्यवस्था बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) कहलाती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में युवा शक्ति इन दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उत्तर प्रदेश की पहचान केवल अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से नहीं है, बल्कि यहां की युवा प्रतिभा भी इसकी बड़ी ताकत है। गांवों से लेकर महानगरों तक युवा नई तकनीकों को सीख रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और रोजमर्रा की समस्याओं के नए समाधान खोज रहे हैं। आज का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाला भी बन सकता है।

नवाचार की शुरुआत हमेशा किसी बड़ी प्रयोगशाला से नहीं होती। कई बार यह हमारे दैनिक जीवन की छोटी–सी समस्या से जन्म लेता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी को कॉलेज आने–जाने में समय की समस्या होती है और वह स्थानीय विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना देता है, जिससे वे एक–दूसरे के साथ सुरक्षित

रूप से यात्रा साझा कर सकें, तो यह भी एक नवाचार है। इसी तरह कोई युवा किसान मोबाइल आधारित ऐसी व्यवस्था विकसित करता है, जिससे किसान मौसम, मंडी के भाव या सिंचाई की जानकारी समय पर प्राप्त कर सकें, तो यह तकनीक खेती को अधिक प्रभावी बना सकती है।

उत्तर प्रदेश में कृषि का विशेष महत्व है। इसलिए कृषि क्षेत्र में नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। युवा कम लागत वाली सिंचाई तकनीक, मिट्टी की गुणवत्ता जांचने वाले उपकरण, सौर ऊर्जा से चलने वाली मशीनें और फसल की निगरानी करने वाले डिजिटल साधन विकसित कर सकते हैं। मान लीजिए किसी गांव का युवा किसान देखता है कि खेत में पानी जरूरत से अधिक खर्च हो रहा है। वह सेंसर आधारित ऐसी प्रणाली तैयार करता है जो मिट्टी में नमी की मात्रा देखकर केवल आवश्यकता होने पर पानी दे। यह छोटा-सा विचार पानी की बचत के साथ किसान की लागत भी कम कर सकता है।

इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी युवा नवाचार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अनेक विद्यार्थी ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों की पहुंच सीमित है। कोई युवा स्थानीय भाषा में छोटे-छोटे वीडियो बनाकर गणित, विज्ञान या अंग्रेजी को सरल तरीके से समझाने वाला प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है। इससे तकनीक केवल मनोरंजन का माध्यम न रहकर शिक्षा का प्रभावी साधन बन सकती है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और डिजिटल तकनीक युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रही हैं।

लेकिन नवाचार का अर्थ केवल अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करना नहीं है। किसी पुराने काम को अधिक सरल, सस्ता, तेज और पर्यावरण-अनुकूल बनाना भी नवाचार है। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग को देखकर यदि कोई युवा पुनः उपयोग किए जा सकने वाले स्थानीय पदार्थों से पैकेजिंग तैयार करता है, तो यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण नवाचार हो सकता है। यहीं से बौद्धिक संपदा का महत्व सामने आता है। किसी युवा ने कोई नया उत्पाद, तकनीकी समाधान, डिजाइन, लोगो, पुस्तक, कविता, सॉफ्टवेयर या अन्य मौलिक रचना तैयार की है तो उसे अपनी रचना की सुरक्षा के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन अधिकार जैसे माध्यम युवाओं की बौद्धिक मेहनत को पहचान और कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।

एक सामान्य उदाहरण मोबाइल एप का है। यदि कोई युवा विद्यार्थियों के लिए एक नया ऐप विकसित करता है और उसकी तकनीकी कार्यप्रणाली मौलिक है, तो उसे यह समझना चाहिए कि उसके विचार और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है। इसी तरह यदि कोई युवा अपने हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए एक विशिष्ट नाम और लोगो बनाता है और उसे बाजार में एक ब्रांड के रूप में विकसित करता है, तो ट्रेडमार्क उसके ब्रांड की पहचान को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।

बौद्धिक संपदा केवल बड़े उद्योगों या वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास के छोटे उद्यमियों और कारीगरों के पास भी विशिष्ट ज्ञान और रचनात्मकता होती है। उत्तर प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प, वस्त्र, काष्ठकला, पीतल के उत्पाद, चिकनकारी और अन्य स्थानीय कलाओं में पीढ़ियों से चली आ रही विशेष पहचान है। युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे इस पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक बाजार, डिजाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ें, साथ ही उसकी मौलिक पहचान और अधिकारों की रक्षा भी करें।

आज सोशल मीडिया ने युवाओं के लिए अपने विचार दुनिया तक पहुंचाना आसान बना दिया है। लेकिन इसके साथ बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता भी जरूरी है। इंटरनेट पर किसी की तस्वीर, लेख, डिजाइन, वीडियो या संगीत को बिना अनुमति इस्तेमाल करना उचित नहीं है। इसी तरह युवा रचनाकारों को भी अपनी सामग्री के अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। डिजिटल युग में रचनात्मकता के साथ जिम्मेदारी भी आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश के युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए

शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉलेज और विश्वविद्यालय केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित न रहें, बल्कि विद्यार्थियों को समस्या पहचानने, प्रयोग करने और असफलताओं से सीखने के अवसर दें। यदि किसी विद्यार्थी का पहला प्रोजेक्ट सफल नहीं होता, तो उसे असफलता नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझना चाहिए। वास्तव में कई बड़े आविष्कार अनेक प्रयासों और असफल प्रयोगों के बाद सामने आए हैं।

सरकार, विश्वविद्यालय, उद्योग और युवा इन चारों के बीच बेहतर सहयोग से उत्तर प्रदेश नवाचार का मजबूत केंद्र बन सकता है। स्टार्टअप संस्कृति, इनक्यूबेशन सेंटर, पेटेंट सहायता, कौशल विकास और अनुसंधान के अवसर युवाओं को अपने विचारों को वास्तविक उत्पाद और सेवाओं में बदलने में सहायता कर सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और वित्तीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए तो नवाचार का लाभ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा।

नवाचार केवल बड़ी उपलब्धि का नाम नहीं है। किसी घर में बिजली की बचत करने का नया तरीका खोजना, किसान की लागत कम करना, विद्यार्थियों की पढ़ाई आसान बनाना, स्थानीय कारीगर के उत्पाद को डिजिटल बाजार तक पहुंचाना या पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई सरल समाधान विकसित करना ये सभी नवाचार की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण मिसालें हैं।

उत्तर प्रदेश के युवाओं के पास संख्या भी है, प्रतिभा भी और संभावनाएं भी। आवश्यकता केवल सही दिशा, अवसर और बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता की है। यदि युवा अपने विचारों को पहचानें, उन्हें प्रयोग में लाएं और अपनी रचनात्मक मेहनत को कानूनी रूप से सुरक्षित करना सीखें तो वे न केवल अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और नवाचार–प्रधान प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज का विचार ही कल का आविष्कार बन सकता है। जरूरत केवल उसे सोचने, आजमाने और सुरक्षित रखने की है।

उत्तर प्रदेश में युवा नवाचार : प्रमुख बिंदु

- **युवा शक्ति : गांवों से महानगरों तक युवा तकनीक, स्टार्टअप और नए समाधानों के जरिए नई संभावनाएं तलाश रहे हैं**
- **कृषि नवाचार : सेंसर आधारित सिंचाई, मिट्टी जांच, सौर ऊर्जा और डिजिटल फसल निगरानी जैसे क्षेत्रों में बड़ी संभावनाएं**
- **शिक्षा में तकनीक : स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा की पहुंच बढ़ा सकते हैं**
- **नई तकनीकें : एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन और डिजिटल तकनीक युवाओं के लिए नए अवसर खोल रही हैं**
- **बौद्धिक संपदा : पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन अधिकार युवा रचनाकारों और नवोन्मेषकों के काम को कानूनी संरक्षण देते हैं**
- **स्थानीय विरासत : चिकनकारी, पीतल, काष्ठकला, वस्त्र और हस्तशिल्प जैसी पारंपरिक कलाओं को युवा आधुनिक डिजाइन और डिजिटल बाजार से जोड़ सकते हैं**
- **डिजिटल जागरूकता : सोशल मीडिया के दौर में अपनी रचनाओं के अधिकारों और दूसरों की सामग्री के सम्मान के प्रति सजग रहना जरूरी है**
- **नवाचार का आधार : सरकार + विश्वविद्यालय + उद्योग + युवा के बीच सहयोग से उत्तर प्रदेश को मजबूत नवाचार केंद्र बनाया जा सकता है।**
- **मूल मंत्र : 'सोचें - आजमाएं-सुरक्षित रखें'; आज का विचार कल का आविष्कार बन सकता है।**

युवाओं को सही दिशा और मार्गदर्शन मिले तो देश विश्वगुरु बन सकता है। - डॉ. मोहनराव भागवत

विकसित यूपी की नई गाथा

डॉ. अनुपमा भारद्वाज
सामाजिक-सांस्कृतिक मानवशास्त्री

किसी भी राष्ट्र या राज्य का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसकी तिजोरी में कितना धन है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी युवा शक्ति के पास कितनी बड़ी सोच और कितना दृढ़ संकल्प है।

आज का उत्तर प्रदेश एक व्यापक और ऐतिहासिक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह राज्य अब केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपराओं और राजनीतिक महत्त्व के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि अपनी विशाल युवा शक्ति, उद्यमिता, तकनीकी क्षमता और नवाचार के कारण भी नई पहचान बना रहा है। विकसित उत्तर प्रदेश का सपना किसी सरकारी दस्तावेज़ तक सीमित नहीं है; यह प्रदेश के करोड़ों युवाओं की प्रतिभा, परिश्रम, आत्मविश्वास और संकल्प से आकार लेता हुआ एक जीवंत अभियान है।

जनसांख्यिकीय लाभांश - उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति : उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा आबादी है। राज्य की बड़ी जनसंख्या युवा वर्ग की है और यही शक्ति आने वाले वर्षों में प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक दिशा तय करने वाली है। बीते दशकों में उत्तर प्रदेश के युवाओं का बड़े महानगरों की ओर रोजगार के लिए पलायन सामान्य बात थी। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु तथा अन्य शहरों में बेहतर अवसरों की तलाश में बड़ी संख्या में युवा जाते थे। अब यह परिदृश्य धीरे-धीरे बदल रहा है। प्रदेश में उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के विस्तार से स्थानीय स्तर पर अवसर बढ़ रहे हैं। युवाओं की सोच में भी उल्लेखनीय बदलाव आया है। वे अब केवल नौकरी प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि स्वयं उद्यम स्थापित कर दूसरों के लिए रोजगार सृजित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।

डिजिटल क्रांति और तकनीक-सशक्त पीढ़ी : उत्तर प्रदेश का युवा आज वैश्विक तकनीकी परिवर्तनों के साथ तेजी से कदम मिला रहा है। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, डिजिटल शिक्षा और आधुनिक तकनीकों ने शहरों एवं गांवों के बीच की दूरी को कम किया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा उत्तर भारत के प्रमुख तकनीकी और औद्योगिक केंद्र बनकर उभरे हैं। यहां सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों, डेटा सेंटरों, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मोबाइल निर्माण इकाइयों का तेजी से विस्तार हुआ है। इससे प्रदेश के युवाओं को सॉफ्टवेयर विकास, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम

बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और अन्य उच्च–कौशल क्षेत्रों में नए अवसर मिल रहे हैं।

लखनऊ भी तकनीक और नवाचार के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, अनुसंधान और नवीन प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों से प्रदेश के युवाओं के लिए भविष्य के अनेक द्वार खुल रहे हैं।

उद्यमिता की नई लहर : उत्तर प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता को लेकर एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है। पहले जहां अधिकांश युवा सरकारी या सुरक्षित नौकरी को प्राथमिकता देते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में युवा नए विचारों, छोटे उद्योगों और स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

राज्य की स्टार्टअप नीति, वित्तीय सहायता, प्रारंभिक पूंजी और इनक्यूबेशन केंद्रों ने इस वातावरण को और मजबूत किया है। प्रयागराज, कानपुर, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी जैसे शहरों में भी युवा उद्यमी नए व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में भी युवा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से फसलों पर छिड़काव, मिट्टी की डिजिटल जांच, आधुनिक सिंचाई, ऑनलाइन विपणन और किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने जैसी पहलें कृषि को अधिक वैज्ञानिक और लाभकारी बना रही हैं।

शिक्षा और कौशल विकास का आधुनिक ढांचा : विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि युवाओं को केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि रोजगार और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल भी मिले।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, विमानन, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ा रहा है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों का आधुनिकीकरण भी महत्त्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रिक वाहन, रोबोटिक्स, आधुनिक मशीनिंग, स्वचालन और नवीन विनिर्माण तकनीकों में युवाओं को प्रशिक्षित करना उन्हें भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कर रहा है।

औद्योगिक गलियारे और बुनियादी ढांचा : उत्तर प्रदेश में सड़क, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे और औद्योगिक गलियारों के विस्तार ने रोजगार और निवेश की नई संभावनाएं पैदा की हैं।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को तेज परिवहन व्यवस्था से जोड़ा है। इनके आसपास विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं के लिए विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, सेवा और तकनीकी क्षेत्रों में नए रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा भी युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, कानपुर और अन्य केंद्रों पर रक्षा उपकरणों तथा संबंधित उद्योगों के विकास से इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र के युवाओं को अवसर मिल रहे हैं।

खेल, कला और सांस्कृतिक नेतृत्व : एक विकसित राज्य की पहचान केवल आर्थिक समृद्धि से नहीं होती। उसकी सांस्कृतिक चेतना, खेल प्रतिभा और सामाजिक जीवंतता भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण होती है।

उत्तर प्रदेश के युवा खेल के क्षेत्र में लगातार अपनी पहचान बना रहे हैं। बेहतर खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के कारण छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से भी नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। एथलेटिक्स, कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट तथा अन्य खेलों में प्रदेश के युवा उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं।

अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्रों के विकास से पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में भी नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। युवा अब पर्यटक मार्गदर्शक, आयोजन प्रबंधक, डिजिटल सामग्री निर्माता, आतिथ्य विशेषज्ञ और विरासत पर्यटन के पेशेवर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता : युवा सशक्तिकरण तभी सार्थक है, जब युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध हों।

विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं और ऋण सुविधाओं के माध्यम से युवा छोटे उद्योग, सेवा केंद्र, दुकानें और अन्य व्यवसाय प्रारंभ कर पा रहे हैं। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं।

डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय तकनीक के प्रसार ने छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की वित्तीय समझ भी बढ़ाई है। आज युवा बचत, निवेश, उद्यम और आर्थिक नियोजन को पहले की तुलना में अधिक गंभीरता से समझ रहे हैं।

नारी शक्ति : विकास की मजबूत भागीदार : विकसित उत्तर प्रदेश की यात्रा में युवा महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। प्रदेश की बेटियां शिक्षा, प्रशासन, तकनीक, सुरक्षा, उद्योग, खेल, चिकित्सा और उद्यमिता के क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रही हैं।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं छोटे उद्योग, वित्तीय सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और डिजिटल सेवाओं से जुड़ रही हैं। शहरों में युवा महिलाएं तकनीकी कंपनियों, स्टार्टअप, कॉर्पोरेट जगत और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में अपना स्थान बना रही हैं।

महिलाओं की यह बढ़ती भागीदारी विकसित उत्तर प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक आधार को और मजबूत कर रही है।

भविष्य की राह : 2030 और उसके आगे : विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आने वाले वर्षों में युवाओं की भूमिका और अधिक निर्णायक होने वाली है। हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहन, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी प्रदेश को सतत् विकास की दिशा में आगे ले जा सकती है।

जेवर, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या जैसे क्षेत्रों से बढ़ता हवाई संपर्क प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ रहा है। इससे स्थानीय उद्योगों, हस्तशिल्प और तकनीकी सेवाओं को विश्व स्तर पर पहुंचाने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

आज उत्तर प्रदेश का युवा अपनी जड़ों, संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करते हुए आधुनिक तकनीक और वैश्विक सोच को भी आत्मसात कर रहा है। उसके पास अपने सपनों को साकार करने के लिए आत्मविश्वास भी है और अवसरों की नई दुनिया भी।

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में उत्तर प्रदेश की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगी और उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने की इस यात्रा का सबसे मजबूत आधार उसकी युवा शक्ति है।

यह समय उस युवा उत्तर प्रदेश का है, जो बदल रहा है, बढ़ रहा है, सीख रहा है, नवाचार कर रहा है और नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है।

"जाओ, शिक्षा प्राप्त करो और अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनो।"

- सावित्रीबाई फुले

सनातन संस्कार और युवा नेतृत्व

पूनम कुमारी
मीडिया शिक्षक

भारत विश्व का सबसे युवा देश है और उत्तर प्रदेश उसकी सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी राज्य की प्रगति उसके युवाओं की शिक्षा, संस्कार, कौशल, रोजगार और नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करती है। यदि युवाओं को पारदर्शी शासन, सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक और अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिले, तो वे राज्य और राष्ट्र के विकास के सबसे बड़े वाहक बन सकते हैं। यही कारण है कि सुशासन केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में सुशासन को विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ जोड़कर देखा गया है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसरों का विस्तार हुआ है।

सुशासन का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से है जो पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील, भ्रष्टाचार–मुक्त, न्यायपूर्ण और जनहितकारी हो। जब सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, प्रशासन समयबद्ध तरीके से कार्य करे, कानून का समान रूप से पालन हो तथा नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, तभी सुशासन की वास्तविक भावना साकार होती है। युवाओं के लिए सुशासन का अर्थ है ,उन्हें शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, उद्यमिता और आत्मविकास के समान अवसर उपलब्ध कराना।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में कानून–व्यवस्था को मजबूत करने, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और डिजिटल शासन को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है। बेहतर कानून–व्यवस्था के कारण निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास हुआ, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि हुई। विभिन्न निवेश सम्मेलनों के माध्यम से देश–विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने की पहल की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, ई–गवर्नेंस तथा नागरिक सेवाओं के सरलीकरण से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला है।

युवाओं के कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्वरोजगार योजनाओं और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आज का युवा केवल नौकरी करने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी भी बनना चाहता है। इसी सोच के अनुरूप नवाचार, स्टार्टअप और डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही आधारभूत संरचना जैसे एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, औद्योगिक गलियारे और बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है,

जिसका प्रत्यक्ष लाभ युवाओं को रोजगार और व्यवसाय के रूप में प्राप्त हो सकता है।

किसी भी समाज के विकास का आधार उसकी संस्कृति और नैतिक मूल्य होते हैं। भारत की सनातन संस्कृति ने सदैव 'वसुधैव कुटुम्बकम्, 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' और 'धर्मो रक्षति रक्षितः' जैसे आदर्शों का संदेश दिया है। सनातन परंपरा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि सत्य, करुणा, सेवा, अनुशासन, कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति जैसे जीवन मूल्यों का मार्गदर्शन भी करती है। यदि युवा आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ-साथ इन मूल्यों को भी अपनाते हैं, तो वे एक जिम्मेदार नागरिक और आदर्श नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं।

योगी आदित्यनाथ ने अनेक अवसरों पर भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण को युवाओं के चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ा है। उनके कार्यकाल में अयोध्या, काशी और प्रयागराज जैसे प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास, आधारभूत संरचना के विस्तार तथा पर्यटन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। इन पहल ने युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और परंपराओं से जुड़ने के साथ-साथ पर्यटन, आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी), परिवहन, स्थानीय उद्यमिता और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में लगभग 48 करोड़ (480 मिलियन) घरेलू पर्यटक आए, जो भारत में सर्वाधिक थे तथा देश के कुल घरेलू पर्यटक भ्रमण का लगभग 19-20 प्रतिशत हिस्सा था। पर्यटन गतिविधियों में इस वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली और विशेष रूप से युवाओं के लिए सेवा क्षेत्र, लघु उद्यमों तथा सांस्कृतिक उद्योगों में रोजगार की संभावनाएँ बढ़ीं। इस प्रकार, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन विकास की पहल केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं रही, बल्कि युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का माध्यम भी बनी।

आज का युवा डिजिटल युग का नागरिक है। इसलिए शिक्षा के साथ डिजिटल साक्षरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और अनुसंधान का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के प्रयास युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि युवा आधुनिक तकनीक का उपयोग राष्ट्रहित, सामाजिक विकास और नवाचार के लिए करें, तो वे भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे ले जा सकते हैं।

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान किसी भी सुशासन की महत्वपूर्ण पहचान है। सुरक्षित वातावरण में ही छात्राएँ शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, रोजगार कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, महिला सुरक्षा के लिए विशेष तंत्र विकसित करने तथा जनजागरूकता बढ़ाने जैसे प्रयासों का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। जब बेटियाँ सुरक्षित होंगी, तभी समाज वास्तविक अर्थों में विकसित और समृद्ध होगा।

सुशासन की सफलता केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं होती। इसमें युवाओं की भी समान भागीदारी आवश्यक है। युवाओं को संविधान का सम्मान करना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भाग लेना चाहिए, मतदान अवश्य करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण, डिजिटल सुरक्षा और सामाजिक सेवा जैसे कार्यों में आगे आना चाहिए। साथ ही उन्हें नशामुक्ति, भ्रष्टाचार, हिंसा और सामाजिक विभाजन जैसी बुराइयों से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान देना चाहिए। सनातन संस्कृति का मूल संदेश भी यही है कि व्यक्ति पहले स्वयं को श्रेष्ठ बनाए, तभी समाज और राष्ट्र का उत्थान संभव है।

उत्तर प्रदेश आज विकास, निवेश, आधारभूत संरचना, डिजिटल प्रशासन और सांस्कृतिक पहचान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। यदि युवा शिक्षा, कौशल,

अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सनातन मूल्यों के साथ आगे बढ़ें सरकार पारदर्शी और उत्तरदायी शासन प्रदान करती रहे, तो उत्तर प्रदेश केवल भारत का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं, बल्कि सबसे विकसित और आत्मनिर्भर राज्यों में भी अपनी पहचान बना सकता है।

सुशासन और सनातन संस्कृति एक–दूसरे के पूरक हैं। जहाँ सुशासन नागरिकों को अवसर, सुरक्षा और न्याय प्रदान करता है, वहीं सनातन संस्कृति उन्हें नैतिकता, सेवा, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों को साथ लेकर चलने का प्रयास दिखाई देता है। आने वाले समय में यदि युवा इन अवसरों का पूर्ण उपयोग करते हुए ज्ञान, चरित्र और कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश 'श्रेष्ठ शासन, श्रेष्ठ संस्कार और श्रेष्ठ विकास' का आदर्श स्थापित कर सकता है तथा विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

वर्तमान समय में 'युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति' का विचार उत्तर प्रदेश में नए आयाम प्राप्त कर रहा है। जब युवा अपने अधिकारों के साथ–साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं, सनातन संस्कृति के आदर्शों–सत्य, सेवा, त्याग, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं तथा सुशासन की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, तब एक समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन, सांस्कृतिक गौरव और युवा सशक्तिकरण को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। यदि सरकार, समाज और युवा इसी समन्वय के साथ कार्य करते रहें, तो उत्तर प्रदेश न केवल आर्थिक और औद्योगिक प्रगति का केंद्र बनेगा, बल्कि सनातन संस्कृति, सुशासन और राष्ट्र निर्माण का एक प्रेरणादायी मॉडल भी स्थापित करेगा। यही संकल्प 'विकसित उत्तर प्रदेश–विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

युवा सशक्तिकरण की विकास यात्रा

- युवाओं के लिए सुशासन का उद्देश्य शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और आत्मविकास के समान अवसर उपलब्ध कराना
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून–व्यवस्था, डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक पारदर्शिता पर विशेष बल
- बेहतर कानून–व्यवस्था से निवेश बढ़ा, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार की संभावनाएँ मजबूत हुई
- ई–गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएँ और डिजिटल प्रशासन ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया
- कौशल विकास, स्टार्टअप और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण
- एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक गलियारे और बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई
- सनातन संस्कृति सत्य, सेवा, अनुशासन, कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति जैसे जीवन मूल्यों की प्रेरणा देती है
- अयोध्या, काशी और प्रयागराज के विकास से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ पर्यटन और रोजगार के नए अवसर बढ़े
- वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में लगभग 48 करोड़ घरेलू पर्यटक आए, जो देश में सर्वाधिक थे; इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बल मिला
- डिजिटल साक्षरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), नवाचार और अनुसंधान भविष्य के युवाओं के लिए आवश्यक क्षेत्र हैं
- महिला सुरक्षा और सम्मान को सुशासन का महत्वपूर्ण आधार माना गया।

"हमें अपने युवाओं को विज्ञान और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना होगा।"
- डॉ. विक्रम साराभाई

कुटुंब का संस्कार युवा शक्ति का आधार

डॉ. विनीत उत्पल
सहायक प्राध्यापक, आईआईएमसी, जम्मू केंद्र

भारत की सभ्यता और संस्कृति परिवार–केंद्रित रही है। एक परिवार साथ रहने वाले व्यक्तियों की इकाई मात्र नहीं, बल्कि संस्कार, परंपरा, जिम्मेदारी, संवेदना और सामाजिक चेतना के निर्माण का पहला विद्यालय है। बदलते समय में शहरीकरण, तकनीकी विकास, सोशल मीडिया और वैश्वीकरण ने परिवार की संरचना और युवा पीढ़ी की जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन किया है। ऐसे समय में 'कुटुंब प्रबोधन' जैसे संस्कार ने उत्तर प्रदेश के परिवारों को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया है। आज उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों से लेकर शहरों तक युवा अपने परिवारों को जोड़कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की दशा और दिशा तय करने में सक्षम हो रहा है।

राज्य सरकार परिवारों को पहचान देने, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है। इसमें 'परिवार आईडी–एक परिवार एक पहचान' योजना प्रमुख है। राज्य के सभी परिवारों को एक विशिष्ट पहचान पत्र देने और डेटाबेस तैयार करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिससे पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीब परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को 30,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार वित्तीय सहायता और आयोजन का प्रबंध करती है।

कुटुंब प्रबोधन का अर्थ परिवार को बचाए रखने या संयुक्त परिवार की पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक अर्थ परिवार के सदस्यों के बीच संवाद, परस्पर सम्मान, जिम्मेदारी, संवेदना और भारतीय जीवन–मूल्यों को मजबूत करना है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं और व्यक्तिगत सफलता के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी आवश्यक होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आधुनिकता का अर्थ अपनी जड़ों से और जुड़ जाना होता है और यही कुटुंब प्रबोधन की मूल भावना है। यह कार्य उत्तर प्रदेश के युवा बखूबी कर रहे हैं और परिवार के साथ जीवन को एक नई दशा और दिशा दे रहे हैं।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो है ही, युवाओं की बड़ी आबादी भी इसी प्रदेश में रहती है। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर और नोएडा जैसे शहर शिक्षा, रोजगार, उद्योग और तकनीक के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं। गांवों से शहरों की ओर युवाओं का प्रवास बढ़ा है। डिजिटल माध्यमों ने दुनिया को युवाओं की मुट्ठी में ला दिया है।

इससे अवसरों का विस्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियां भी बढ़ी हैं।

उत्तर प्रदेश का युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, स्टार्टअप शुरू कर रहा है, डिजिटल कंटेंट बना रहा है और देश–विदेश में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश रहा है। वह तकनीक के माध्यम से नई दुनिया से जुड़ रहा है। यह परिवर्तन सकारात्मक है। साथ ही, अकेलापन, पारिवारिक संवाद में कमी, उपभोक्तावाद, तनाव, सोशल मीडिया की आभासी दुनिया और पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी जैसी समस्याएं भी दिखाई देती हैं। ऐसे में कुटुंब प्रबोधन युवाओं को आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करने का रास्ता दिखा रहा है।

युवा किसी भी समाज की ऊर्जा और भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वे अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हैं, तो वे केवल सफल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के युवा देश को एक नई राह दिखा रहे हैं। वे परिवार में संवाद की संस्कृति विकसित कर रहे हैं। माता–पिता और बच्चों के बीच पढ़ाई, नौकरी या करियर की चर्चा के साथ–साथ जीवन, समाज, संस्कृति, देश और भविष्य पर भी बातचीत कर रहे हैं। परिवार में भोजन के समय कुछ देर साथ बैठ रहे हैं, बुजुर्गों के अनुभव को सुन रहे हैं, त्योहारों और पारिवारिक परंपराओं में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ये प्रयास बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं।

उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना में परिवार की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहां गांवों और कस्बों में आज भी रिश्तेदारी और सामाजिक संबंधों का मजबूत तंत्र मौजूद है। परिवारों में दादा–दादी और नाना–नानी की उपस्थिति बच्चों को अनुभव और परंपरा से जोड़ती है। लोकगीत, लोककला, त्योहार, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन तथा स्थानीय परंपराएं युवा पीढ़ी को अपनी पहचान से जोड़ने का माध्यम बनती हैं। संस्कारों से ही सशक्त परिवार बनते हैं और ऐसे सशक्त परिवार मजबूत एवं संगठित समाज की नींव तैयार करते हैं। पारिवारिक जीवन में आपसी प्रेम, संवाद, विश्वास, सहयोग और अच्छे संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुदृढ़ पारिवारिक व्यवस्था, स्वस्थ जीवनशैली, अच्छे संस्कार और आपसी सहयोग समाज को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कुटुंब प्रबोधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष पीढ़ियों के बीच संवाद है। युवा पीढ़ी डिजिटल तकनीक के साथ बड़ी हुई है, जबकि माता–पिता और बुजुर्गों का अनुभव अलग सामाजिक परिस्थितियों में निर्मित हुआ है। दोनों के बीच विचारों का अंतर स्वाभाविक है और उत्तर प्रदेश के युवा इस सामंजस्य को बिठाने में सफल हो रहे हैं। युवा बुजुर्गों के अनुभव का सम्मान कर रहे हैं और बुजुर्ग भी युवाओं की आकांक्षाओं तथा बदलती दुनिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। संवाद दोनों दिशाओं में हो रहा है और परिवार मजबूत बन रहा है।

महिलाओं की भूमिका भी कुटुंब प्रबोधन में केंद्रीय है। परिवार में समानता, सम्मान और अवसर का वातावरण युवाओं के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। बेटियों को शिक्षा, निर्णय और करियर के समान अवसर देना तथा बेटों को घरेलू जिम्मेदारियों में सहभागी बनाना आवश्यक है, जिसे राज्य की सरकार बखूबी कर रही है। परिवार में लैंगिक समानता की भावना विकसित हो रही है और युवा पीढ़ी जिस परिवार को अपने जीवन में देखती है, उसी से वह समाज के प्रति अपने व्यवहार की सीख लेती है।

डिजिटल युग के कारण परिवार के सामने नई चुनौती भी है। एक ही कमरे में बैठे परिवार के सदस्य अलग–अलग स्क्रीन पर व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया ने संवाद को बढ़ाया है, लेकिन आमने–सामने की बातचीत को कम भी किया है। इसलिए डिजिटल अनुशासन आवश्यक है। परिवार में 'स्क्रीन टाइम' और 'फैमिली टाइम' के बीच संतुलन बनाया जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को डिजिटल माध्यमों का उपयोग ज्ञान, रचनात्मकता और सामाजिक जागरूकता के लिए करने के साथ–साथ फेक न्यूज, साइबर अपराध और डिजिटल लत से बचने के लिए जागरूक किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कुटुंब प्रबोधन का एक और

महत्वपूर्ण आयाम राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी है। परिवार से प्राप्त संस्कार व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में दिखाई देते हैं। परिवार में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, बुजुर्गों का सम्मान, जरूरतमंदों की सहायता, ईमानदारी और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जिम्मेदारी जैसे मूल्य व्यवहार में उतर रहे हैं। परिवार सामाजिक परिवर्तन का सबसे छोटा, लेकिन सबसे प्रभावशाली केंद्र बन रहा है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की भूमिका कुटुंब प्रबोधन में अहम हो चुकी है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में युवाओं में केवल रोजगारपरक कौशल ही नहीं, बल्कि जीवन–कौशल, नैतिकता, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और युवा संगठन परिवार, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी पर संवाद, कार्यशालाएं, सामुदायिक गतिविधियां और युवा नेतृत्व कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कुटुंब प्रबोधन का उद्देश्य युवाओं को अपनी जड़ों से शक्ति लेकर भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देना है। भारतीय परिवार की शक्ति उसके संबंधों की गुणवत्ता में है। आज संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार, मूल प्रश्न यह है कि उसमें प्रेम, विश्वास, संवाद और जिम्मेदारी कितनी है।

बहरहाल, उत्तर प्रदेश का युवा आज नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्टार्टअप से लेकर शोध, प्रशासन से लेकर पत्रकारिता, खेल से लेकर कला और तकनीक से लेकर उद्यमिता तक उसके सामने अनेक संभावनाएं हैं। उसकी आधुनिक प्रतिभा को परिवार से मिले संस्कार, सामाजिक संवेदना और राष्ट्रीय दृष्टि का साथ उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के संदर्भ में कुटुंब प्रबोधन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां का युवा विकसित भारत के साथ–साथ 2047 में परिवार, समाज और राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। मजबूत परिवार से संवेदनशील युवा और संवेदनशील युवा से मजबूत समाज का निर्माण होता है। यही कुटुंब प्रबोधन की सार्थकता है और यही उत्तर प्रदेश के युवा की सबसे बड़ी शक्ति भी है।

युवा और उत्तर प्रदेश

- उत्तर प्रदेश : देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य और बड़ी युवा आबादी का केंद्र।
- प्रमुख युवा केंद्र : प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर और नोएडा।
- परिवार आईडी : एक परिवार–एक पहचान के तहत परिवारों का डेटाबेस।
- कन्या सुमंगला : बेटियों के जन्म से उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ : कमाने वाले की मृत्यु पर आश्रित परिवार को ₹ 30,000 की सहायता।
- सामूहिक विवाह योजना : कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहयोग।
- कुटुंब प्रबोधन : संवाद, सम्मान, संस्कार और जिम्मेदारी को मजबूत करने की पहल।
- डिजिटल युग : युवाओं के लिए अवसरों के साथ फेक न्यूज, साइबर अपराध और डिजिटल लत जैसी चुनौतियां।
- युवा शक्ति : परिवार के संस्कार और सामाजिक संवेदना से जिम्मेदार नागरिक और मजबूत समाज का निर्माण।

उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। - स्वामी विवेकानंद

युवा शक्ति से समरस समाज की नई तस्वीर

डॉ.रामशंकर
एसोसिएट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
आईआईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट

उत्तर प्रदेश के युवा भारतीय संस्कृति के समरसता, सेवा और राष्ट्रनिर्माण के आदर्शों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, आपदा राहत तथा स्वच्छता अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स तथा विभिन्न युवा संगठनों के माध्यम से वे समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर कार्य कर रहे हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर से जुड़े सेवा कार्यों, प्रयागराज महाकुंभ में स्वयंसेवी सेवाओं तथा हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियानों में युवाओं की सहभागिता ने सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और समरसता की भावना को सशक्त किया है। यही युवा शक्ति विकसित और समरस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आधारशिला है।

भारत की सांस्कृतिक चेतना का मूल आधार समरसता, सह–अस्तित्व और लोककल्याण की भावना है। हमारे ऋषि–मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही यह उद्घोष किया था–'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः' अर्थात सभी सुखी हों और सभी निरोग रहें। इसी प्रकार 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का सिद्धांत सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की प्रेरणा देता है।

भारतीय संस्कृति में समाज का विकास तभी पूर्ण माना गया है, जब उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव, वैमनस्य अथवा असमानता न हो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान तथा समान अवसर प्राप्त हो। आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब समरस समाज के निर्माण की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश के युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य न केवल भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, बल्कि सबसे बड़ी युवा शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है।

भारतीय चिंतन में युवा केवल आयु का नहीं, बल्कि ऊर्जा, साहस, सेवा, त्याग और राष्ट्रनिर्माण का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं के चरित्र और संकल्प पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश के युवा शिक्षा, विज्ञान, कृषि, खेल, उद्यमिता, डिजिटल तकनीक, सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से समाज को नई दिशा दे रहे हैं। यदि यह युवा शक्ति भारतीय जीवन मूल्यों से प्रेरित होकर कार्य करे, तो सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता दोनों सुदृढ़ होंगी।

समरस समाज का अर्थ केवल सामाजिक समानता नहीं है, बल्कि ऐसा समाज है जहाँ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। भारतीय संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श इसी समरस समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में यह भावना केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहार रही है। भगवान श्रीराम ने वनवास के दौरान निषादराज गुह को गले लगाया, माता शबरी के प्रेम से अर्पित बेर स्वीकार किए तथा वानर–भालू समाज को अपने साथ लेकर धर्म की स्थापना की। इन प्रसंगों का संदेश स्पष्ट है कि भारतीय समाज का आधार जन्म नहीं, बल्कि मानवता, सदाचार और कर्तव्य है।

भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में लोकसंग्रह अर्थात सम्पूर्ण समाज के कल्याण के लिए कर्म करने का संदेश दिया। महात्मा गांधी ने सर्वोदय के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात कही। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सामाजिक समानता और संवैधानिक अधिकारों को लोकतंत्र की आत्मा बताया, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद ने व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को एक–दूसरे का पूरक माना। इन सभी विचारों का मूल उद्देश्य समरस समाज की स्थापना था।

उत्तर प्रदेश संतों और महापुरुषों की भूमि रही है। संत कबीर ने जाति–पाँति के भेदभाव का विरोध करते हुए कहा कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म और आचरण से होती है। संत रविदास ने ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ किसी प्रकार का ऊँच–नीच न हो। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लोकमंगल और सामाजिक समन्वय का संदेश दिया। इन संतों की शिक्षाएँ आज भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

आज उत्तर प्रदेश के युवा अनेक ऐसे कार्य कर रहे हैं जो समरस समाज की भावना को व्यवहार में उतारते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हजारों युवा गाँवों और शहरों में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, साक्षरता अभियान, पौधरोपण, स्वास्थ्य जागरूकता, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। इन अभियानों में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी होती है। सेवा के समय किसी की जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति नहीं देखी जाती, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान और सहयोग दिया जाता है। यही भारतीय समरसता का वास्तविक स्वरूप है।

कोविड–19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश के युवाओं ने मानवता और सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। अनेक स्वयंसेवी युवाओं ने अस्पतालों में रक्तदान किया, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए, गरीब परिवारों तक भोजन पहुँचाया, दवाइयों की व्यवस्था की तथा अकेले रह रहे बुजुर्गों की सहायता की। उस कठिन समय में सेवा करने वालों ने यह नहीं देखा कि सहायता पाने वाला व्यक्ति किस धर्म या जाति से है। उनके लिए प्रत्येक पीड़ित मानव सेवा का अधिकारी था। भारतीय संस्कृति के 'नर सेवा ही नारायण सेवा' का यह

जीवंत स्वरूप समाज में समरसता की भावना को और अधिक मजबूत करता है।

प्रयागराज महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन भी समरसता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहाँ हजारों युवा स्वयंसेवक स्वच्छता, चिकित्सा सहायता, यातायात व्यवस्था, जल वितरण, खोया–पाया केंद्र और श्रद्धालुओं की सहायता में दिन–रात सेवा करते हैं। इसी प्रकार अयोध्या में श्रीराम मंदिर से जुड़े सेवा कार्यों में भी अनेक युवाओं ने श्रमदान, स्वच्छता, जनसहयोग और श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन में योगदान दिया। इन कार्यों ने यह सिद्ध किया कि भारतीय संस्कृति में सेवा ही समाज को जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

डिजिटल युग में युवाओं की भूमिका और भी व्यापक हो गई है। सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सशक्त उपकरण भी है। उत्तर प्रदेश के अनेक युवा डिजिटल मंचों के माध्यम से रक्तदान अभियान चलाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराते हैं, गरीब विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं और आपदा के समय राहत कार्यों के लिए जनसहयोग जुटाते हैं। इसके साथ ही उनकी यह जिम्मेदारी भी है कि वे फर्जी समाचार, अफवाह और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री से बचें तथा सत्य, संयम और जिम्मेदार संवाद को बढ़ावा दें।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के युवा उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। अनेक युवा अपने गाँवों में पुस्तकालय स्थापित कर रहे हैं, डिजिटल शिक्षा केंद्र चला रहे हैं, महिला स्वयं सहायता समूहों को तकनीकी प्रशिक्षण दे रहे हैं, स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन बाजार से जोड़ रहे हैं तथा जैविक खेती और जल संरक्षण जैसे अभियानों को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे केवल आर्थिक विकास ही नहीं होता, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग, विश्वास और आत्मीयता भी बढ़ती है।

समरस समाज के निर्माण के लिए केवल सरकारी योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं। परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थाएँ, सामाजिक संगठन और मीडिया सभी को युवाओं के भीतर सेवा, संवेदना, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के संस्कार विकसित करने होंगे। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसा नागरिक तैयार करना होना चाहिए जो अपने अधिकारों के साथ–साथ अपने सामाजिक दायित्वों को भी समझे। जब युवा संविधान के मूल्यों और भारतीय संस्कृति के आदर्शों को व्यवहार में उतारेंगे, तभी समाज में स्थायी समरसता स्थापित होगी।

आज उत्तर प्रदेश विकसित भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। औद्योगिक विकास, स्टार्टअप, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर युवाओं को आगे बढ़ने का मंच प्रदान कर रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि युवा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान को भी अपना दायित्व समझें। सेवा, सद्भाव, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता को अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर ही वे भारतीय विचारधारा के वास्तविक प्रतिनिधि बन सकते हैं।

अंततः यह कहा जा सकता है कि समरस समाज का निर्माण भारतीय संस्कृति का शाश्वत आदर्श है और उत्तर प्रदेश के युवा इस आदर्श को साकार करने की सबसे बड़ी शक्ति हैं। जब युवा अपने जीवन में 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'सर्वे भवन्तु सुखिनः', 'नर सेवा ही नारायण सेवा' और 'लोकसंग्रह' जैसे भारतीय जीवन–मूल्यों को अपनाकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेंगे, तब समरस समाज का स्वप्न साकार होगा। उत्तर प्रदेश का युवा यदि सेवा को संस्कार, राष्ट्र को परिवार और मानवता को अपना धर्म मानकर आगे बढ़े, तो वह न केवल राज्य, बल्कि पूरे भारत को सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई दिशा प्रदान कर सकता है।

"हर व्यक्ति हृदय से अच्छा होता है। परिस्थितियों के कारण उसका व्यवहार अलग हो सकता है। किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे कोई समस्या हल नहीं होती।" **- रज्जू भैय्या**

पंच परिवर्तन : समावेशी समाज की ओर

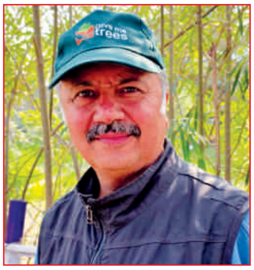

विनीत वोहरा
पर्यावरणविद् (give me tree foundation)

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी की सोच, ऊर्जा, चरित्र और कार्यशैली पर निर्भर करता है। युवा केवल देश की जनसंख्या का एक हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे समाज की सबसे सक्रिय, रचनात्मक और परिवर्तनकारी शक्ति होते हैं। उनकी आंखों में सपने होते हैं, मन में उत्साह होता है और कठिन परिस्थितियों को बदलने की क्षमता होती है। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के संदर्भ में युवाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तर प्रदेश का युवा यदि सही दिशा, अच्छे संस्कार, आधुनिक शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े, तो वह न केवल प्रदेश, बल्कि पूरे देश की प्रगति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

'पंच परिवर्तन' समाज के निर्माण से जुड़े पांच महत्वपूर्ण विषयों सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुम्ब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य तथा स्वदेशी एवं स्व-बोध पर आधारित है। ये पांचों विचार केवल सिद्धांत नहीं हैं। इन्हें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन, व्यवहार और सामाजिक गतिविधियों में सरलता से अपना सकता है। यदि उत्तर प्रदेश का युवा इन पांचों सूत्रों को आत्मसात कर ले, तो प्रदेश में व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और नैतिक परिवर्तन संभव है।

उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति : उत्तर प्रदेश विविधताओं से भरा हुआ राज्य है। यहां बड़े महानगरों के साथ-साथ छोटे कस्बे, गांव, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक नगर, ऐतिहासिक शहर और सांस्कृतिक केंद्र मौजूद हैं। प्रदेश के युवा भी अलग-अलग भाषाई, सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से आते हैं। कोई युवा खेत में नई तकनीक अपना रहा है, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई खेल में प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है और कोई स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है।

आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं रह गया है। वह उद्यमी, शोधकर्ता, कलाकार, किसान, खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ भी बन रहा है। वह डिजिटल माध्यमों से दुनिया से जुड़ा है और वैश्विक अवसरों को समझ रहा है। इसके बावजूद उसकी जड़ें गांव, परिवार, स्थानीय भाषा और संस्कृति में हैं।

सामाजिक समरसता : सामाजिक समरसता का अर्थ है जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, धर्म, आर्थिक स्थिति और अन्य भेदों

से ऊपर उठकर सभी लोगों को समान सम्मान देना। समाज तभी प्रगति कर सकता है, जब उसके सभी वर्ग एक–दूसरे के साथ सहयोग, संवेदना और भाईचारे से रहें।

उत्तर प्रदेश ने अनेक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को देखा है। यहां की सामाजिक संरचना अत्यंत विविध है। कई बार जातिगत भेदभाव, ऊंच–नीच की मानसिकता और सामाजिक दूरी ने समाज को कमजोर किया है। युवाओं को यह समझना होगा कि किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से नहीं होती। उसकी वास्तविक पहचान उसके चरित्र, ज्ञान, व्यवहार और कर्म से होती है। आज विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों में अलग–अलग पृष्ठभूमि के युवा साथ पढ़ते और काम करते हैं। यह सामाजिक समरसता को मजबूत करने का बड़ा अवसर है। युवा मित्रता, सहयोग और संवाद के माध्यम से पुरानी सामाजिक दूरियों को कम कर सकते हैं। खेलकूद प्रतियोगिताएं, सामूहिक उत्सव, सहभोज, रक्तदान शिविर, शिक्षा अभियान और सामाजिक सेवा के कार्य लोगों को एक–दूसरे के करीब लाते हैं।

सोशल मीडिया का उपयोग भी सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। युवाओं को ऐसी सामग्री साझा करनी चाहिए, जो समाज को जोड़ती हो। अफवाहों, घृणा और भेदभाव फैलाने वाले संदेशों से बचना चाहिए। किसी भी संदेश को आगे भेजने से पहले उसकी सत्यता जांचना एक जिम्मेदार युवा की पहचान है। सामाजिक समरसता का अर्थ केवल भेदभाव दूर करना ही नहीं है बल्कि इसका अर्थ समाज के कमजोर, गरीब और वंचित लोगों को आगे बढ़ने में सहायता देना भी है। युवा गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण तथा संवेदनशील आवाज उठा सकते हैं। इस प्रकार युवा समाज को केवल समानता का संदेश नहीं देते, बल्कि उसे व्यवहार में भी उतारते हैं।

पर्यावरण संरक्षण : पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, उपजाऊ भूमि, पेड़–पौधे और जैव विविधता के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। आधुनिक विकास ने सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। उत्तर प्रदेश नदियों, कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, घाघरा और राप्ती जैसी नदियां प्रदेश के जीवन और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन नदियों की स्वच्छता और संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की है।

युवा पर्यावरण संरक्षण में नेतृत्व कर सकते हैं। वे अपने मोहल्लों, गांवों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं। लेकिन केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है। पौधों की नियमित देखभाल करना, उन्हें पानी देना और उनके बड़े होने तक उनकी रक्षा करना भी जरूरी है। जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में पानी की समस्या लंबे समय से रही है। युवा वर्षा जल संचयन, तालाबों की सफाई, पुराने कुओं के संरक्षण और जल के उचित उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। घरों में नल खुला न छोड़ना, वाहन धोने में कम पानी का उपयोग करना और वर्षा का पानी एकत्र करना छोटी, लेकिन प्रभावशाली आदतें हैं।

प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग भी पर्यावरण के लिए

गंभीर खतरा है। युवा कपड़े या जूट के थैले अपना सकते हैं, एकल–उपयोग प्लास्टिक से बच सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। कचरे को सूखे और गीले भाग में अलग करना, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाना तथा बिजली की बचत करना पर्यावरण संरक्षण के सरल उपाय हैं।

कुटुम्ब प्रबोधन : भारतीय समाज में परिवार केवल साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं है। परिवार संस्कार, सुरक्षा, प्रेम, अनुशासन और सहयोग की पहली पाठशाला है। व्यक्ति बोलना, व्यवहार करना, बड़ों का सम्मान करना और दूसरों की चिंता करना सबसे पहले परिवार में सीखता है। आधुनिक समय में परिवार अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नौकरी, पढ़ाई, व्यस्त जीवनशैली, सोशल मीडिया और मोबाइल के अत्यधिक उपयोग के कारण परिवार के सदस्यों के बीच संवाद कम हो रहा है। एक ही घर में रहने वाले लोग कई बार घंटों मोबाइल पर रहते हैं, लेकिन आपस में बात नहीं करते। इससे भावनात्मक दूरी बढ़ती है।

कुटुम्ब प्रबोधन का उद्देश्य परिवारों में संवाद, सहयोग और संस्कारों को मजबूत करना है। इसका अर्थ आधुनिक तकनीक का विरोध करना नहीं है, बल्कि उसका संतुलित उपयोग करना है। युवा सप्ताह में कुछ समय 'स्क्रीन–फ्री फैमिली टाइम' के रूप में निर्धारित कर सकते हैं। इस समय परिवार के सभी सदस्य मोबाइल से दूर रहकर साथ भोजन करें, एक–दूसरे की बातें सुनें और पारिवारिक विषयों पर चर्चा करें।

बुजुर्गों का सम्मान कुटुम्ब प्रबोधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके पास जीवन का अनुभव, लोक परंपराओं का ज्ञान और परिवार का इतिहास होता है। युवा दादा–दादी और माता–पिता के अनुभव सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके साथ ही परिवार के बुजुर्गों को आधुनिक तकनीक सिखाना भी युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति लोकगीतों, त्योहारों, कथाओं और पारिवारिक परंपराओं से समृद्ध है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेली क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। युवा इन परंपराओं को आधुनिक मंचों, वीडियो, पॉडकास्ट और लेखन के माध्यम से संरक्षित कर सकते हैं।

नागरिक कर्तव्य : लोकतंत्र में नागरिकों को अनेक अधिकार प्राप्त हैं, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। केवल सरकार और प्रशासन से अपेक्षा रखना पर्याप्त नहीं है। देश की व्यवस्था तभी मजबूत होगी, जब नागरिक स्वयं भी जिम्मेदारी निभाएंगे। नागरिक कर्तव्य का अर्थ है कानून का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, स्वच्छता बनाए रखना, मतदान करना और समाज के प्रति संवेदनशील रहना। उत्तर प्रदेश के युवा इस क्षेत्र में उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यातायात नियमों का पालन करना एक सामान्य, लेकिन महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य है। हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना, रेड लाइट का पालन करना, गलत दिशा में वाहन न चलाना और एम्बुलेंस को रास्ता देना जीवन की रक्षा करता है। नियमों को डर के कारण नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की भावना से मानना चाहिए।

सार्वजनिक संपत्ति देश की संपत्ति होती है। रेलवे स्टेशन, बस, सड़क, विद्यालय, पार्क और सरकारी कार्यालय सभी नागरिकों के कर के पैसे से बनाए जाते हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाना अपने ही संसाधनों को नष्ट करना है। युवा सार्वजनिक स्थानों की साफ–सफाई और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। मतदान भी महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य है। युवाओं को जाति, धर्म, प्रलोभन या अफवाह के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी और कार्यक्षमता के आधार पर मतदान करना चाहिए। उन्हें दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए।

स्वदेशी एवं स्व-बोध : स्वदेशी का अर्थ अपने देश में बने

पंच परिवर्तन में युवा योगदान

समरसता–सेवा, रक्तदान और शिक्षा अभियानों से सामाजिक एकता।

पर्यावरण–पौधरोपण, नदी–सफाई और जल संरक्षण में सक्रिय भागीदारी।

कुटुम्ब प्रबोधन –परिवार, बुजुर्गों और लोकपरंपराओं से नई पीढ़ी को जोड़ना

नागरिक कर्तव्य – स्वच्छता, मतदान और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जागरूकता।

स्वदेशी–स्व का बोध– स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को डिजिटल बाजार से जोड़ना।

उत्पादों, स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को प्राथमिकता देना है। स्व–बोध का अर्थ अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और पहचान को समझना है। अपनी जड़ों से जुड़ा व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी होता है और दुनिया के साथ बेहतर संवाद कर सकता है। उत्तर प्रदेश स्थानीय कला और उत्पादों का विशाल केंद्र है। बनारस की साड़ियां, भदोही के कालीन, कन्नौज का इत्र, लखनऊ की चिकनकारी, अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद का पीतल और फिरोजाबाद की चूड़ियां विश्व प्रसिद्ध हैं। ये केवल उत्पाद नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका और पीढ़ियों की कला हैं।

युवा तकनीक के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को नया बाजार दे सकते हैं। ई–कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और आकर्षक पैकेजिंग की सहायता से छोटे कारीगरों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों से जोड़ा जा सकता है। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और पलायन कम होगा।

'एक जिला एक उत्पाद' जैसी योजनाएं युवाओं को स्थानीय विशेषताओं को समझने और उनके आधार पर व्यवसाय विकसित करने का अवसर देती हैं। युवा खेती, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, हस्तशिल्प और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में उद्यम शुरू कर सकते हैं। स्व–बोध का अर्थ अपनी भाषा पर गर्व करना भी है। हिंदी के साथ–साथ अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेली जैसी भाषाएं प्रदेश की सांस्कृतिक संपदा हैं। अंग्रेजी या अन्य भाषाएं सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मातृभाषा से दूरी बनाना प्रगति नहीं है। वास्तविक आधुनिकता वही है, जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान बनाए रखते हुए वैश्विक ज्ञान को अपनाए।

पंच परिवर्तन को प्रभावी बनाने के उपाय : पंच परिवर्तन को व्यापक बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों, परिवारों, सामाजिक संगठनों और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्यावरण, सामाजिक सेवा और नागरिक जिम्मेदारी से जुड़े व्यावहारिक कार्यक्रम होने चाहिए। युवा मंडल, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय संस्थाएं स्वच्छता अभियान, रक्तदान, वृक्षारोपण, डिजिटल साक्षरता और अध्ययन केंद्र चला सकती हैं। अच्छा काम करने वाले युवाओं को पहचान और मंच मिलना चाहिए।

सोशल मीडिया पर सकारात्मक सामग्री का निर्माण भी जरूरी है। युवा छोटे वीडियो, पॉडकास्ट, लेख और कहानियों के माध्यम से पंच परिवर्तन के संदेश को रोचक और सरल भाषा में लोगों तक पहुंचा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश का युवा आज केवल इतिहास पढ़ने वाला युवा नहीं है, बल्कि इतिहास रचने की क्षमता रखने वाला युवा है। उसके पास ऊर्जा, प्रतिभा, तकनीक और अवसर हैं। आवश्यकता केवल सही दिशा और मजबूत मूल्यों की है। सामाजिक समरसता उसे समाज को जोड़ना सिखाती है। पर्यावरण संरक्षण उसे प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाता है। कुटुम्ब प्रबोधन उसे परिवार और संस्कारों से जोड़ता है। नागरिक कर्तव्य उसे अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। स्वदेशी एवं स्व–बोध उसे आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास प्रदान करते हैं।

जब उत्तर प्रदेश का युवा इन पांचों सूत्रों को अपने जीवन में उतारेगा, तब परिवर्तन केवल भाषणों और लेखों तक सीमित नहीं रहेगा। वह घर, मोहल्ले, गांव, विद्यालय और कार्यस्थल पर दिखाई देगा। एक जिम्मेदार युवा एक परिवार को प्रभावित करेगा, एक परिवार पूरे समाज को और समाज पूरे प्रदेश को बदल सकता है।

"शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि मनुष्य का निर्माण करना है।"
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

नई शिक्षा नीति : शिक्षा का भारतीयकरण

डॉ. अनुज कुमार
सहायक प्राध्यापक (अतिथि) दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म
दिल्ली विश्वविद्यालय

ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा व विवेक का उपयोग करते हुए मनुष्य ने आदिमानव व पाषाण युग से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक तक का सफर तय किया है। इस सबके मूल में शिक्षा है। कोविड महामारी में जब मानव यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव आया। ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के सुसंयोग से सम्पूर्ण मानव समाज उससे भी आसानी से पार निकल आया। शुरूआती दौर में मानव को ज्ञान के नाम पर सिर्फ धार्मिक पुस्तकों का ही अध्ययन करवाया गया। उस समय से लेकर आज तक दुनिया की कुछ धार्मिक पुस्तकों में सवाल पूछने की मनाही थीं। बदलते समय और दौर के साथ लोगों की उत्कंठाएं सामने आयीं तो सवाल भी होने लगे। इसके लिए अलग विषय की जरूरत महसूस हुई जहां सवाल पूछा जा सके और बदलते समय के साथ इस पाठ्यक्रम में बदलाव भी किए जा सकें, जिससे लोगों में तार्किकता बची रहे।

दर्शनशास्त्र को सबसे पहला विषय माना गया जहां लोगों ने अपनी जिज्ञासा को तर्क के माध्यम से शांत किया। मनुष्य की इन्हीं जिज्ञासाओं और कुछ अलग कर जाने की चाह ने दुनिया में तमाम विषय, पाठ्यक्रम तथा स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आज हम आप अपने आस-पास देखें हम जिन उपकरणों और तकनीकी से घिरे हुए हैं, यह सब शोध और अनवरत साधना के कारण सम्भव हो पाया है। मानव जीवन के इस प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को अब शोध के नाम से जाना जाता है। इस जानने की प्रवृत्ति के निवारण के लिए तमाम प्रकार के शोध की डिग्रियां और तमाम तरह के शोध संस्थान, शोध फंड आदि दिया जाता है।

जिस देश व समुदाय में धार्मिक पुस्तकों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, आप देख सकते हैं कि उन देशों की आर्थिक व सामाजिक दशा किस प्रकार की है। समय के बदलाव के साथ शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जाता है। शिक्षा महज औपचारिकता नहीं बल्कि यह सबसे प्रभावी बल है। जिन देशों का दुनिया में तकनीकी और आर्थिक स्तर पर दबदबा है आप देखिए वे राष्ट्र नावाचार को कितना महत्व देते हैं। कई क्षेत्रों में भारत का वर्चस्व है, उदाहरणार्थ चिकित्सा, सॉफ्टवेयर आदि। किसी भी क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए नावाचार पर बल देना होगा, शोध की ओर शोधार्थियों का रूझान बढ़ाना होगा। इसके लिए समय-समय पर शिक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव करने होंगे, जिसे हम शिक्षा नीति कहते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विकास यात्रा : 1968, 1986, 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन किए गए हैं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। किसी देश का वर्तमान और भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। भारत में लंबे समय तक चली शिक्षा प्रणाली पर यह आरोप लगता रहा कि वह औपनिवेशिक सोच से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकी। उसमें भारतीय संस्कृति, भाषाओं, परंपराओं और व्यावहारिक कौशल को अपेक्षित स्थान नहीं मिला। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) लागू की गई, जिसे स्वतंत्र भारत की सबसे व्यापक और दूरदर्शी शिक्षा नीति माना जाता है। डॉ. के. कस्तूरींगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार इस नीति का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम बदलना नहीं, बल्कि शिक्षा को भारतीय जीवन-दर्शन, आधुनिक विज्ञान और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप

समावेशी शिक्षण की ओर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, संसाधनों के बेहतर उपयोग और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत राज्य में अब तक लगभग 10,000 परिषदीय विद्यालयों की पेयरिंग (Pairing) की जा चुकी है। पेयरिंग का आशय ऐसे विद्यालयों को एक–दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया से है, जहाँ छात्र संख्या अपेक्षाकृत कम है और एक किलोमीटर के दायरे में कोई अन्य विद्यालय उपलब्ध है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उपलब्ध शिक्षकों, शैक्षणिक संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना तथा छात्र–शिक्षक अनुपात को संतुलित बनाना है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 1,32,886 परिषदीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन विद्यालयों को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनका प्रशासनिक पुनर्संयोजन किया जा रहा है। जहाँ पेयरिंग के कारण विद्यार्थियों, विशेषकर छोटे बच्चों, को विद्यालय तक पहुँचने में दूरी, परिवहन या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ संबंधित विद्यालयों की समीक्षा कर उन्हें पुनः अनपेयर (Unpair) करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। यह दर्शाता है कि सरकार केवल संसाधनों के अनुकूलन पर ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की सुविधा और शिक्षा के अधिकार को भी समान रूप से महत्व दे रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और समान शिक्षा पहुँचाना है। विद्यालयों की पेयरिंग जैसी पहल को इसी व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखा जा सकता है, जहाँ सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित शिक्षक, बेहतर वातावरण, पुस्तकालय, खेलकूद और अन्य शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि स्थानीय परिस्थितियों, ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक चुनौतियों और विद्यार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका क्रियान्वयन किया जाए। यदि पेयरिंग और अनपेयरिंग की प्रक्रिया संतुलित एवं संवेदनशील दृष्टिकोण से लागू की जाती है, तो यह उत्तर प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकती है।

पुनर्गठित करना है। यह नीति भारत को ज्ञान– आधारित, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय दृष्टि से शिक्षा का पुनर्स्थापन : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाँच मूलभूत सिद्धांतों – पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही पर आधारित है। इसका लक्ष्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है जो प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचान सके और उसे अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करे।यह नीति केवल डिग्री प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय चेतना और कौशल विकास का समन्वित प्रयास है। इसमें शिक्षा को रोजगार तक सीमित न रखकर जीवनोपयोगी बनाया गया है।

समग्र विकास पर विशेष बल : नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर आलोचनात्मक चिंतन, तार्किक विश्लेषण, संवाद, रचनात्मकता और समस्या समाधान जैसी क्षमताओं के विकास पर बल देती है। शिक्षा का उद्देश्य अब केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने योग्य नागरिक तैयार करना है। इसी सोच के अनुरूप विद्यालयी शिक्षा की पारंपरिक 10+2+3 संरचना को बदलकर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया है। इससे तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों को भी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा गया है, जो बाल विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

भारतीय भाषाओं और संस्कृति को सम्मान : राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय भाषाओं को उचित स्थान देना है। नीति में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा की गई है।

अनेक शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अधिक सहजता से सीखते हैं। इसके साथ ही संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया गया है। यह केवल भाषा का प्रश्न नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा, साहित्य, दर्शन और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का माध्यम भी है।

कौशल आधारित शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम : नई शिक्षा नीति शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम करने का प्रयास करती है। छठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा (दस दिन बस्ता रहित कक्षा) की व्यवस्था इसका प्रमाण है। इससे विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक शिक्षा के बीच मौजूद कृत्रिम विभाजन को समाप्त कर विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। यह व्यवस्था शिक्षा को अधिक लचीला और बहुविषयक बनाती है।

उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनेक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत करती है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बहुविषयक तथा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसी व्यवस्थाएँ विद्यार्थियों को अधिक अवसर प्रदान करती हैं।

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न संस्थानों से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट सुरक्षित रख सकेंगे और आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग कर सकेंगे। इससे शिक्षा अधिक लचीली और विद्यार्थी-केंद्रित बनेगी।

तकनीक और डिजिटल शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधुनिक तकनीक के महत्व को स्वीकार करती है। इसी उद्देश्य से नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) तथा नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर (NDEAR) जैसी पहलें शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य डिजिटल माध्यमों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देश के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचाना है।

आधारभूत साक्षरता पर विशेष ध्यान : नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने, लिखने और गणना करने में दक्ष बनाना है। इसी उद्देश्य से निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है ताकि प्राथमिक कक्षाओं में ही आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक क्षमता सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG-4) के अनुरूप वर्ष 2030 तक सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को 50 प्रतिशत तक पहुँचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल शिक्षा सुधार का दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत को ज्ञान, संस्कृति, नवाचार और आत्मनिर्भरता के आधार पर विकसित राष्ट्र बनाने का एक व्यापक दृष्टिपत्र है। यह नीति भारतीयता और आधुनिकता के संतुलित समन्वय का प्रयास करती है।

कौशल विकास

हर हाथ कौशल और प्रत्येक युवा को रोजगार : इस ध्येय वाक्य के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास पर बल दिया गया है। यह कार्य जमीनी स्तर पर शुरू किया गया है। इसके माध्यम से आईटीआई, पॉलिटेक्निक, जन शिक्षण संस्थान तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से युवाओं में कौशल का विकास कर उन्हें रोजगार उन्मुख बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से कक्षा 6 वोकेशनल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के द्वारा 250 से अधिक ट्रेड में युवाओं के रोजगार के अवसर खुलेंगे। जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से अशिक्षित तथा कम पढ़े-लिखे लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

"जो राष्ट्र अपने युवाओं में निवेश करता है, वही अपना भविष्य बनाता है।"

- जमशेदजी टाटा

युवा चेतना से समर्थ भारत का निर्माण

प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी
विभागाध्यक्ष, जनसंचार विभाग माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

भारत इस अर्थ में गौरवशाली है कि यह एक युवा देश है। युवाओं की संख्या के हिसाब से भी, अपने सामर्थ्य और चैतन्य के आधार पर भी भारत पूरी दुनिया में एक विशिष्ट स्थान रखता है। भारत एक ऐसा अनूठा देश है, जिसके सारे नायक युवा हैं। हमारे गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र श्रीराम, श्रीकृष्ण, जगदगुरू शंकराचार्य और आधुनिक युग के नायक स्वामी विवेकानंद तक सभी युवा नायक रहे हैं। युवा कोई केवल शारीरिक आयु नहीं है, युवा वास्तव में एक विराट चेतना है, जिसमें अपार ऊर्जा बसती है, गहरा भरोसा बसता है, अडिग विश्वास बसता है, सुंदर सपने पलते हैं और नई आकांक्षाएं लगातार धड़कती हैं। इसलिए युवा होना भारत को बेहद रास आता है।

भारत के सारे भगवान युवा हैं। वे कभी बुजुर्ग नहीं होते, वे सदैव शाश्वत युवा रहते हैं। यही युवा चेतना और ऊर्जा भारत की जींवतता का मुख्य आधार है। आज जबकि दुनिया के तमाम देशों में युवा शक्ति का भारी अभाव दिखता है, भारत का चेहरा उनमें बिल्कुल अलग और ओजस्वी दिखाई देता है। छात्र होना यदि निरंतर सीखना और ज्ञान अर्जित करना है, तो युवा होना अपने कर्म को पूजा मानकर पूरी लगन से राष्ट्र निर्माण में जुट जाना है। एक सीख है, तो दूसरा प्रचंड कर्म है। सीखी गई हर चीज को हमारे युवा ही परिणाम देते हैं और उसे धरातल पर साकार करते हैं। ऐसे में भारत की इस विराट छात्र शक्ति को सीखने के बेहतर और पारदर्शी अवसर देना,उनकी अंतर्निहित प्रतिभा के उन्नयन के लिए नए अनंत आकाश उपलब्ध कराना, हमारे समाज और चुनी हुई सरकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि हमारे छात्र को छात्र जीवन में ठीक से गढ़ा नहीं जाएगा, तो वह आगे चलकर एक आदर्श और जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेगा?

देश के प्रति अपनी मौलिक जिम्मेदारियों का निर्वहन वह किस प्रकार करेगा? भारत के शिक्षा परिसर ही नए भारत के निर्माण की असली आधारशिला हैं, अतः उनका वैचारिक रूप से जींवत होना और निरंतर सक्रिय रहना बेहद जरूरी है। अराजनैतिक छात्र शक्ति का निर्माण आज हमारे समाज की एक बड़ी विडंबना बन चुकी है। देश में पूरी तरह से एक ऐसा कृत्रिम वातावरण बनाया जा रहा है जिसमें छात्र सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने व्यक्तिगत करियर और पैकेज के बारे में सोचें। उसमें सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्र के प्रति गहरे सद्भाव और संवेदनशीलता कैसे पैदा हो, इस ओर गंभीर प्रयास आज बहुत जरूरी है। यह अत्यंत आवश्यक है कि वे अपने देश के बारे में गहराई से जानें, उसकी विविधताओं और बहुलताओं का सम्मान करें, ऐसे प्रबुद्ध नागरिक बनें जो विश्वमंच पर भारत की मान-प्रतिष्ठा को बढ़ा सकें। अतीत में तमाम सामाजिक

यूपी की युवा शक्ति आंकड़ों में

5.52 करोड़ : 15-29 वर्ष के युवा

39 प्रतिशत युवा कार्यरत आबादी का अनुपात

45.39 लाख+ रोजगार संगम के तहत

7.28 लाख + लोगों को रोजगार दिया गया

22,318 - स्टार्टअप इंडिया

3,614 - उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप

76 - इन्क्यूबेटर्स Incubators

7 - सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

₹1,000 करोड़ - स्टॉर्ट निधि कोष

नोट-15-29 वर्ष के युवाओं का आंकड़ा 2011 Census पर आधारित है

संगठनों से जुड़कर हमारी छात्र–युवा शक्ति अनेक प्रकार के सामाजिक और रचनात्मक प्रकल्पों को चलाती भी रही है। किंतु दुर्भाग्यवश, हमारी वर्तमान औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कोई जीवंत व्यवस्था पूरी तरह नदारद दिखाई देती है। आज ऐसा महसूस होता है कि वर्तमान शिक्षा से हमारे युवा जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, उससे वे संवेदनशील मनुष्य कम और संवेदनहीन मशीन ज्यादा बन रहे हैं। वे कॉरपोरेट जगत के लिए काम के लोग तो बनते हैं, किंतु नागरिक और राष्ट्रीय चेतना से लैस संपूर्ण मनुष्य नहीं बन पाते हैं।

छात्रों और युवाओं में राष्ट्रीय चेतना किसी भी सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा और प्रखर होती है। इसलिए यदि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में ही राष्ट्रीय भाव और सामाजिक मूल्य समाहित होते, तो आज देश के हालात बिल्कुल अलग और बेहतर होते। हालात यह है कि जो छात्र और युवा व्यक्तिगत रूप से सामाजिक–सांस्कृतिक संगठनों से नहीं जुड़े हैं, उनकी राष्ट्रीय विषयों पर कोई स्पष्ट सोच या राय नहीं बन पाती है। उन्हें इस दिशा में सोचने और खुलकर काम करने का अवसर ही नहीं मिलता। इस प्रकार हमने अनजाने में या किसी सुनियोजित व्यवस्था के तहत छात्र–युवाओं को पूरी तरह अराजनैतिक और नितांत व्यक्तिगत सोच वाला बना दिया है। आज का मुख्यधारा का छात्र–युवा केवल तात्कालिक आनंद और बाहरी उत्सवों में मस्त है। वह लेट–नाइट पार्टियों, सोशल मीडिया के आभासी संसार और मस्त माहौल को ही अपना सर्वस्व समझ रहा है। ऐसी गंभीर स्थितियों में यह बेहद जरूरी है कि छात्रों का स्वस्थ राजनीतिकरण हो, उन्हें एक मजबूत वैचारिक आधार से लैस किया जाए। देश के बुनियादी प्रश्नों पर वे खुलकर परिसरों में संवाद करें। आज देश के तमाम बड़े शिक्षा परिसरों में छात्रसंघ चुनाव भी नहीं कराए जाते। आखिर एक लोकतांत्रिक देश में छात्रों के राजनीतिकरण और उनकी वैचारिक प्रखरता से किसे डर लगता है? सच तो यह है कि सत्ताएं हमेशा चाहती हैं कि युवा मस्त–मस्त जीवन जीते रहें, समाज में खड़े बुनियादी सवालों से कभी न टकराएं। वे पार्टियों में झूमते रहें और फौरी मनोरंजन ही उनके जीवन का आधार बना रहे।

मनोरंजन और सिर्फ अपने कॅरियर से आगे सोचने वाली युवा शक्ति का अभाव आज हमारे समय की सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे शिक्षा परिसरों को ज्यादा जीवंत, उत्तरदायी और प्रासंगिक बनाया जाए। हमारे परिसरों को सांस्कृतिक, राजनीतिक और

सामाजिक प्रश्नों पर विमर्श और प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र बनाया जाए। अगर हमारे परिसर जीवंत होंगे तो उनसे निकलने वाला नया समाज भी उतना ही जीवंत और जागरूक बनेगा। भारतीय परंपरा में संवाद और विवाद की अनंत धाराएं रही हैं। यह समाज मूलतः एक संवादित समाज है। जिन दिनों संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, तो भी हमारा समाज उतना ही संवादित और वैचारिक रूप से सक्रिय था। कुंभ के विशाल आयोजनों से लेकर अनेक मेलों में समाज आपस में संवाद करता था और महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन करता था। नए समय ने समाज के इस आपसी संवाद के अनेक मार्ग बंद कर दिए हैं। सामयिक प्रश्नों पर संवाद बेहद कम होने के कारण नई पीढ़ी को देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियों से रू–ब–रू होने का अवसर ही नहीं मिलता। इसलिए देश के युवा आज अपने समय की वास्तविक चुनौतियों को नहीं पहचान पा रहे हैं।

युवाओं को एक ऐसा रोबोटिक युवा बनाया जा रहा है जो करियर और मनोरंजन से आगे कभी न सोच सके। इस प्रकार सामाजिक सोच का स्वाभाविक विकास पूरी तरह बाधित हो रहा है। ऐसे में देश के छात्र संगठनों को अपनी बड़ी जिम्मेदारी

निभानी होगी। छात्र संगठनों की यह जिम्मेदारी है कि वे राजनीतिक दलों के पिछलग्गू बनने के बजाय अपने संकुचित दायरे से बाहर आएं। आज जहां व्यावसायिकता के कारण शिक्षा और शिक्षक छात्रों का साथ छोड़ रहे हैं, छात्र संगठनों को वहीं पर छात्रों का साथ पकड़ना होगा। छात्र संघों को छात्रों की सर्वांगीण प्रतिभा के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करना होगा। छात्र संघ अपनी भूमिका का विस्तार करते हुए सिर्फ छात्र समस्याओं और संकीर्ण राजनीतिक कामों के बजाय देश के बड़े सवालों पर सोचने और उन पर निरंतर विमर्श का कार्य भी कर सकते हैं। छात्र शक्ति की सक्रिय और जागरूक भागीदारी से देश में आमूल–चूल परिवर्तन आ सकता है। एक बार राष्ट्र कल्याण का मिशन और ध्येय पैदा होते ही छात्र एक ऐसी अपराजेय युवा शक्ति में परिवर्तित हो जाता है, जिससे देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। आज देश के सभी क्षेत्रों में रचनात्मक जन–आंदोलन कमजोर हुए हैं। इन आंदोलनों के कमजोर होने के कारण विविध क्षेत्रों की वास्तविक और शोषित आवाजें नीति–निर्धारकों तक सुनाई देनी बंद हो गई हैं। इसके चलते सत्ताओं का अतिरेक और आत्मविश्वास अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है। जनसंगठन और छात्र संगठन एक सामाजिक दंड शक्ति के रूप में काम करें,इसके लिए उन्हें पूरी सजगता के साथ सचेतन प्रयास करने होंगे। इससे सत्ता और प्रशासन को भी सामाजिक शक्ति और जनभावना का विचार करना पड़ता है।

लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी ही उसे सफल और सार्थक बनाती है। अगर नागरिक जागरूक नहीं होते हैं, तो उनको उसके भयंकर परिणाम भोगने पड़ते हैं। एक सोया हुआ समाज कभी भी न्याय प्राप्ति की उम्मीद नहीं कर सकता। एक जागृत समाज ही अपने हितों की रक्षा करता हुआ अपने राष्ट्र की चौमुखी प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देता है। अगर छात्रों में छात्र जीवन से ही ये राष्ट्रीय मूल्य स्थापित कर दिए जाएं तो वे आगे चलकर देश के एक सक्रिय और ईमानदार नागरिक बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें अपनी जड़ों से गहरा प्रेम होगा, अपनी संस्कृति से प्रेम होगा, अपने समाज और उसके लोगों से सच्चा प्यार होगा। वह कभी किसी से नफरत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में राष्ट्रीय भावना का प्रवेश हो चुका होगा। वह राष्ट्र को सदैव सर्वोपरि मानेगा और राष्ट्र के सभी नागरिकों को अपना भाई–बंधु समझेगा। वह जानेगा कि उसके द्वारा किए गए हर कार्य का क्या सामाजिक परिणाम है। उसे बखूबी पता होगा कि देश के समक्ष उपस्थित विभिन्न चुनौतियों का सामना उसे किस तरह करना है। देश के छात्र संगठन अपनी–अपनी विचारधाराओं और राजनीतिक धाराओं को मजबूत करते हुए भी यह पावन भाव अपने संपर्क में आने वाले हर युवा में भर सकते हैं। सही मायने में यही जागरूक युवा आगे चलकर एक समर्थ, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगें।

भारत के युवाओं को अपने देश की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। - भगिनी निवेदिता

विद्या भारती विद्यालय

सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

सेक्टर क्यू, अलीगंज, लखनऊ (सीबीएसई, नई दिल्ली से संबद्ध)

प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक

विषय वर्ग

विज्ञान , वाणिज्य

कंप्यूटर साइंस , आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं शारीरिक योग शिक्षा के साथ

हम केवल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ही प्रतिबद्ध नहीं हैं, बल्कि विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

आधुनिक सुविधाएँ

- विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भौतिक विज्ञान , रसायन विज्ञान , जीव विज्ञान , गणित , कम्प्यूटर साइंस , कम्प्यूटेशनल मिडिया और रोबोटिक्स की प्रयोगशाला"
- विभिन्न कार्यक्रमों एवं समारोहों के लिए उयघुक दी बहुउद्देशीय सभागार।
- सरस्वती विद्या मंदिर में अनुभवी शिक्षकों की एक टीम है, जो प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिता ध्यान एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिससे वे अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सकें।

प्रमुख विशेषताएँ

वातानुकूलित कक्षाएँ, सभागार, खेल-आधारित शिक्षण, सीबीटवा निगरानी, ऑडियो-विजुअल शिक्षण, इनडोर एवं आउटडोर खेल, बस्तायुक एवं संवादात्मक शिक्षा।

svmlko@rediffmail.com
www.svmlkoaliganj.org
0522-3117520, 6307257740

प्रशिक्षण एवं परामर्श

- हमारे विद्यालय ने एलजीएफआई (स्कूल गैम्स फ़ेडरेशन ऑफ इंडिया) में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो हमारे विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को प्रदर्शित करता है।
- हमारे विद्यालय में बॉकी, बेडमिंटन एवं ताइक्वांडो जैसे खेलों के लिए प्राप्त एवं सांयकालीन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- हमारे एक विद्यार्थी ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय की खेल उत्कृष्टता को और अधिक गौरवान्वित किया है।
- इस वर्ष हमारे 3 विद्यार्थियों ने आईआईटी एवं 6 विद्यार्थियों नीट जैसी प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त की है।
- हम प्रतिभोगी परीक्षाओं के लिए सेमिनार के माध्यम से परामर्श भी प्रदान करते हैं, जिससे विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

डॉ आर० के० गर्ग	श्री अभिनव भार्गव	श्री के ० आर ० कनोजिया	श्री संतोष कुमार सिंह
संरक्षक/अध्यक्ष	प्रबंधक	कोषाध्यक्ष	प्रधानाचार्य

AZZURRO SPACES

ARCHITECTURE ◆ INTERIOR ◆ TURNKEY

ELEVATE YOUR HOME

OUR SERVICES

CUSTOMIZED PLANNING PACKAGES

Consultancy only — 2D + 3D rendering

FULL-SERVICE EXECUTION

Planning + on-site material & team coordination

TURNKEY SOLUTIONS

Stress-free 'Ready-to-Live' completion

CONTACT US | +91 88007 30804

UP INTERNATIONAL TRADE SHOW
25TH-29TH SEPTEMBER, 2026
4TH EDITION
INDIA EXPO CENTRE & MART, GREATER NOIDA
एक जनपद एक उत्पाद
75 उत्पादों को वैश्विक पहचान
राज्य के कुल ₹2 लाख करोड़+ के निर्यात में लगभग 50% का योगदान
विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
UPGovtOfficial
CMOUttarpradesh
CMOfficeUP